LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT

OC

देश का मिज़ाज सर्वेक्षण

19 अगस्त, 2020 40 रुपए

इंडिया टुडे

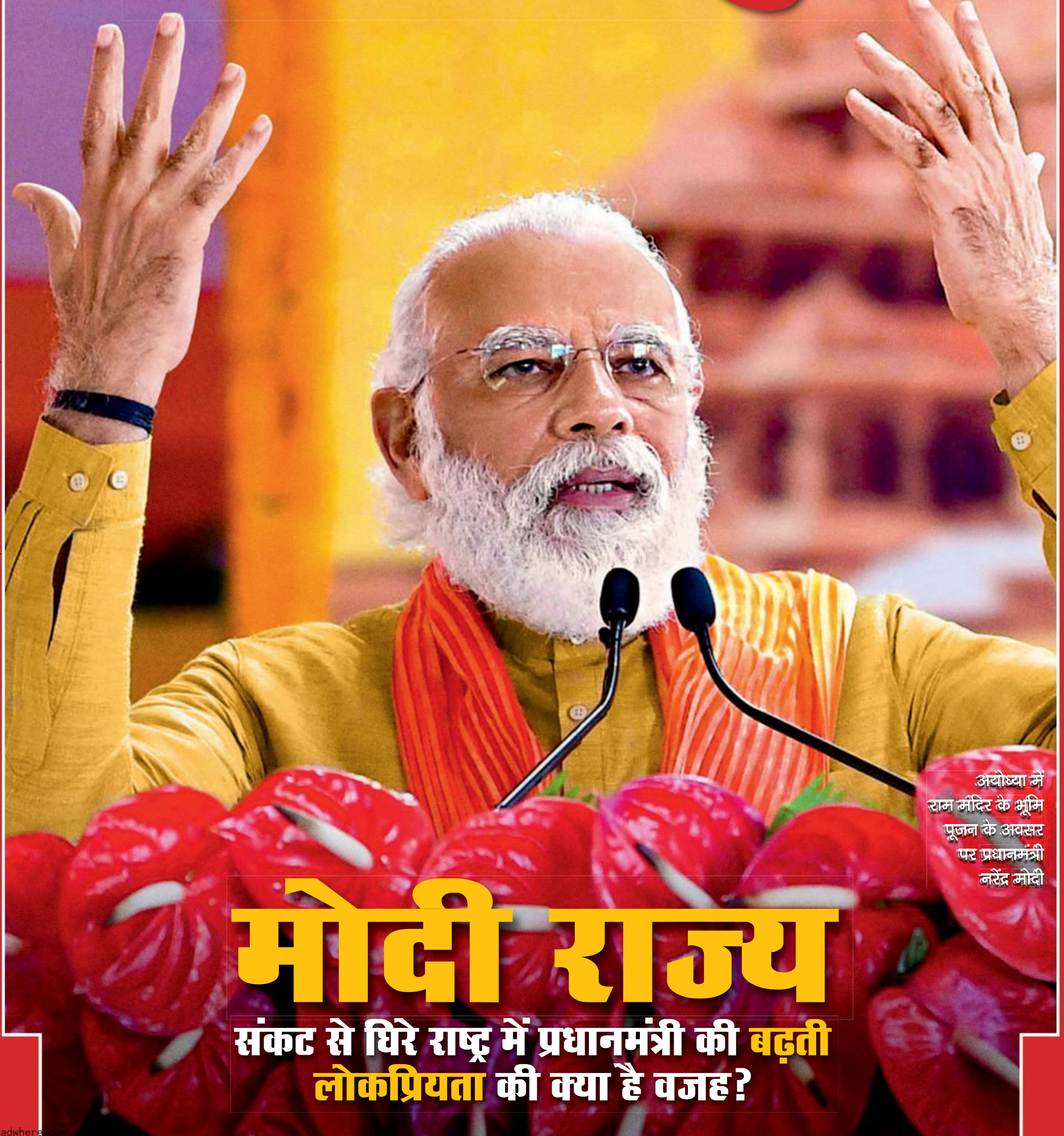

मोदी राज्य

संकट से घिरे राष्ट्र में प्रधानमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता की क्या है वजह?

अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

RNI NO. 45823/86 REGISTERED NO. FARIDABAD/46/2020-22; DL(ND)-11/6042/2018-20; U(C)-31/2018-20

www.indiatodayhindi.in

www.readwhere.com

VISIT…

GALGOTIAS UNIVERSITY

(Under the Uttar Pradesh Private Universities Act No. 12 of 2019)

AWARDED THE QS RANKING
FOR E-LEARNING EXCELLENCE
FOR ACADEMIC DIGITISATION

is proud to receive

NBA Tier 1 Accreditation

The Highest Benchmark of
ACADEMIC EXCELLENCE, PLACEMENTS
& RESEARCH
for its following programmes

Computer Science Engineering • Mechanical Engineering
Electronics & Communication Engineering

ADVANTAGES OF NBA ACCREDITED PROGRAMMES

- Most Organizations/Recruitment Agencies prefer to hire students from NBA Accredited programmes
- Students aspiring for PG courses abroad will be preferred as NBA is recognized under Washington Accord and Degrees are accepted at par with world's reputed Universities
- Students from NBA Accredited programmes are eligible for Scholarships under different schemes of Central/State Government

RANKED AMONGST TOP 200 UNIVERSITIES IN INDIA IN 2020
RANKED AMONGST TOP 100 PHARMACY COLLEGES IN 2020 IN INDIA BY nirf

RANKED AMONGST TOP 18 PRIVATE UNIVERSITIES IN INDIA BY TIMES ENGINEERING RANKING, 2020

Admissions open for 2020-21 in following disciplines

CAREER-FOCUSED UNDERGRADUATE / POST GRADUATE DEGREES IN

• Computer Science Engineering *(NBA Accredited)* • Computer Applications • Electrical Engineering • Electrical & Electronics Engineering • Electronics & Communication Engineering *(NBA Accredited)* • Mechanical Engineering *(NBA Accredited)* • Automobile Engineering • Civil Engineering • Biomedical Engineering • Business Administration • Finance & Commerce • Applied Psychology • English • Political Science • Sociology • Economics • Forensic Science • Physics • Chemistry • Mathematics • Biochemistry • Environmental Science • Microbiology • Biological Science • Zoology • Botany • Biochemistry • Architecture • Law • Pharmacy • Physiotherapy • Medical Lab Technology • Optometry • Cardiovascular Technology • Nursing • Hotel Management • Travel & Tourism • Journalism & Mass Communication • Fashion Design • Education • Clinical Research & Healthcare • Nutrition & Dietetics • Medical Biotechnology • Ayurvedic Science • Logistic & Supply Chain Management • Aviation Management • Agriculture • Marketing & Automobile Management • University Polytechnic

Students are eligible to get Honours degree with extra credits.

Students who graduate in the accredited programmes during the validity period of accreditation will be deemed to have graduated with an NBA accredited degree.

LATERAL ENTRY

Direct Admission in B Tech IInd Year

Amazon AWS Educate Approved and Verified Cloud Integrated Curricula for B.Tech (CS) and M.Tech (CS) Programmes

Congratulations to our students who have got selected with amazon for internship and a package of ₹30.5* lacs on conversion of full time role

Brickwork RATINGS — BWR A* (Star) Grading (Uttar Pradesh) at the State Level in Education

QS GLOBAL RECOGNITION
QS STARS RATING SYSTEM
QS STARS RATING SYSTEM
Galgotias University is one of India's few Multi-disciplinary Universities with a 5 Stars QS rating in Teaching & Facilities.

RANKED NO. 4
ENGINEERING INSTITUTE
IN NORTH INDIA BY INDIA TODAY GROUP, MDRA SURVEY, MAY, 2019.

TIMES ENGINEERING RANKING 2019
RANKED NO. 1 IN PLACEMENTS AND NO. 1 IN RESEARCH CAPABILITY

RANKED NO. 6
AMONG PRIVATE LAW SCHOOLS IN UP

RANKED NO. 4
IN MEDIA AND COMMUNICATION STUDIES
AMONG PRIVATE UNIVERSITIES IN UP

RANKED NO. 4
AMONG PRIVATE BBA COLLEGES IN UP
BY INDIA TODAY BEST COLLEGES SURVEY, 2020

90% PLACEMENT RECORD B.TECH CSE STUDENTS
91.9% PLACEMENT RECORD MBA STUDENT
91% PLACEMENT RECORD BA LLB/BBA

400+ COMPANIES | 2000+ OFFERS IN 5 MONTHS

amazon | Infosys | Cognizant | TATA CONSULTANCY SERVICES | wipro | accenture

CALL 0120-4370000, +91 9582847072, 9810162221

/GalgotiasUniversity /Galgotias_University /GalgotiasUni admissions@galgotiasuniversity.edu.in

For the complete list of programmes offered & to apply for fully online admission process visit: **www.galgotiasuniversity.edu.in**

SCAN HERE TO APPLY

www.readwhere.com

प्रधान संपादक की कलम से

आजाद भारत में ऐसा वक्त मुश्किल से ही ढूंढे मिलेगा, जब थोड़े ही समय में इतनी सारी चुनौतियां एक साथ आ धमकी हों—महामारी, लॉकडाउन, करोड़ों प्रवासी मजदूरों का शहरों से पलायन, आर्थिक मंदी और सीमा पर सैन्य टकराव. यही मौजूदा हालात हमारे छमाही *इंडिया टुडे*-कार्वी इनसाइट्स देश का मिजाज जनमत सर्वेक्षण को बेहद महत्वपूर्ण बना देता है.

लेकिन देश कभी भी चौंकाने-से नहीं चूकता और, वाकई, लॉकडाउन के बाद हमारे पहले देश का मिजाज सर्वेक्षण से कई हैरतनाक नतीजे निकले हैं. देश में अनेक संकटों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आकाश चूम रही है. उनकी लोकप्रियता 78 फीसद पर अब तक के सबसे ऊंचे मुकाम पर है, जो इसके पहले जनवरी 2017 के सर्वाधिक 69 फीसद से बेहतर है.

हम इस विचित्र घटनाक्रम से इस साल जनवरी में अपने पिछले देश का मिजाज सर्वेक्षण से वाकिफ हुए. प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी सरकार की किसी भी अनुमानित नाकामी से आंच आती नहीं दिखती. उस वक्त भी रोजगार और अर्थव्यवस्था की खस्ताहाली के साथ-साथ सरकार के कामकाज को लेकर काफी बेचैनी थी, मगर मोदी की लोकप्रियता ऊंचे ही चढ़ रही थी, 68 फीसद अंकों के साथ पिछले साल के अगस्त से महज तीन फीसद अंक कम. यह जारी है और उनकी लोकप्रियता से कामकाज के दूर के रिश्ते का खुलासा भला कोविड-19 महामारी में उनकी सरकार के रवैए से बेहतर और क्या हो सकता है. हमारे सर्वेक्षण में 70 फीसद लोगों ने इसे देश में सबसे बड़ी समस्या माना और 25 फीसद का मानना है कि कोविड-19 के प्रति सरकार का रवैया उसकी सबसे बड़ी नाकामी है. फिर भी 77 फीसद लोग महामारी के प्रति मोदी के रवैए को अच्छा या बेहतरीन मानते हैं.

इंडिया टुडे देश की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पत्रिका : रीडरशिप सर्वे
7 फरवरी, 2018 30 रुपए
इंडिया टुडे
विशेषः जनमत सर्वेक्षण
देश का मिज़ाज
चिंता के सबब
मोदी 2019 में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में अब भी सबसे आगे हैं लेकिन भाजपा बहुमत से नीचे खिसक गई
www.indiatodayhindi.in
7 फरवरी, 2018 का आवरण

उन्हें 66 फीसद लोग अगले प्रधानमंत्री के लिए बेहतरीन पसंद मानते हैं. दरअसल, हमारे सर्वेक्षण में 44 फीसद लोग उन्हें अब तक का बेहतरीन प्रधानमंत्री मानते हैं. यह हमारे देश का मिजाज सर्वेक्षण में किसी प्रधानमंत्री को हासिल सर्वाधिक अंक है और जनवरी 2019 के सर्वेक्षण से 29 फीसद अंक अधिक है. उन पर वाकई ऐसा मुलम्मा चढ़ा हुआ है कि कुछ भी नकारात्मक उनसे नहीं चिपकता. लिहाजा, 2016 में उनकी नोटबंदी से भले बड़े पैमाने पर मुसीबतें आईं, मगर उससे चार महीने बाद ही हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा की भारी जीत नहीं रुक पाई. उनकी भाषण-शैली और करिश्मे का कोई जवाब नहीं है. सबसे बढ़कर उनकी लोकप्रियता बड़े करीने से बनाई गई ऐसे जन-हितैषी नेता की छवि से कायम रहती है, जो आम आदमी की दशा सुधारने में शिद्दत से जुटा है. सर्वेक्षण से पता चलता है कि उनकी गरीब-समर्थक और ग्रामीण-समर्थक पहल का भारी असर है. मौजूदा राजनैतिक परिदृश्य में 'महज इकलौते मोदी' का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है और विपक्ष बिखरा-बिखरा-सा है.

हमारे सर्वेक्षण में 16 फीसद लोग अनुच्छेद 370 को बेमानी बनाने को सरकार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि की तरह देखते हैं, जो जनवरी 2020 के मुकाबले हल्का-सा 4 फीसद अंक घटा है. हालांकि अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उनकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानने वालों की तादाद चार फीसद अंक बढ़कर जनवरी 2020 के 9 फीसद से 13 फीसद पर पहुंच गई है.

हमारे सर्वेक्षण में मोदी के इस आभामंडल से सबसे अधिक फायदा एनडीए को है. इस गठजोड़ को जनवरी 2020 में 303 सीटें और 41 फीसद वोट के अनुमान के मुकाबले अब 316 सीटों और 42 फीसद वोट का अनुमान है. भाजपा की सीटों की संख्या जनवरी 2020 के 271 से बढ़कर 283 के अनुमान पर पहुंच गई है लेकिन दोनों सर्वेक्षणों में उसकी वोट हिस्सेदारी एक समान 36 फीसद ही बनी हुई है.

उधर, विपक्ष की दिशाहीनता कायम है. यूपीए जनवरी 2020 में 108 सीटों और 29 फीसद वोट हिस्सेदारी के अनुमान से अब 93 सीटों और 27 फीसद वोट हिस्सेदारी पर पहुंच गई है. कांग्रेस पिछले सर्वेक्षण में 60 सीटों के अनुमान से घटकर 49 सीटों पर आ गई है, जबकि उसकी वोट हिस्सेदारी एक फीसद अंक घटकर 19 फीसद हो गई है. 47 फीसद का मानना है कि पार्टी गर्त की ओर जा रही है. फिर भी, 44 फीसद लोग बतौर विपक्ष कांग्रेस की भूमिका को अच्छा या बेहतरीन बताते हैं. आश्चर्यजनक रूप से 23 फीसद की राय में राहुल गांधी ही कांग्रेस में जान फूंक सकते हैं.

सीमा पर टकराव के मामले में चीन पर आर्थिक पाबंदियां थोपने के सरकार के कदम को सर्वेक्षण में भारी समर्थन मिला. करीब 90 फीसद ने चीन के उत्पादों के बॉयकाट के पक्ष में राय दी, 67 फीसद चीन में न बने सामान खरीदने के लिए अधिक पैसे देने को तैयार हैं और 91 फीसद का सोचना है कि चीन के आक्रामक रुख के जवाब में चीन के ऐप पर पाबंदी और चीन की कंपनियों को ठेका देने से इनकार करना सही कदम है. करीब दो-तिहाई या 69 फीसद का मानना है कि मोदी सरकार ने चीन को करारा जवाब दिया.

हालांकि प्रधानमंत्री को भरपूर समर्थन से सरकार को चैन से नहीं बैठ जाना चाहिए. चेतावनियों के संकेत भी हैं. एनडीए सरकार की अर्थव्यवस्था के मामले में रेटिंग अगस्त 2019 के 60 फीसद से घटकर 43 फीसद पर आ गई है. 33 फीसद का मानना है कि सरकारी नीतियां बड़े कॉर्पोरेट के फायदे में हैं और 63 फीसद की आमदनी काफी घट गई है. सबसे अहम तो यह है कि मोदी के भ्रष्टाचार-मुक्त सरकार की धारणा में गिरावट आई है—सिर्फ 9 फीसद ही उनकी यह उपलब्धि मानते हैं, जो छह महीने पहले से 8 फीसद अंक कम है. इस बीच देश कुछ गंभीर समस्याओं की जद में है. सिकुड़ती अर्थव्यवस्था, देशव्यापी स्वास्थ्य संकट और सीमा पर टकराव गंभीर है. सर्वेक्षण के मुताबिक, देश प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करता है लेकिन उनके आगे महती चुनौती है. अगर वे इन मसलों का सफलतापूर्वक हल निकालने में नाकाम रहते हैं तो उनसे मोहभंग हो सकता है. वह न तो देशहित में, न ही उनके हक में होगा.

अरुण पुरी

(अरुण पुरी)

www.readwhere.com

इंडिया टुडे

www.indiatodayhindi.in

प्रधान संपादक: अरुण पुरी
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर: राज चेंगप्पा
एडिटर: अंशुमान तिवारी
सीनियर एडिटर: मोहम्मद वक़ास
एसोसिएट एडिटर: शिवकेश मिश्र, शुभम शंखधर
असिस्टेंट एडिटर: मनीष दीक्षित, सुजीत ठाकुर
विशेष संवाददाता: संध्या द्विवेदी
राज्य ब्यूरो: आशीष मिश्र (लखनऊ), अमिताभ श्रीवास्तव (पटना), रोहित परिहार (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटर: नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर: चंद्रमोहन ज्योति
चीफ डिजाइनर: असित रॉय
ग्रुप फोटो एडिटर: बंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंट: विक्रम शर्मा, सुबीर हलदर, चंद्रदीप कुमार, शैलेश रावल (अहमदाबाद), मंदार देवधर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चर: प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चर: सलोनी वैद
सीनियर फोटो रिसर्चर: शुभ्रोजीत ब्रह्मा
प्रोडक्शन चीफ: अभिनव पुगला
पब्लिशिंग डायरेक्टर: मनोज शर्मा
एसोसिएट पब्लिशर: अनिल फर्नांडीस
इंपैक्ट टीम: सीनियर जनरल मैनेजर: जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजर: मयूर रस्तोगी (नॉर्थ), उपेंद्र सिंह (बेंगलूरु), कौशिकी गांगुली (ईस्ट)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर: विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजर: दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजर: विपिन बग्गा: (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजर: राजीव गांधी (नॉर्थ)
रीजनल सेल्स मैनेजर: सैयद आसिफ सलीम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजर: पीयूष रंजन दास (ईस्ट)

INDIA TODAY GROUP

वर्ष: 34; अंक: 40; 13-19 अगस्त, 2020; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

- **संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोन: 0120-4807100;
- **ग्राहकी चंदा भेजें:** इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- **ग्राहक सेवा:** कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोन: दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्स: (0120) 4078080. ई-मेल: wecare@intoday.com
- **सर्कुलेशन कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- **इंपैक्ट कार्यालय:** 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोन: 022-66063355 फैक्स: 022-66063226
- **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:** ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोन: 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरु-560 025 फोन: 2212448, 226233, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN. फैक्स: 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालय: के-9, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001

- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.

- **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा के-9, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110 001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित. संपादक: राज चेंगप्पा**

सुर्खियां
आइपीएल: यह शो रुकना नहीं चाहिए
पेज 5

अर्थात्: जागते रहो
पेज 11

भीतर

फुरसत
सवाल+जवाब/इला अरुण: लय में लगातार
पेज 58

इंडिया टुडे ग्रुप-कार्वी इनसाइट्स

देश का मिजाज

आवरण कथा

24 मोदी मंत्र

देश विभिन्न संकटों से जूझ रहा है, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है, आखिर इसका राज क्या है?

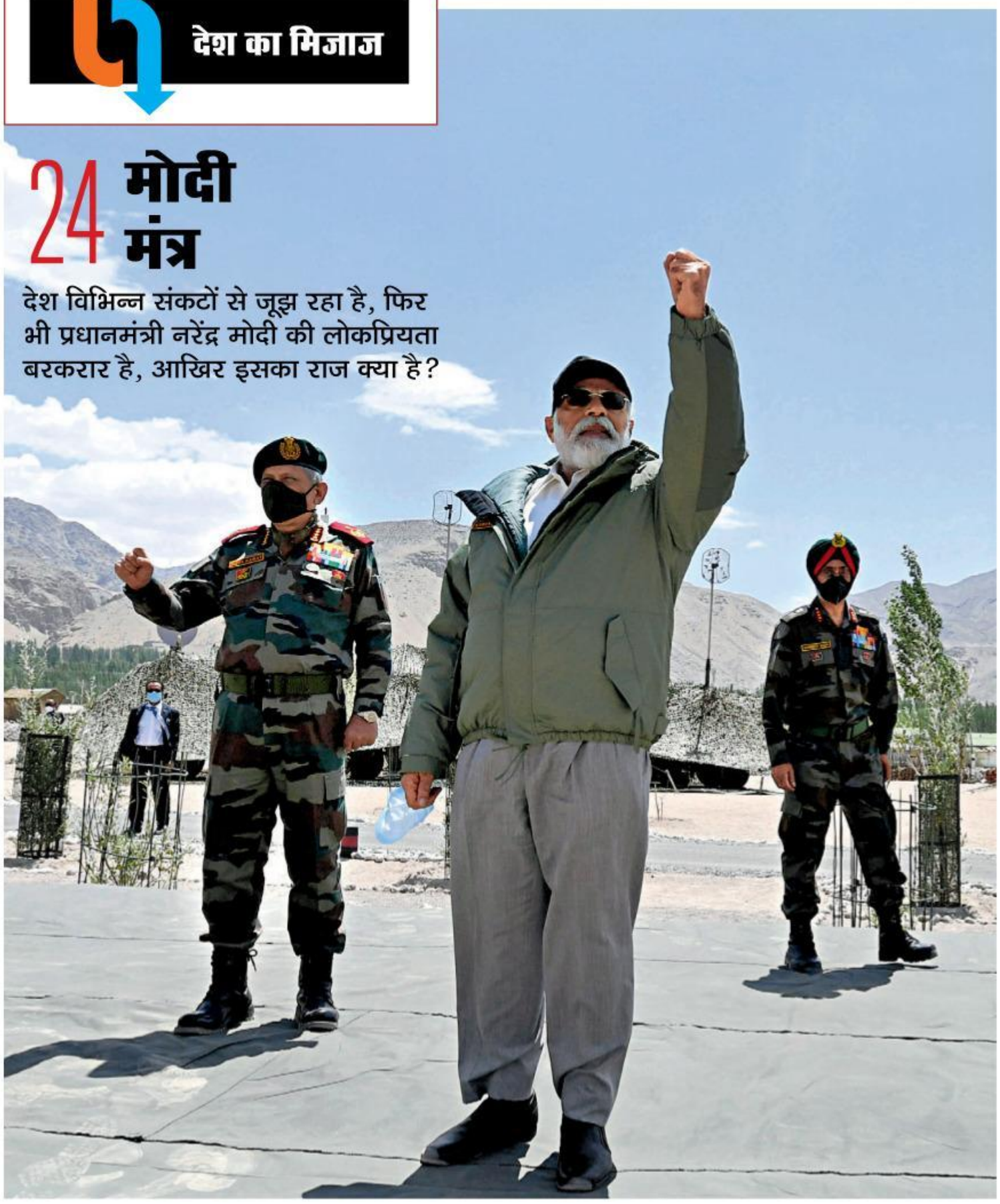

खास रपट

12 राम के नाम अयोध्या का 'नवनिर्माण'

राम मंदिर के साथ-साथ अयोध्या का हिंदू धार्मिक पर्यटन के केंद्रबिंदु के तौर पर पुनर्निर्माण करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार 5,000 करोड़ खर्च कर रही हैं.

आवरण फोटो: **पीआइबी**

INDIA TODAY GROUP

पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी वस्तु, सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वचनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों को विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशनों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

www.readwhere.com

राजस्थानः महारानी की खामोशी
पेज 10

सुर्खियां

अर्थातः जागते रहो
पेज 11

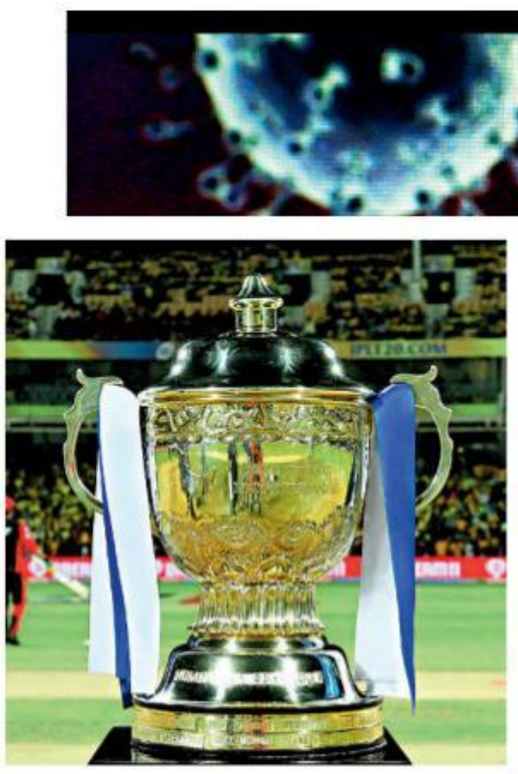

किसी भी कीमत पर

महामारी के दौर में भी आइपीएल रद्द करना इसलिए मुश्किल है कि इसमें बहुत ऊंचे दांव लगे हैं. इसी वजह से विकल्प तलाशे जा रहे हैं

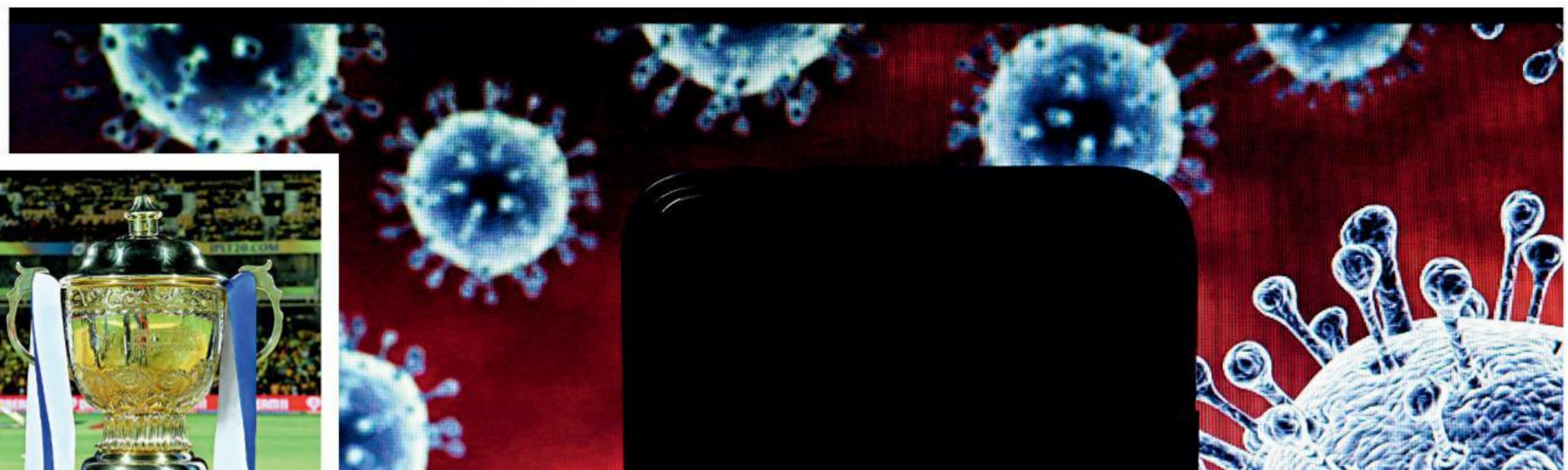

गेट्टी इमेजेज

आइपीएल

यह शो रुकना नहीं चाहिए

आनंद वसु

दुनियाभर में महामारी फैलने लगी तो सरकारें लॉकडाउन के लिए मजबूर हुईं. क्रिकेट खेलने वाले देशों के बीच संपर्क टूट गया था, इसलिए क्रिकेट में व्यवधान आना लाजिमी था. क्रिकेट बोर्ड से लेकर खिलाड़ियों और मैच प्रसारकों से लेकर प्रायोजकों और प्रशंसकों तक, क्रिकेट के सभी हितधारक खेल कैलेंडर में व्यवधान से चिंतित थे. बहुत सारे खिलाड़ियों की इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के साथ विशेष रुचि और चिंता जुड़ी होती है. इसके पीछे कई अच्छी वजहें भी होती हैं.

निश्चित रूप से, आइसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) ट्वेंटी-20 विश्व कप का रद्द होना, जो अक्तूबर में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना था, अधिकतर क्रिकेट बोर्डों की प्राथमिकता में सबसे ऊपर था. आखिरकार, बहुत से ऐसे देश जो कम क्रिकेट खेलते हैं, उनके राजस्व का एक बड़ा हिस्सा आइसीसी के आयोजनों से ही तो आता है. लेकिन खिलाड़ियों के लिए, जो इस खेल में सबसे अहम भूमिका में होते हैं, पैसा तो दरअसल आइपीएल से ही आता है; शेष क्रिकेट जो वे खेलते हैं, वह तो बस एक पूरक आय है.

ट्वेंटी-20 विश्व कप के रद्द होने और इस बात को लेकर एक व्यापक स्वीकृति के साथ कि महामारी के बीच भी जीवन रुकना नहीं चाहिए, आइपीएल से संबंधित सवाल क्या यह होना चाहिए से बदलकर यह कहां होना चाहिए हो गया और सभी संबंधित पक्षों ने इससे राहत की सांस ली. यह भारत में नहीं हो सकता यह बात तो लगभग तुरंत तय हो गई. चिकित्सा सुरक्षा की किसी भी डिग्री के साथ इस तरह के टूर्नामेंट की मेजबानी करना लगभग असंभव था. इस चुनौती के अलावा, जब भारत में कोविड के कारण लोगों की जिंदगी और आजीविका पर बड़ा संकट दिखता हो, ऐसे में दो महीने लंबा क्रिकेट उत्सव कराना गलत संदेश देता और उसकी आलोचना होती.

आइपीएल भारत के बाहर कराया जा सकता है, इस विचार के साथ ही जगहों की खोज शुरू हुई तो सबसे पहले न्यूजीलैंड के

www.readwhere.com

सुर्खियां

47,500
करोड़ रुपए
है आइपीएल की अनुमानित ब्रांड वैल्यू

34 करोड़ डॉलर
(2,550 करोड़ रुपए)
चीनी मोबाइल कंपनी विवो ने बीसीसीआइ को पांच साल, 2022 तक, के आइपीएल सौदे के लिए दिए

2.55 अरब डॉलर
(19,125 करोड़ रुपए)
स्टार टीवी ने बीसीसीआइ को दिए पांच साल के ब्रॉडकास्टिंग अधिकार के लिए

बारे में सोचा गया. दरअसल, क्रिकेट खेलने वाले प्रमुख देशों में न्यूजीलैंड ऐसा था जो महामारी से सबसे कम प्रभावित था. लेकिन मेजबान के रूप में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो बात जा रही थी, वह उसका भौगोलिक नक्शे पर अलग-थलग होना था. यह बहुत संभव नहीं लगता कि इस तरह के टूर्नामेंट का वहां बहुत स्वागत होगा, और शायद इससे भी बड़ी बात कि यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं लगा.

श्रीलंका ने भी मैच के लिए अपने हाथ खड़े किए, पर यह हाथ किसी भी अन्य चीज से ज्यादा, उम्मीद में खड़ा किया था. श्रीलंका में वर्ष के उस वक्त दो महीने की बारिश-मुक्त शामें (या भारत के अधिकांश हिस्सों में भी) होना, एक ख्याली पुलाव ही होता.

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के लिए 'कहां' प्रश्न का उत्तर देना बहुत आसान रहा: बारिश की कोई संभावना नहीं और ज्यादा अहम बात कि भौगोलिक रूप से यूएई सबसे अधिक क्रिकेट देशों के खिलाड़ियों के लिए बस एक उड़ान की दूरी पर है. यानी वहां एक केंद्रीय, एक स्थान पर क्वारंटीन संभव है.

वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड में अपनी तीन टेस्ट मैचों की शृंखला खेली लेकिन उसके लिए जो तैयारियां हुईं वे अभूतपूर्व थीं. खिलाड़ियों को क्वारंटीन की जरूरतें पूरी करनी थी और उन्होंने बायो सिक्योर बबल (एक अत्यंत सुरक्षित जैव-सुरक्षित माहौल) में अपना क्रिकेट खेला.

बबल निर्माण ने एक संकेत दिया कि कोविड के समय में टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए किस तरह के इंतजाम करने होंगे. इस प्रयोग का अर्थ था कि लोगों के एक निश्चित समूह—खिलाड़ियों, सहायक कर्मचारियों और बिल्कुल आवश्यक अन्य कर्मचारियों से—के अलावा अन्य कोई भी खेल के मैदान और टीम होटल जैसे मुख्य क्षेत्रों में न तो प्रवेश कर सकेगा न बाहर जा सकेगा. इंग्लैंड में दो स्थानों पर, होटल उन ग्राउंड्स में ही थे जहां मैच खेले गए.

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने कहा कि यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म में होने जैसा था. उन्होंने कई बार कहा है, ''हर कोई मास्क पहने था और आप किसी को भी देख नहीं सकते हैं. आपको पता नहीं चलता कि वे आपके लिए मित्रवत हैं या नहीं! यह थोड़ा अलग और अजीब है, लेकिन अब हमें इसकी आदत डालनी होगी.'' खिलाड़ियों के शरीर का तापमान नियमित अंतराल पर लिया जाता था, और उस सुरक्षित बबल में प्रवेश करने से पहले कोविड जांच होती थी और बाद में भी थोड़े-थोड़े अंतराल पर जांच होती थी.

दुबई में जो बबल बनाया जाएगा वह एकदम इंग्लैंड के जैसा नहीं, पर उससे बहुत मिलता-जुलता होगा. यूएई में एक अहम अंतर यह है कि यहां खेल के स्थानों पर होटल नहीं हैं. यह निर्धारित किया गया है कि संयुक्त अरब अमीरात पहुंचने वाले सभी खिलाड़ी आगमन के पहले सप्ताह में तीन कोविड-19 जांच से गुजरेंगे और तीनों जांच में सुरक्षित पाए जाने के बाद ही उन्हें बायो-सिक्योर्ड बबल में प्रवेश दिया जाएगा. प्रत्येक स्थान पर कलर-कोडेड जोन होंगे—सबसे भीतरी जोन हरे रंग का होगा, जहां केवल खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों को प्रवेश की अनुमति होगी; नारंगी, जहां परिचालन कर्मचारी भी अपना काम कर सकते हैं; और सबसे बाहरी घेरा लाल रंग का होगा जहां बबल के बाहर से आवश्यक वस्तुओं जैसे कि भोजन, पानी और ऐसी ही अन्य वस्तुओं की नियमित रूप से आपूर्ति होगी.

इंग्लैंड में इसी तरह का सख्त अलगाव किया गया था—60 से कम लोगों को ग्रीन जोन में जाने दिया जाता था—पर यह आइपीएल के लिए बहुत अधिक जटिल होगा. प्रत्येक टीम में 24 खिलाड़ी हैं. उसमें कोच और सहायक कर्मचारियों को जोड़ लें. हर दिन दो मैच होने का मतलब है कि लोगों के अलग-अलग सेट मैच में शामिल हैं, यानी वास्तविक तस्वीर बहुत अलग हो सकती है. अकेले सुरक्षा इंतजाम ही थोड़े डराने वाले दिखते हैं.

जब इतनी सारी दिक्कतें हैं फिर आइपीएल का आयोजन कराया जाना इतना जरूरी क्यों है? उद्योग के विशेषज्ञ लीग की ब्रांड वैल्यू को सबसे बड़ी वजह मानते हैं. इस साल फरवरी में वित्तीय सलाहकार डफ ऐंड फेल्प्स के अनुमान के मुताबिक, आइपीएल का बाजार मूल्य 47,500 करोड़ रुपए है. अनुमान लगाया गया है कि आइपीएल के प्रत्येक संस्करण ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 17.5—20 करोड़ डॉलर के बराबर योगदान किया.

सबसे अहम बात कि इस साल आइपीएल के न होने का मतलब था कि बीसीसीआइ (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) के कोष को एक बड़ी चपत लग जाती. पांच साल के प्रसारण अधिकारों के लिए स्टार, जिसने 2.55 अरब डॉलर (19,125 करोड़ रुपए) का भुगतान किया है, कतार में सबसे आगे होता, लेकिन फ्रेंचाइजी, खिलाड़ी, विज्ञापनकर्ता, प्रायोजक सभी बहुत तेजी से कतार में खड़े होने लगते. संभवत: यही वजह है कि जुलाई की शुरुआत में सौरव गांगुली ने कहा था: ''हम नहीं चाहते कि वर्ष 2020 बिना आइपीएल के खत्म हो जाए. हमारी पहली प्राथमिकता भारत है और भले ही हमें 35-40 दिन ही मिले, हम इसकी मेजबानी करेंगे. लेकिन हमें पता नहीं है कि हम कहां करेंगे.''

जब तक यूएई में टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए जरूरी अनुमति मिली, आइपीएल पर एक और संकट छा गया—चीनी कंपनी विवो 2020 के टूर्नामेंट का स्पॉन्सर बनने के वादे से पलट गई. विवो और बीसीसीआइ दोनों ने चुप्पी साध रखी है—और 3 अगस्त तक परेशानी के कोई संकेत भी नहीं दिख रहे थे—अब यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों के बीच संबंधों का भविष्य क्या होगा. विवो ने 2015 में दो साल के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे, और फिर 34 अरब डॉलर का भुगतान करके उसे अगले पांच साल के लिए यानी 2022 तक बढ़ाया था.

आखिरी समय में विवो के हाथ खींच लेने से अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या अन्य चीनी कंपनियों ने भी टीम के प्रायोजकों के रूप में जो निवेश किया है, उससे पीछे हट जाएंगी. खिलाड़ियों और अन्य सभी हितधारकों के मन में फिलहाल एक ही सवाल चल रहा है 'अभी क्यों?' जहां पहले सारी बात किसी भी रूप में टूर्नामेंट खेलने की थी और इसे नि:स्वार्थ भाव से एक अरब लोगों के मनोरंजन के लिए बताया जा रहा था, वहीं अब जिसे धीमी आवाज में पूछा जा रहा है: जब दुनिया में आग लगी है तब भी आइपीएल क्यों खेला जाए? ■

www.readwhere.com

लॉकडाउन तिकड़म

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने महामारी की चुनौती तो है, पर अगले साल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर वे किसी धार्मिक भावना के ठेस पहुंचाने से परहेज कर रही हैं. ममता अगस्त से पखवाड़े भर का लॉकडाउन लगाना चाहती थीं, लेकिन इतने सारे त्योहार और कार्यक्रम—ईद, रक्षाबंधन, विश्व आदिवासी दिवस, जन्माष्टमी, पारसी नववर्ष, गणेश चतुर्थी, मुहर्रम और यहां तक कि ग्रामीण बंगाल की लोकप्रिय देवी मनसा की पूजा—के कारण उन्हें इसकी तारीख छह बार बदलनी पड़ी. अब लॉकडाउन पूरे महीने में सिर्फ सात दिन तक लागू होगा. यह लॉकडाउन भी ममता के तिकड़म में फंस गया!

इलस्ट्रेशनः सिद्धांत जुमडे

कार में नाम

जुलाई के आखिरी दिनों में भारत आनेवाले पांच राफेल के टेल नंबर में एयरचीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया का संक्षिप्त नाम आरबी लिखा है, और उनके पूर्ववर्ती बी.एस. धनोआ के लिए बीएस. फ्रांस से इन लड़ाकू विमानों की खरीद में उनकी भूमिका के मद्देनजर यह आभार जताने जैसा है. लेकिन मध्य प्रदेश के नौकरशाह इससे प्रभावित नहीं हैं. राज्य के मुख्य सचिवों की कारों में बहुत पहले ही रजिस्ट्रेशन प्लेट में अपने संक्षिप्त नाम जुड़वा रखे हैं. 2002-04 तक मुख्य सचिव रहे ए.वी. सिंह की कार का नंबर एमपी 02 एवी 0001 था, 2013-16 तक पद पर रहे एंथनी डि सा की कार का नंबर एमपी 02 एडी 0001, जबकि उनके उत्तराधिकारी बी.पी. सिंह की कार का नंबर एमपी02 बीपी 0001 था. ये अधिकारी रिटायर हो चुके हैं पर एवी, एडी और बीपी सीरीज अभी चालू है और नई कारें उनमें रजिस्टर हो रही हैं.

www.readwhere.com

पावर लंच

लंच ब्रेक के बहाने लखनऊ के शक्ति भवन से अमूमन गायब रहने वाले उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ ऊर्जा अधिकारियों में इन दिनों खलबली मची हुई है. ऊर्जा मंत्री **श्रीकांत शर्मा** ने अब दफ्तर में ही लंच करना शुरू कर दिया है और वे चाहते हैं कि उनकी टीम भी इसमें शामिल हो. अधिकारियों की चिंता है कि शर्मा के दफ्तर में लगे बड़े-से एलईडी डैशबोर्ड पर पूरे राज्य में बिजली की उपलब्धता और आपूर्ति दिखती रहती है और दीवार पर टारगेट का चार्ट चस्पां है. नतीजा यही है कि लंच का मतलब और अधिक काम.

इंडिया टुडे

प्रतिद्वंद्वी का प्रादुर्भाव!

कर्नाटक के मुख्यमंत्री **बी.एस. येद्दियुरप्पा** के खेमे में खतरे की घंटी बज उठी, जब उनके नायब लक्ष्मण सवाडी 27 जुलाई को राज्य सरकार की पहली सालगिरह के समारोह से नदारद रहे और आला भाजपा नेताओं से मिलने नई दिल्ली पहुंच गए. सवाडी भी येद्दियुरप्पा की तरह लिंगायत हैं और पार्टी का एक धड़ा उन्हें मुख्यमंत्री के वारिस के तौर पर पेश करता है. येद्दियुरप्पा असंतुष्ट नेताओं को बोर्ड और निगमों में पद देते रहे हैं. लेकिन कोविड पॉजिटिव आने और अस्पताल में भर्ती होने के बाद से उनके भविष्य को लेकर कयासों का दौर चल निकला है.

—संदीप उन्नीथन, साथ में **रोमिता दत्ता, राहुल नरोन्हा, आशीष मिश्र** और **अरविंद गौड़ा**

कोविड–19 संकट से मुकाबले के लिए आईटीसी की पहल

कोविड-19 महामारी एक अभूतपूर्व स्तर का खतरा है. राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में, आईटीसी सरकार द्वारा की जा रही कोशिशों को समर्थन देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है.

आईटीसी आकस्मिक कोष

आईटीसी ने इस प्रतिकूल स्थिति से उपजी चुनौतियों के समाधान और प्रबंधन के लिए 150 करोड़ रुपये का आकस्मिक कोष (कंटीजेंसी फंड) बनाया. इसका उपयोग मुख्य रूप से महामारी से बुरी तरह प्रभावित समाज के कमजोर और सबसे जरूरतमंद वर्गों को राहत देने के लिए किया जाएगा. इसे जिला अधिकारियों के सहयोग में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की मदद में लगाए जाने का विचार है. इसके अलावा, फंड को देश भर में लोगों को लोगों के लिए दवा, किराने का सामान, अन्य आवश्यक सामग्री, कृषि–वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने वालों को व्यक्तिगत सुरक्षात्मक साधन और स्वच्छता उत्पाद प्रदान करने में लगाया जाएगा.

आईटीसी ने #PMCaresFund में भी 100 करोड़ रुपये का योगदान दिया है.

सभी जिले में कमजोर तबके को मदद

कंपनी स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर खाद्य पदार्थों के साथ–साथ साबुन और सैनिटाइजर जैसे स्वच्छता उत्पाद उपलब्ध कराने के प्रयास में जुटी है. 23 राज्यों के विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों को 28 लाख से अधिक साबुन, 16 लाख पैकेट YiPPee! नूडल्स, सनफीस्ट बिस्कुट के 26 लाख पैकेट, बी नेचुरल फ्रूट जूस के 6 लाख पैक, 3.3 लाख किलोग्राम आटा, 4.6 लाख पैकेट स्नैक्स दिए गए हैं. पुलिसकर्मियों के साथ–साथ स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों के लिए सैवलोन साबुन दिए गए हैं. फ्रंटलाइन स्टाफ और वैल्यू चेन पार्टनरों को एक लाख मास्क वितरित किए जा रहे हैं.

व्यवसायों द्वारा विशिष्ट पहल

बिजनेस डिवीजन भी सक्रिय योगदान कर रहे हैं. फूड्स डिवीजन ने 'आशीर्वाद बॉक्स ऑफ होप' और 'सनफीस्ट बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस' पहल के माध्यम से बच्चों और बुजुर्गों को खाद्य पदार्थों की मदद भेजी है. जरूरतमंदों को आवश्यक खाद्य आपूर्ति के लिए आईटीसी ने 3 प्रमुख एनजीओ का एक साझा नेटवर्क बनाया है. फूड्स डिवीजन ने राजस्थान के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक भीलवाड़ा में फूड पैकेज बांटे जिसमें करीब एक महीने की जरूरत का 10 किलो आटा और बिंगो स्नैक्स शामिल है!

आईटीसी के पेपर और पेपरबोर्ड डिवीजन (आईटीसी पीएसपीडी) ने तेलंगाना में भोजन के पैकेट बांटे. आईटीसी पीएसपीडी के डॉक्टरों ने जागरूकता शिविर लगाए. भद्राचलम में, ट्रक चालकों को दस्ताने बांटे, सिकंदराबाद में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सैनिटाइजर दिए. भद्राचलम कारखाने के आसपास के 18 गांवों को सेनेटाइज भी किया. वेल बीइंग आउट ऑफ वेस्ट टीम द्वारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 16 जिलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए. लॉकडाउन में छात्रों को रचनाशील कामों में लगाए रखने के लिए आईटीसी क्लासमेट ने स्किल और आर्ट फॉर्म के लिए एक सोशल मीडिया अभियान चलाया.

तैयार भोजन का वितरण

देशभर में प्रवासी कामगारों और जरूरतमंदों के लिए भोजन की स्थानीय प्रशासन और अस्पतालों

www.readwhere.com

द्वारा बताई गई आवश्यकता अनुसार, आईटीसी के होटल और आईटीसी कारखाने पूरी मदद कर रहे हैं. अब तक 1 लाख से अधिक मील्स (भोजन) प्रदान किए गए हैं. नई दिल्ली में आईटीसी मौर्य और शेरेटन, प्रवासी श्रमिकों को बांटने के लिए प्रतिदिन 1500 से अधिक मील्स दे रहे हैं. बेंगलुरु में आईटीसी गार्डेनिया ने नगर निगम को 15 दिनों तक रोजाना 1000 भोजन पैकेट (15000 मील्स) दिए. मुंबई में आईटीसी ग्रैंड सेंट्रल ने एमजी हॉस्पिटल में और कस्तूरबा अस्पताल के डॉक्टरों के लिए भोजन तैयार किया. लखनऊ में फॉर्च्यून होटल प्रतिदिन 1000 से अधिक मील्स उपलब्ध करा रहा है. पेपरबोर्ड बिजनेस, भद्राचलम कारखाने के आसपास के प्रवासी मजदूरों को 1400 से अधिक भोजन पैकेट बांटता है. यूपी के सहारनपुर में आईटीसी कारखाने और पटना में आईटीसी की टीमें प्रतिदिन 3500 से अधिक फूड पैकेट उपलब्ध करा रही हैं.

आईटीसी होटलों ने क्वारंटीन की जगह उपलब्ध कराई

मुंबई नगर निगम ने आईटीसी मराठा को क्वारंटीन स्पेस के रूप में इस्तेमाल किया. आईटीसी होटल्स स्थानीय प्रशासन और दूतावासों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. आईटीसी ग्रैंड चोल और आईटीसी कोहेनूर ने भी ऐसी पेशकश की है ताकि आवश्यकता पड़ने पर एसिम्पटमेटिक अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को वहां ठहराया जा सके. जयपुर और गोवा में आईटीसी होटल ने डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए शॉवर कैप और सैनिटाइटर उपलब्ध कराया.

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति

महामारी के दौरान, देशभर में खाद्य और स्वच्छता उत्पादों को पहुंचाना जरूरी था. आईटीसी ने यह सुनिश्चित किया है कि आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण और वितरण, न्यूनतम लोगों के साथ निर्बाध रूप से जारी रहे. कारखानों में उच्च स्तर पर एहतियात बरतते हुए व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक दूरी के सख्त प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं. कारखानों में काम करने या बाजारों में आपूर्ति करने वाले कर्मचारियों के लिए सैनिटाइजर, सुरक्षात्मक उपकरण, मास्क, नियमित तापमान जांच, काम के आरामदायक घंटे और 24X7 चिकित्सा सहायता का प्रबंध रहा. जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी कार्यक्रम का लाभ उठाकर, आटा और मसाले जैसे आवश्यक सामान की डिलीवरी के लिए आईटीसी ने डोमिनोज के साथ करार किया है.

स्वच्छता उत्पादों का निर्माण

आईटीसी के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स डिवीजन ने बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए सैवलॉन सैनिटाइजर का उत्पादन बढाया है. हिमाचल प्रदेश की अपनी विश्वस्तर की इत्र निर्माण सुविधा को अतिरिक्त 1,25,000 लीटर सैवलॉन हैंड सैनिटाइटरों के उत्पादन के लिए तैयार किया गया. सरकारी आदेश के अनुसार और सार्वजनिक हित में, आईटीसी ने सैवलॉन सैनिटाइटर की कीमतें कम की हैं और नए स्टॉक को बाजार तक पहुंचाने के लिए दिन रात काम चला है.

किसानों के साथ काम

बाजार में कृषि–वस्तुओं की आपूर्ति एक चुनौती है पर आईटीसी के एग्री बिजनेस डिवीजन अपनी संस्थागत क्षमताओं और अन्य संरचनात्मक लाभों के बूते कृषि उपज की खरीद शुरू करने के विकल्पों को तलाशा है. कृषि व्यवसाय, आईटीसी ई–चौपाल 4.0 जैसी मोबाइल तकनीक और स्थानीय फील्ड कर्मचारियों की ताकत का लाभ उठाते हुए किसानों को सर्वोत्तम सुरक्षा उपायों के साथ प्रौद्योगिकी का उपयोग करके खेती की निरंतरता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है.

आईटीसी में फ्रंटलाइन वॉरियर्स का सम्मान

आशीर्वाद रेंज के बुनियादी खाद्य पदार्थों, सनफीस्ट बिस्कुट या सैवलॉन सैनिटाइजर जैसे कई आवश्यक उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे आईटीसी के अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो संदेशों सहित कई अभियान शुरू किए गए हैं. कंपनी के चेयरमैन श्री संजीव पुरी ने पूरी टीम आईटीसी की ओर से, कर्मचारियों को एक प्रेरणादायक पत्र लिखकर उस जज्बे और समर्पण को सलाम किया है जो कर्मचारियों ने इस चुनौतीपूर्ण समय में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करके राष्ट्र की सेवा के रूप में दिखाई है.

कर्मचारियों की कुशलता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना

आईटीसी ने इस स्वास्थ्य आपदा में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी पहलें की हैं. चेयरमैन और कॉर्पोरेट प्रबंधन समिति रोजाना स्थिति की निगरानी कर रहे हैं. निगरानी और सहायता प्रदान करने के केंद्रीय स्तर पर और प्रत्येक बिजनेस के अंदर आकस्मिक प्रबंधन टीमों को तैयार रखा गया है. चेयरमैन कई माध्यमों से कर्मचारियों को प्रेरित करते रहे हैं और उन्हें कंपनी की ओर से हर तरह की मदद का आश्वासन दिया है. कंपनी के डॉक्टरों की एक टीम को किसी भी सलाह या सहायता के लिए 24X7 उपलब्ध कराया गया है. जिन लोगों को फैक्ट्रियों में काम करना है या आवश्यक उत्पादों की आपूर्ति को बनाए रखना है, उनके लिए सेवलॉन सैनिटाइजर, सुरक्षात्मक उपकरणों, मास्क आदि का प्रयोग और नियमित तापमान की जांच, सामाजिक दूरी से जुडे दिशानिर्देशों के साथ–साथ काम के आरामदायक घंटे जैसी सुरक्षा सावधानियां लागू की गई हैं. घर से काम कर रहे कर्मचारियों समेत सभी के साथ नियमित रूप से संचार जारी है और उन्हें डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए जा रहे हैं. आईटीसी के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आईटीसी इन्फोटेक, तकनीकी सहयोग प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है, और घर से काम कर रहे कर्मचारियों के लिए काम का संचालन निर्बाध रखने में सक्षम बनाती है.

6 अप्रैल 2020 को

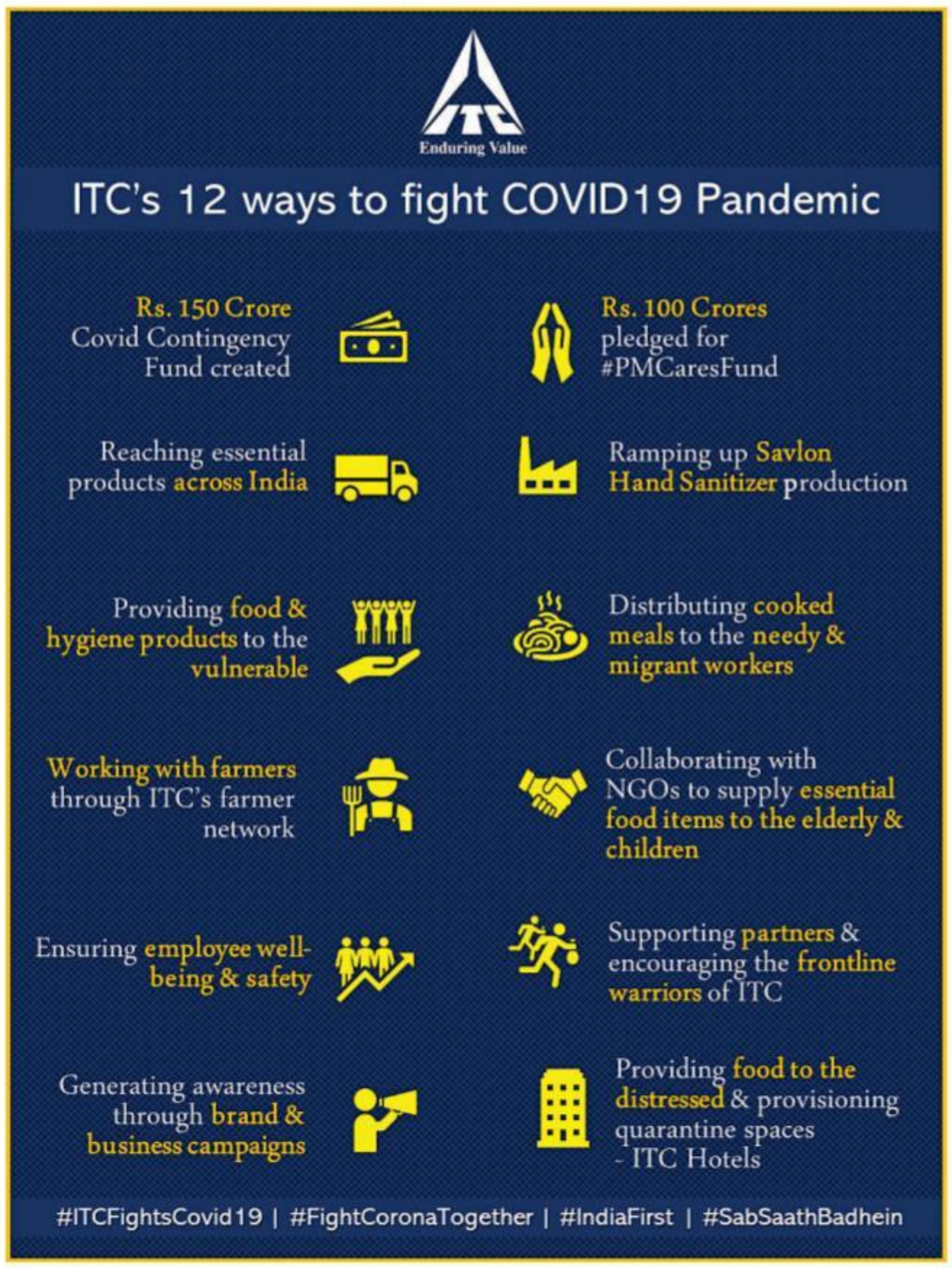

www.readwhere.com

राजस्थान

महारानी की खामोशी

रोहित परिहार

मौन की ताकत
राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अप्रैल 2019 में नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में

चंद्रदीप कुमार

इस जुलाई की 31 तारीख को भाजपा की राजस्थान इकाई ने राज्य कार्यकारिणी के नए सदस्यों के नामों की घोषणा की. उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और अनुशासन समिति सदस्यों जैसे 30 पदों में से ज्यादातर वसुंधरा राजे विरोधी तिकड़ी—प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, महासचिव (संगठन) चंद्रशेखर और विपक्ष के उप नेता राजेंद्र सिंह राठौर के नामांकित लोगों के पास चले गए. विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद से पार्टी ने ऐसा कोई मौका नहीं खोया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री के विरोधियों को आगे न बढ़ाया गया हो. जब गजेंद्र शेखावत को केंद्रीय मंत्री और ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया, तभी रणनीति स्पष्ट हो गई थी—भाजपा राजे विरोधी नेताओं को खड़ा कर रही है. पार्टी ने उनके बेटे और चार बार के सांसद रहे दुष्यंत सिंह के मंत्री पद के दावे को भी नजदरअंदाज कर दिया.

राजस्थान में जब भाजपा ने अशोक गहलोत की अगुआई वाली कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए पूरा जोर लगा रही थी तो दो महीने के पूरे घटनाक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अस्वाभाविक रूप से खामोश रहीं. 1 अगस्त को केंद्रीय जलशक्ति मंत्री शेखावत ने एक न्यूज एजेंसी से कहा, ''राजे की खामोशी एक ऐसी रणनीति हो सकती है जिसमें चुप्पी शब्दों से अधिक जोरदार होती है.'' यह एक संकेत था कि भाजपा आला कमान चिंतित है.

इस संदर्भ में, सात बार के विधायक राठौड़, एक खास केस स्टडी हैं. पार्टी और आरएसएस को उनके विवादित अतीत की वजह से उनसे चिढ़ है. लंबे समय तक वे चाहते थे कि राजे उन्हें किनारे लगा दें लेकिन जब 2014 में उन्होंने राठौड़ से दूरी बनाई तो विरोधी खेमे ने राठौड़ का बांहें खोलकर स्वागत किया. नई कार्यकारिणी में दो ऐसे युवा भी शामिल किए गए जो पहले उनकी मंडली में थे पर अब राजे के दुश्मनों में गिने जाते हैं. इनमें पहला नाम है अजय पाल सिंह, जिनका बहुत जनाधार नहीं है पर वे अब पार्टी उपाध्यक्ष हैं. सिख समुदाय के सिंह 2003 में मीडिया की निगाहों में आए थे जब राजे राज्य की राजनीति में गहलोत की कांग्रेस सरकार से भिड़ने के लिए उतरी थीं. तब राजे, अजय पाल सिंह के जयपुर स्थित भव्य बंगले में साल भर तक टिकी थीं. बाद में उनको राजे ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाकर उपकृत किया और यह तथ्य नजरअंदाज किया था कि उनकी रियल एस्टेट कंपनी है. अगले चार साल में उनकी कंपनी खूब फूली-फली. 2008 में चुनावों में उन्होंने राजे के लिए खूब फंड मुहैया कराया. 2008 के चुनाव अभियान के दौरान, और उसके बाद कई और बार, गहलोत ने टिप्पणी की थी कि अजयपाल राजे की दहशत से उनके सामने रो पड़े थे. दया की भीख मांगता उनका आंसुओं भर चेहरा तब स्थानीय अखबारों के पहले पन्ने पर छपा था. जब वे दोबारा मुख्यमंत्री बनीं तो उन्होंने राजे के नजदीक आने की कोशिश की, पर कड़वाहट दूर नहीं हुई.

दूसरी बड़ी नियुक्ति बतौर महासचिव सांसद दिया कुमारी की है और यह संकेत है कि पार्टी जयपुर की राजकुमारी को धौलपुर की महारानी राजे के वैकल्पिक शाही चेहरे के रूप में पेश करना चाहती है.

इस बीच, प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने राजे-विरोधी रणनीति को खारिज करते हुए और कहा कि पार्टी अपने नेताओं के लिए भूमिका तय करती है. वे कहते है, ''हमने नए चेहरों और ऐसी नई जातियों को शामिल किया है जिनका प्रतिनिधित्व कम था.'' इस बात का समर्थन विधायक और पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी भी करते हैं. लेकिन क्या भाजपा राजे और उनकी टीम को हाशिए पर धकेलने का खतरा तब उठा सकती है जब कांग्रेस के गहलोत कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं? राजे कहती हैं कि वे पार्टी के फैसले से बंधी हैं; लेकिन इसके बाद गहलोत की टिप्पणी आई कि भाजपा में कद घटाने की कोशिशों से वे (राजे) बहुत नाखुश हैं. प्रदेश में भाजपा के 72 विधायक हैं इनमें से राजे को 45 विधायकों का समर्थन हासिल है और इनमें से अधिकतर राजे के प्रति बेहद वफादार हैं. बाकी के लोग बंटे हुए हैं, जिनमें से 20 लोग विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया के साथ हैं.

प्रदेश की राजनीति में राजे महत्वपूर्ण कारक हैं. वे सत्ताविरोधी लहर को बड़ी जीत में तब्दील करने में कामयाब रही हैं. यह प्रतिभा भाजपा या कांग्रेस के कुछ ही नेताओं में है. विधानसभा चुनावों में दो पराजयों में भी उन्होंने हाल के दशकों में दूसरों के मुकाबले अधिक सम्मानजनक सीटें हासिल की हैं. बहरहाल, जब मोदी-शाह के पसंदीदा शेखावत कहते हैं कि उनकी (वसुंधरा) खामोशी विस्फोटक हो सकती है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि कयास नए उभरते राजनैतिक समीकरण के भी हैं. ■

जब मोदी-शाह के पसंदीदा शेखावत कहते हैं कि उनकी (वसुंधरा) खामोशी विस्फोटक हो सकती है तो ऐसा इसलिए क्योंकि कयास नए राजनैतिक समीकरण के भी हैं

www.readwhere.com

अर्थात्

जागते रहो

अंशुमान तिवारी

घनघोर मंदी के बीच शेयर बाजार की छलांग देखने के बाद एक नवोदित ब्रोकर ने शेयरों-शेयरों का पानी पिए अपने तपे तपाए उस्ताद के केबिन में जाकर खिलखिलाते हुए कहा, ''सर, मजा आ गया, आज तो निफ्टी रॉकेट हुआ जा रहा है.'' उम्रदराज ब्रोकर ने कंप्यूटर से निगाहें हटाकर कहा, ''लकी फूल' हो तुम.'' यानी किस्मती मूर्ख, जो मौके के सहारे मीर (फूल्ड बाई रैंडमनेस) बन जाते हैं और अपनी कामयाबी को तर्कसंगत ज्ञान मान बैठते हैं. सतर्क होकर ट्रेड करो, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की मर्यादा मत तोड़ना.

यकीनन अर्थव्यवस्था में जितने नकारात्मक आंकड़े हो सकते हैं वे सब एक साथ बरस रहे हों और अनिश्चितता की ब्रह्मपुत्र कारोबारों को अपनी बाढ़ में डुबा रही हो तब शेयर बाजार में जोखिमों का भंवर तैयार होने के लिए यह सबसे माकूल मौका है. बाजार हमेशा वास्तविकताओं को कंबल ओढ़ाकर ख्याली तेजी में लग जाता है इसलिए अगर आप बहुत उत्साही हैं तो भी कुछ ताजा तथ्यों को समझना जरूरी है ताकि कम से कम आप अपनी गाढ़ी बचत न जला बैठें.

संयोग है कि बाजार के रंगों को परखने वाले ही नहीं बल्कि रिजर्व बैंक ने भी (फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2020) अधिकृत तौर पर इस बात पर बेचैनी जाहिर की है कि आखिर बीते एक माह में सेंसेक्स 3000 अंक कैसे कूद गया जबकि आने वाला हर आकलन यह बता रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर इस पूरे साल में शून्य से 10 फीसद नीचे तक टूट सकती है.

वित्तीय बाजार अक्सर अति आशावाद का शिकार हो कर मौके के मीरी को हकीकत मान लेते हैं. कुछ तथ्य हमें सतर्क करते हैं:

● आमतौर पर बॉन्ड, गोल्ड और शेयर मार्केट एक साथ नहीं दौड़ते. शेयरों में तेजी के वक्त पैसा बॉन्ड बाजार से निकल कर शेयरों में जाता है क्योंकि तत्काल फायदे की उम्मीद होती है लेकिन इस समय आर्थिक अनिश्चतताओं के बीच जब पूंजी बॉन्ड बाजार में लग रही है. (बॉन्ड की यील्ड कम है यानी ग्राहक खूब हैं) संकट में चमकने वाला सोना भी बढ़ रहा है तो फिर शेयरों में पैसा कौन लगा रहा है?

● लॉकडाउन के बाद कंपनियों के नतीजों की हालत देखते ही बनती है. कभी भी घाटा न उठाने वाली तेल कंपनियां तक एक तिमाही में 40 फीसद का नुक्सान दर्ज कर रही हैं. दरअसल, बाजार में सूचीबद्ध करीब 1,640 प्रमुख कंपनियों (बैंक व एनबीएफसी के अलावा) के मुनाफे बीते बरस की चौथी तिमाही में करीब 10.2 फीसद गिरे. यह गिरावट कॉर्पोरेट टैक्स में कमी के बावजूद हुई. नए वित्त वर्ष (2020-21) की दो तिमाही पूरी तरह डूबने के बाद बाजार में बड़ी सतर्कता जरूरी है.

● मंदी के कारण कंपनियों के मुनाफे ही नहीं गिरे बल्कि उनके कर्ज देनदारी की भी थम गई. कंपनियों ने बड़े पैमाने कर्ज भुगतान टालने का विकल्प चुना. इससे उनकी साख पर गहरा असर पड़ा है. रिजर्व बैंक ने कंपनियों के खातों को परख कर बताया है कि ज्यादातर कर्जदारों की साख टूट (डबल ए से नीचे) रही है. इसके बाद भी किसका पैसा बाजार में लग रहा है.

● रिलायंस के बाद भारतीय शेयर बाजारों की जान भारत के बैंकिंग उद्योग में बसती है. आत्मनिर्भरता के तमाम मृदंग वादन के बावजूद बैंकों की कर्ज देने की रफ्तार अब तक केवल तीन फीसद रही है जो पिछले दशकों की न्यूनतम है. कोविड लॉकडाउन के बाद कर्ज का भुगतान टालने से बैंकों के पैर लड़खड़ा गए हैं. वहां संकट के बल्ब जल रहे हैं.

● जून में इक्विटी म्युचुअल फंड 95 फीसद कम हुआ यानी कि छोटे निवेशकों की पूंजी भी बाजार से निकल रही है. डेट फंड में तो संकट पहले से ही है.

● अर्थव्यवस्था में मांग की वापसी के दूर-दूर तक कोई सबूत नहीं हैं और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में गहरी अनिश्चतिता है. इसलिए रिजर्व बैंक को भी यह मंदी लंबी चलने का खतरा नजर आ रहा है.

इस समय भारतीय बाजार में तेजी चुनिंदा शेयरों में सीमित है, जो छोटे निवेशकों को भरमाए रखने के लिए है. रिजर्व को डर है यह बाजी पलट सकती है. सनद रहे कि जानवर बनना आदमी का पुराना शौक है. इसीलिए वित्तीय बाजार दुनिया की सबसे दिलचस्प जगह हैं. यहां पूरी भीड़ का दिमाग शहद वाली मक्खियों की तरह एक तरफ दौड़ पड़ता (स्वार्म इंटेलिजेंस) है, यानी कभी पालकी को उठाने की होड़ तो कभी पटकने की प्रतिस्पर्धा.

बाजार में रोज कुछ 'लकी फूल' होते है, बकौल नसीम तालेब (किताब-फूल्ड बाइ रैंडमनेस) इनको होने वाले 99 फीसद मुनाफे केवल मौके का नतीजा हो सकते हैं. लेकिन वे कारोबारी इसे अक्सर अपनी सफल रणनीति समझ लेते हैं और कइयों को चिपका देते हैं यानी उनकी नकल करते हुए असंख्य लोग मौके के मीर बनने की कोशिश करते हैं. इसलिए सतर्क रहिए क्योंकि इस मंदी के बीच, आप अपनी गाढ़ी बचत के साथ एक बार लकी (भाग्यशाली) और सौ बार (फूल) ठगे जाना झेल नहीं पाएंगे.

@anshuman1tiwari

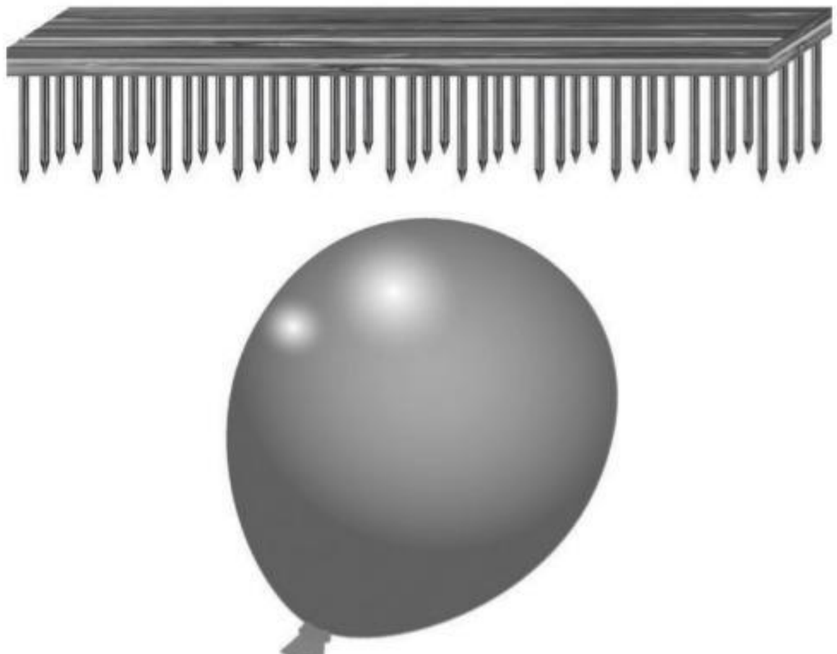

अर्थव्यवस्था डूब रही है और शेयर बाजार बढ़ रहे हैं. कितना बड़ा है यह खतरा?

इलस्ट्रेशनः असित रॉय

www.readwhere.com

खास रपट

अयोध्या

राम के नाम अयोध्या का ‘नवनिर्माण’

राम मंदिर के साथ-साथ अयोध्या का हिंदू धार्मिक पर्यटन के केंद्रबिंदु के तौर पर पुनर्निर्माण करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं

आशीष मिश्र

फोटोः मनीष अग्निहोत्री

www.readwhere.com

पीआइबी

पानी अभी उतरा नहीं
अयोध्या में राम की पैड़ी घाट; (इनसेट) हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ

अयोध्या के निवासियों में 5 अगस्त को गजब का उत्साह दिखाई दे रहा था. इस उत्साह में महामारी के कारण वांछित सामाजिक दूरी की बंदिशें उन्हें रोक नहीं पाईं और शाम को पौराणिक राम की पैड़ी घाट पर अयोध्यावासी भारी संख्या में जुटे. वहां, उन्होंने राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत को स्मरणीय बनाने के लिए 'दीपोत्सव' मनाया और करीब 3,50,000 दीप प्रज्वलित किए.

आखिरकार, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन में भूमि पूजन करने और राम मंदिर के लिए आधारशिला रखने के बाद कहा, ''भारत के इतिहास में एक नया अध्याय'' जो शुरू हो रहा था. इस अवसर पर शुद्ध चांदी की 22.6 किलोग्राम ईंट का उपयोग किया गया. महामारी के कारण पैदा हुई बाधाओं का प्रभाव इस आयोजन में भी दिखाई दे रहा था. प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ चार अन्य लोगों—आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपालदास, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही मंच साझा किया. बताया गया कि केवल 175 लोगों को समारोह के लिए आमंत्रित किया गया था, उनमें से कई आध्यात्मिक नेता और ऐसे अन्य लोग थे जो राम मंदिर आंदोलन से शुरू से ही जुड़े हुए थे. हालांकि आंदोलन के कुछ उल्लेखनीय चेहरे नदारद थे.

मोदी राम जन्मभूमि स्थल और अयोध्या के सबसे पुराने हनुमानगढ़ी मंदिर का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री भी बन गए. उन्होंने पूजा से पहले पारिजात का एक पौधा भी लगाया. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे मुक्ति का दिन बताया और इसकी तुलना 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस के साथ करते हुए कहा कि राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा क्योंकि यह नगरी दुनियाभर के लोगों को आकर्षित करती है.

और ऐसा हो सकता है अगर अयोध्या को इक्ष्वाकु वंश की पौराणिक नगरी के रूप में विकसित करने की आदित्यनाथ

www.readwhere.com

सरकार की योजना साकार हो जाती है. केंद्र और राज्य सरकार की 5,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं पहले से ही चल रही हैं (देखें बॉक्स: अयोध्या के पर्यटन पर जोर). राज्य के संस्कृति और पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार कहते हैं, ''अयोध्या में नवनिर्माण कार्य वर्षों से रुका हुआ था क्योंकि राम जन्मभूमि का विवाद अदालत में लंबित था. इसके कारण स्थायी प्रकृति का कोई भी कार्य नहीं हो सका था. अब, अयोध्या को एक नए इक्ष्वाकु नगर के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है और उसकी के अनुरूप एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है. पर्यटन और संस्कृति विभाग इसमें विशेष योगदान दे रहे हैं ताकि इसके सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व को उजागर किया जा सके.''

इसके संकेत पहले से ही, लखनऊ-गोरखपुर राजमार्ग एनएच-28 पर दिखने लगे हैं. 'अयोध्या कट' से बाईं ओर मुड़ने पर सरयू नदी तट की ओर लेकर जाने वाली 2.5 किमी लंबी सड़क का कायाकल्प हो चुका है. यह सड़क रामकथा पार्क, अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय, कोरिया पार्क, नया घाट और चौधरी चरण सिंह घाट से होकर गुजरती है. इसका अंतिम पड़ाव धनुषाकार भजन संध्या स्थली है. यह ओपन एयर थिएटर, जिसमें 5,000 लोग बैठ सकते हैं, भविष्य में अयोध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा. सड़क के दूसरी तरफ राम की पैड़ी घाट है जिसे बहुत से लोग अयोध्या की पहचान कहते हैं. निर्बाध जल आपूर्ति की परियोजना इसी साल मार्च में पूरी हुई और यह बहुत भव्य दिखती है. यह अब एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बन गया है.

अगर सब कुछ योजनानुसार चला तो अयोध्या का नवनिर्माण और राम मंदिर, दोनों बड़े कार्य एक साथ पूरे हो जाएंगे. जितेंद्र कुमार कहते हैं, ''जब लोग नए इक्ष्वाकु नगर में प्रवेश करेंगे तो उन्हें ऐसा महसूस होना चाहिए कि वे भगवान राम की नगरी में आए हैं.'' इस नए आध्यात्मिक शहर का एक किनारा प्रसिद्ध गुप्तार घाट होगा. ऐसा माना जाता है कि राम ने अपने भाइयों के साथ सरयू के तट पर इसी घाट पर जल समाधि ली थी. घाट पर पूजा कराने वाले पंडित रमेश पांडे कहते हैं, ''उत्तर प्रदेश में सरयू उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन गुप्तार घाट की स्थिति ऐसी है कि यहां से यह नदी उत्तरवाहिनी हो जाती है. इसलिए यहां यह दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है. यही कारण है कि गुप्तार घाट को अयोध्या का मस्तक कहा जाता है.''

इसके पौराणिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, गुप्तार घाट से राम जन्मभूमि तक के 1,800 एकड़ क्षेत्र को इक्ष्वाकु नगर के रूप में विकसित किया जाएगा. मास्टर प्लान के अनुसार, 5 किमी लंबे नदीतट को इस तरह से बनाया जाएगा कि राम मंदिर इन घाटों से दिखाई दे. नया बसने वाला शहर भी वैदिक ज्ञान का एक केंद्र बन जाएगा—एक वैदिक विश्वविद्यालय और एक शोध संस्थान यहां स्थापित किए जाएंगे.

पुरानी अयोध्या की भी अनदेखी नहीं की जा रही है. शहर के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए योजनाएं बनाई गई हैं. जितेंद्र कुमार कहते हैं, ''अयोध्या केवल हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान नहीं है. यहां सिखों के भी कई पवित्र स्थल हैं, जिनमें गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड साहेब, गुरुनानक गोविंद धाम और गुरुद्वारा गुरुसिंह सभा शामिल हैं जिसे देशभर में गुरुनानकपुरा के नाम से जाना जाता है. जैन धर्म के अनुयायियों के लिए, अयोध्या उनके 24 तीर्थंकरों में से पांच तीर्थंकरों का जन्मस्थान है. अयोध्या की इन सभी तीर्थ स्थलों के विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जा रही है.''

आने वाले वर्षों में पर्यटकों की आमद की उम्मीद में, सरकार तीन पांच सितारा होटल, तीन से 10 तीन सितारा होटल और 20-30 ऐसी सुविधाओं का निर्माण करने का प्रस्ताव कर रही है, जहां करीब 10,000 लोगों को ठहराया जा सकता है. 2017 से, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या में दिवाली समारोह—'दीपोत्सव'—के आयोजन ने 'राम नगरी' को देश और विदेश में एक विशिष्ट पहचान दी है. सरकारी आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं. 2019 में यहां 2.1 करोड़ पर्यटक आए. लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के कारण इस साल सन्नाटा छाया रहा. अयोध्या में पर्यटन विभाग के एक अधिकारी का कहना है, ''बड़ी गिरावट आई है, जुलाई के अंत तक यहां 50 लाख से भी कम पर्यटक आए.'' विभाग को उम्मीद है कि वायरस के प्रकोप से मुक्ति के बाद चीजें बेहतर होंगी.

इन सभी विकास कार्यों के बीच, अयोध्या प्रशासन के लिए सरयू नदी को साफ रखना एक बड़ी चुनौती है. कुल आठ नाले नदी में गिरते हैं. उन्हें राम घाट पर 12 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से सीधे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. 363 करोड़ रुपए की लागत से

अयोध्या के पर्यटन पर जोर

↘ राम की मूर्ति

भगवान राम की 251 मीटर ऊंची मूर्ति के लिए **1,000 करोड़ रुपए,** जो ''दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति'' होगी; इसके लिए 84 हेक्टेयर भूमि अयोध्या में माझा बरहटा में अलग रखी जा रही है. योजना है कि तीन साल में राम मंदिर निर्माण पूरा होने पर मूर्ति को स्थापित किया जाएगा

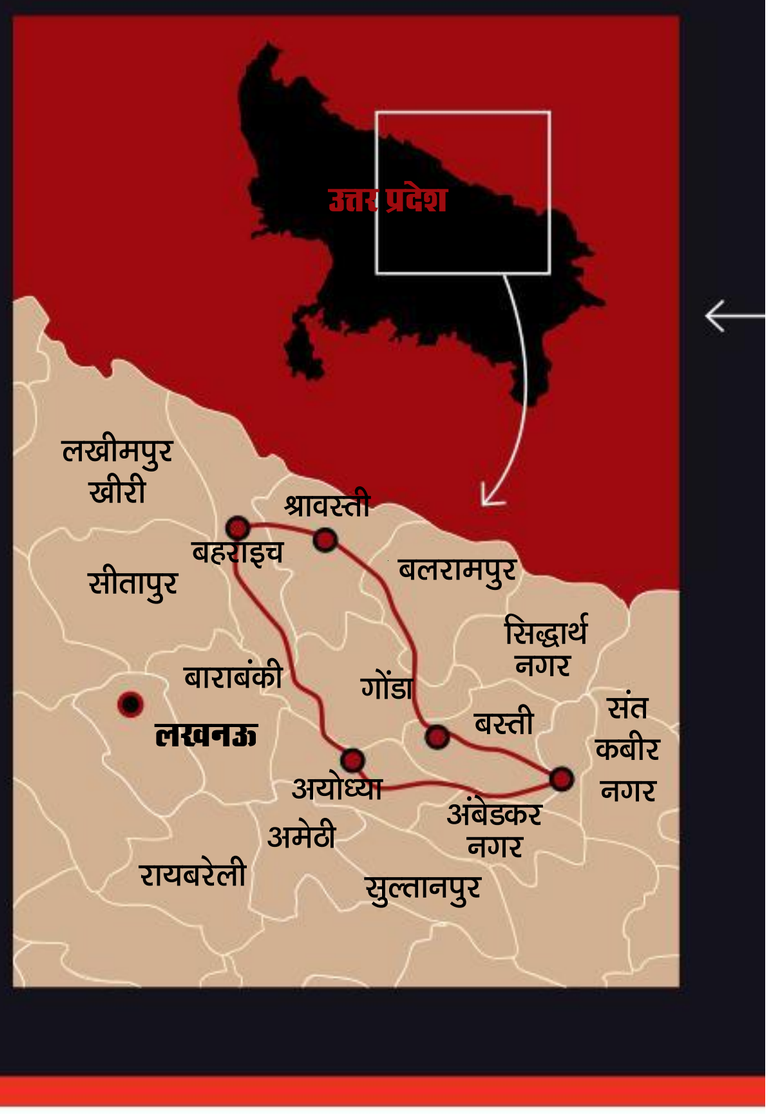

''जब लोग नए इक्ष्वाकु नगर में प्रवेश करेंगे तो उन्हें ऐसा महसूस होना चाहिए कि वे भगवान राम की नगरी में आए हैं.''

—जितेंद्र कुमार
प्रमुख सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग

www.readwhere.com

सभी फोटोः मनीष अग्निहोत्री

↘ अयोध्या शोध संस्थान

संस्थान का रिकॉर्ड **17 करोड़ रुपए** की लागत से डिजिटाइज किया जाएगा. एक रामलीला अकादमी की भी योजना है जहां छात्रों को लोक कला का प्रशिक्षण दिया जाएगा

↘ परिक्रमा परियोजना

अयोध्या में चार तरह की परिक्रमा हैं: रामकोट परिक्रमा, 5 कोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा और 84 कोसी परिक्रमा. इन परिक्रमा के मार्ग में हर 10 किमी पर पर्यटन विभाग के सुविधा केंद्र बनेंगे. इसके लिए **20 करोड़ रुपए** अलग रख दिए गए हैं

↘ परिक्रमा मार्ग

3,000 करोड़ रुपए की लागत से 275 किमी लंबे 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का नवीनीकरण किया जाएगा. चित्रकूट जाने वाले हाइवे से इसे जोड़ा जाएगा. यह परियोजना 2023 तक पूरी होनी है

↘ अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय

अयोध्या बाइपास पर अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में रामायण की थीम पर एक नए प्रेक्षागृह का निर्माण किया जाएगा. वहां ऑडियो-विजुअल वर्णन, एक डिजिटल रामायण गैलरी आदि की योजना बनाई गई है

↘ रामलला हवाई अड्डा

500 करोड़ रुपए की लागत से अवध विश्वविद्यालय के पास स्थित हवाई पट्टी को नागरिक हवाई अड्डे के तौर पर विकसित किया जाएगा; इसके लिए 102 हेक्टेयर भूमि का इंतजाम हुआ है

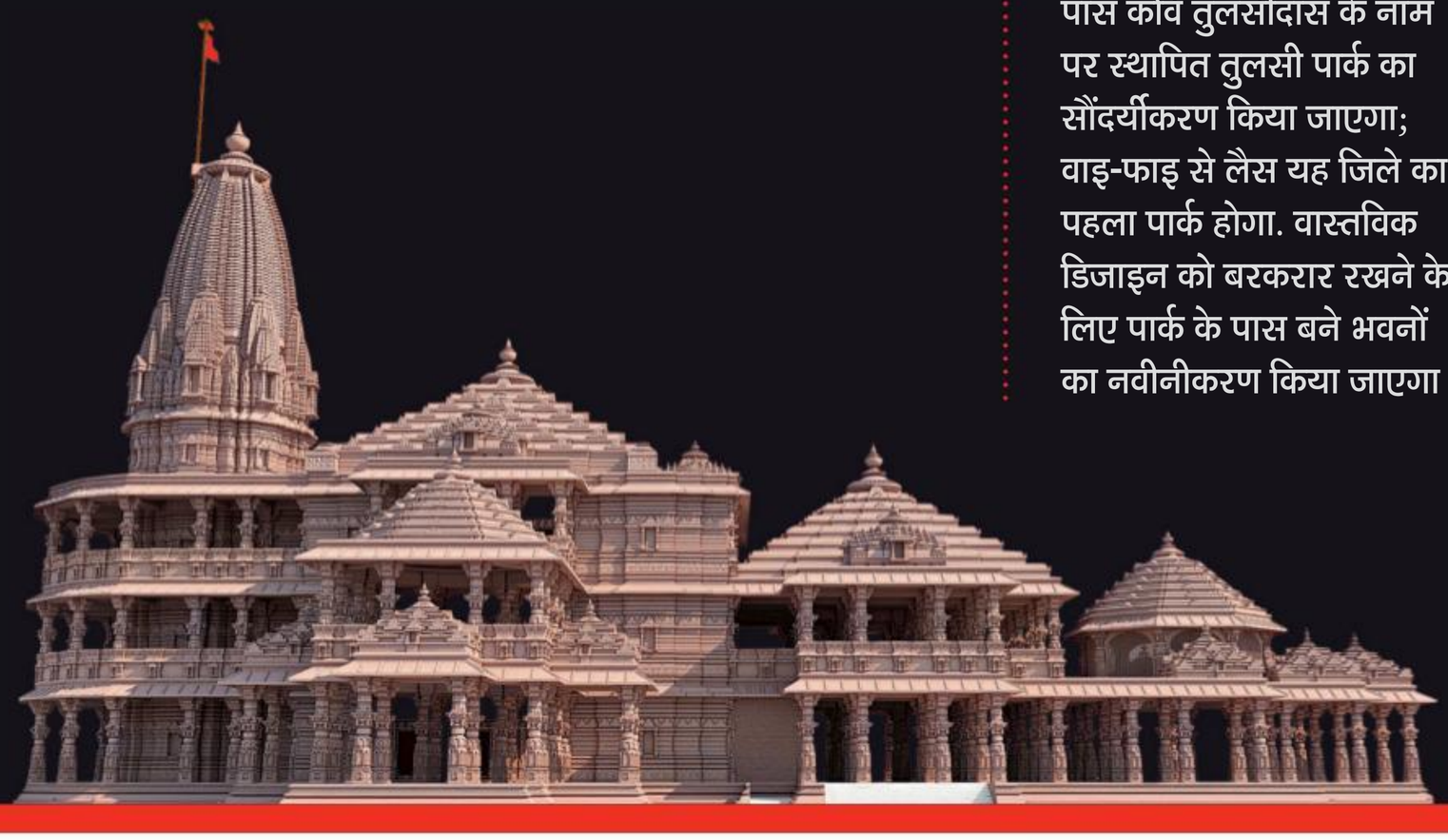

↘ भजन संध्यास्थल

सरयू नदी के तट पर खुले सभागार के निर्माण का कार्य आखिरी चरण में है

↘ कोरिया पार्क

कोरिया की राजकुमारी क्वीन हो की याद में सरयू के तट पर बने पार्क का विस्तार किया जा रहा है. 2.5 एकड़ पर **25 करोड़ रुपए** की लागत से बनने वाला यह पार्क भारत-कोरिया के संबंधों का स्मारक होगा

↘ परिवहन

एनएच-28 पर एक नया बस स्टैंड अयोध्या 'तीर्थ यात्रा सर्किट' का हिस्सा होगा. 'रामनगरी' अयोध्या रेलवे स्टेशन को दोबारा डिजाइन करने के लिए **104 करोड़ रुपए** आवंटित किए गए हैं

अंकित रंजन

↘ तुलसी उद्यान

अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पास कवि तुलसीदास के नाम पर स्थापित तुलसी पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा; वाइ-फाइ से लैस यह जिले का पहला पार्क होगा. वास्तविक डिजाइन को बरकरार रखने के लिए पार्क के पास बने भवनों का नवीनीकरण किया जाएगा

बनाया जा रहा 32 एमलएलडी क्षमता के एक नए संयंत्र का निर्माण कार्य भी अपने अंतिम चरण में है. अयोध्या में पाइपलाइन से पेयजल की उपलब्धता भी एक बहुत बड़ी समस्या है. पिछले दो वर्षों में, करीब 8,000 घरों को पाइपलाइनों से जोड़ा गया है. अयोध्या के महापौर हृषिकेश उपाध्याय कहते हैं, ''निगम अगले दो वर्षों में अयोध्या में हर घर को पाइपलाइन से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ काम कर रहा है.''

अयोध्या जिला पहले दो प्रशासनिक प्रभागों, फैजाबाद और अयोध्या नगर पालिका परिषद में विभाजित था. 9 मई, 2017 को इन दोनों नगर पालिका परिषदों को मिलाकर अयोध्या नगर निगम बनाया गया था. उपाध्याय का कहना है कि बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के लिए उन्हें भविष्य में और जमीन की जरूरत होगी. इसे ध्यान में रखते हुए, निगम शहर की सीमाओं का विस्तार कर रहा है. मेयर बताते हैं, ''41 राजस्व गांवों को शामिल करने के प्रयास जारी हैं. उनके समावेश के साथ, शहर में 35 वर्ग किमी का अतिरिक्त क्षेत्र शामिल हो जाएगा; अयोध्या शहर 90 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा.'' यह एक स्मार्ट शहर होगा जिसमें 14 करोड़ रुपए की एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली होगी.

जाहिर है, नए इक्ष्वाकु नगर का खाका तैयार हो चुका है. ऐसे में क्या नई राम नगरी पुराने जख्मों पर मरहम लगाएगी और क्या यह शहर अपने सभी नागरिकों का पूरा ख्याल रखेगा? कुछ लोगों को इन भव्य योजनाओं की सफलता पर संदेह है, लेकिन जैसा कि अयोध्या के पुराने निवासी और साकेत महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य वी.एन. अरोड़ा कहते हैं, ''अयोध्या के निवासियों ने पिछले 50 वर्षों में केवल विध्वंस और तनाव ही देखा है. अब, पहली बार, वे यहां निर्माण और विकास देखेंगे.'' उम्मीद की ये किरणें बहुत मायने रखती हैं. ■

www.readwhere.com

CELEBRATING 26 YEARS
OF EDUCATIONAL EXCELLENCE

IPS ACADEMY

THE KNOWLEDGE KINGDOM

www.ipsacademy.org

From i to identity

The change we bring in every student

UGC AUTONOMOUS ENGINEERING INSTITUTE

First self-financing institute in MP

NBA ACCREDITED
Engineering UG Programs

NAAC ACCREDITED ACADEMY

nirf

Management
Ranking amongst
top 100 institutes of India

FOR 4 CONSECUTIVE YEARS
2017-2018-2019-2020

Providing
71 Courses
to select from

Spread over
58 Acre
campus area

Unmatched
Placements
with separate training & skill development department

Latest
Technologies
to learn from
(Online & Offline)

Support of
Huge Alumni
placed globally

www.readwhere.com

ADMISSIONS OPEN

Guidance & Counselling 2020-21

Contact M: 92294 98055, 99778 35161 Landline:0731 4014578 Email: admission@ipsacademy.org

B.Sc. (CS/Elex/PCM/Biot/LS),
M.Sc. (Biot/Microbio/ Phy/ Maths/ Chem/ Pharm Chem) Call: 9424573311, 9826670227
B.Lib. Call: 9977042814

BFA, **MFA**
Call: 9826091445

BALLB (Hons), **BBALLB** (Hons),
LLB (Hons), **LLM**
Call: 9926926161, 9575027525

BA (Mass Comm) Call: 8989898802

B.Ed Call: 9907307160

B.Com (Hons/Plain/CA/Tax/FT), **M.Com**
Call: 9131278889, 6232626261

BA (Tourism), **MSW**
Call: 92005 80032

B. Design (Fashion),
PG Dip. in Fashion Design
Call: 9826560056

BPA (Vocal, Instrumental & Dance),
MPA, **Certificate Course in Drama & Theatre** Call: 9981030074

Institute of Engineering & Science

B.Tech. (CS/CS&IT/EC/Elect & Elex/Fire Tech & Safety/ Civil/Chem/Mech/Comp. Sc. & Engg.(Data Science)/Comp. Sc. & Engg.(IOT), **M.E.** (CS / EC), **M.Tech.** (Chem/ C & P Mgmt./ Ind. Safety/ Power Elex./ Struc. Engg./ Robotics) Call: 7746000161, 9826079161

Institute of Business Management & Research

BBA (Plain /FT/Hospital Administration/HM), **BA** (Economics Hons.),
MBA (Core/ BE/IB/FA/MM), **Ph.D** (Management/ Economics)
Call: 9755545648, 9111009161

College of Pharmacy

B.Pharm., M.Pharm
(Pharmaceutics/Pharmacology/ Quality Assurance) Call: 9907586213

School of Computers

BCA, **MCA**
Call: 8085224628, 9926999261

Institute of Hotel Management

Bachelor of Hotel Management,
BBA (Hotel Management)
Call: 9575854161, 9039503035

School of Architecture

B.Arch, M.Arch
Call: 8871449049

IPS ACADEMY
THE KNOWLEDGE KINGDOM

IPS ACADEMY, Knowledge Village, Rajendra Nagar, Indore.

Approved by UGC, AICTE, COA, NCTE, PCI, M.P. Govt. & Affiliated to DAVV Indore, RGPV Bhopal, RMTSAVV Gwalior, MCRPV Bhopal Universities.

Antic

www.readwhere.com

संवैधानिक रस्साकशी

दलबदल के चलते बनती-बिगड़ती राज्य सरकारों के बीच राज्यपाल और स्पीकर की भूमिका पर सदन से लेकर अदालत तक राजनैतिक दलों की खींचतान संविधान की कसौटी पर कहां टिकती है

मनीष दीक्षित

एएनआइ

महामहिम और माननीय
14 जुलाई को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को हटाने की जानकारी देते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

बीते छह सालों में बिहार और मणिपुर को भी शामिल कर लें तो आठ राज्यों में राजनैतिक उठापटक के बाद भाजपा की अकेले या सहयोगी दलों के साथ सरकारें बनीं. जोड़तोड़ की सरकारें बनीं तो दलबदल भी हुआ. सरकार बनाने-गिराने की प्रक्रिया में राज्यपालों और स्पीकर की भूमिका पर भी सवाल उठे. हाल के राजस्थान का है जहां चीफ व्हिप की शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके वफादार विधायकों को दलबदल कानून के तहत नोटिस जारी कर दिया, जिसे विधायकों ने अदालत में चुनौती दे दी. दूसरी ओर, सरकार ने राज्यपाल से फौरन विधानसभा सत्र बुलाने को कहा तो राज्यपाल ने सत्र का एजेंडा पूछ लिया. सरकार का कहना है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की राय पर सत्र बुलाने का प्रावधान संविधान में है. हालांकि इस पर विधि विशेषज्ञों की राय कुछ और है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था एकदम स्पष्ट है.

राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियां होती हैं. राज्य सरकार के अल्पमत में होने पर राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है. वर्ष 2015 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा ने विधानसभा सत्र तय तारीख (14 जनवरी 2016) से एक महीने पहले बुला लिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि मुख्यमंत्री नबाम तुकी बहुमत खो चुके हैं. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. इस पर संविधान पीठ के मुख्य फैसले में जस्टिस जे.एस. खेहर ने स्पष्ट रूप से कहा, ''राज्यपाल केवल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर सत्र बुला सकता है और इसका समापन कर सकता है. न कि अपनी मर्जी से वह ऐसा कर सकता है.'' इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ इस तथ्य से कि कुछ विधायक दलबदल कर रहे हैं, सरकार अल्पमत में नहीं आ जाती. अगर राज्यपाल को लगता है कि सरकार अल्पमत में आ गई है तो उसे सदन के भीतर बहुमत परीक्षण के लिए कह सकता है.

लेकिन राजस्थान के ताजा मामले में विधायक दल की बैठक सदन के बाहर हुई और यहां पर विधायकों के अनुपस्थित रहने पर उन्हें स्पीकर ने व्हिप की शिकायत पर नोटिस जारी किया. इस पर राजस्थान हाइकोर्ट के सीनियर एडवोकेट आर.एन. माथुर कहते हैं, ''सदन के बाहर हुई बैठक के लिए व्हिप जारी नहीं हो सकता. विधानसभा से संबंधित या सदन के भीतर की कार्यवाही के लिए व्हिप जारी हो सकता है लेकिन इसके बाहर की गतिविधियों के लिए ऐसा करना सदस्यों की स्वतंत्रता और बोलने की आजादी बाधित करने जैसा है.'' उनका कहना है कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 एक बंद मुट्ठी है. यदि कहीं भी कोई गैर कानूनी कार्य हो रहा हो या कार्य कानून सम्मत न हो तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के के तहत हाइकोर्ट में याचिका डाली जा सकती है. ऐसे मामलों में कोर्ट विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को रद्द कर सकता है. हालांकि स्पीकर

www.readwhere.com

बातचीत **सुभाष कश्यप**

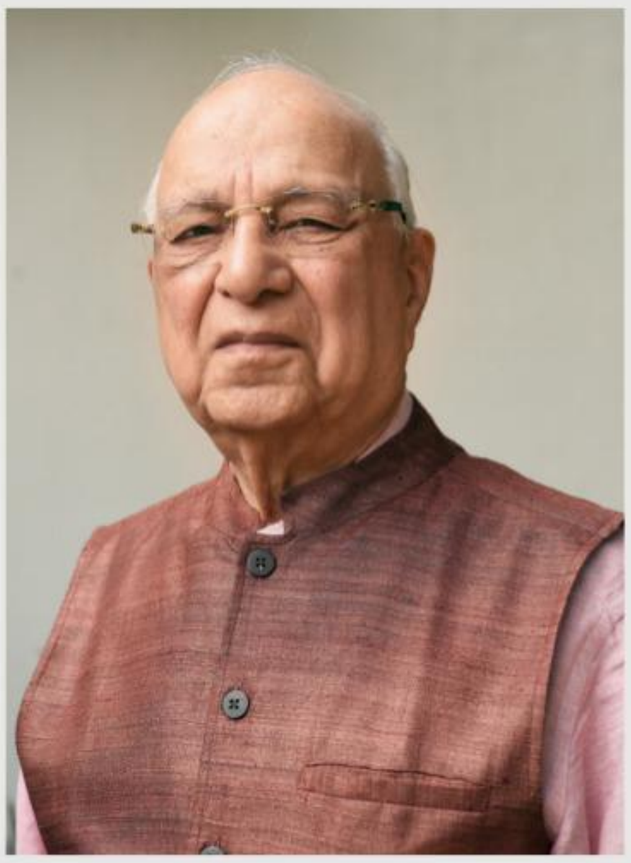

सत्यम् कुमार

‘सत्र बुलाने का अधिकार केवल गवर्नर को है’

राजस्थान के हाल के राजनैतिक घटनाक्रम और उसमें राज्यपाल और स्पीकर की भूमिका के संदर्भ में दिग्गज संविधान विशेषज्ञ **सुभाष कश्यप** *से इंडिया टुडे के असिस्टेंट एडिटर* **मनीष दीक्षित** *ने बात की. प्रस्तुत हैं इसके कुछ अंशः*

● विधायक दल की बैठक सदन के बाहर होती है तो व्हिप लागू होता है?

नहीं, बिल्कुल नहीं.

● सदन के बाहर हुई विधायक दल की बैठक के बाद व्हिप की शिकायत पर स्पीकर का विधायकों को नोटिस जारी करना ठीक है?

ये नोटिस की भाषा पर निर्भर है. अगर उन्होंने ऐसी भाषा का उपयोग किया कि विधायक दल की बैठक में वे नहीं आए तो ये स्वीकार्य नहीं होगा. संविधान में दलबदल कानून में अगर पार्टी के निर्देश के खिलाफ सदन में वोट करें या वोटिंग से अलग रहें तो आपके खिलाफ दलबदल कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है. दूसरा स्वेच्छा से दल की सदस्यता त्याग दें तो हो सकती है. नोटिस सिर्फ एक सूचना है, दोषी मानना नहीं है. उनका जवाब आने के बाद स्पीकर कार्रवाई कर सकते हैं.

● स्पीकर अनंत काल तक दलबदल के तहत कार्रवाई पर फैसला रोक सकता है?

ये संविधान का ग्रे एरिया है. ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें स्पीकर ने दो-दो, तीन-तीन साल तक कार्रवाई नहीं की. ऐसे में हाइकोर्ट में अर्जी दाखिल की जा सकती है. अदालत स्पीकर को जल्दी फैसला लेने के लिए कह सकती है.

● पाला बदलने वाले विधायक चाहते हैं कि खुद इस्तीफा दें, उन पर दलबदल की कार्रवाई न हो, क्यों?

अगर दलबदल में दोषी पाए जाएंगे तो सदस्यता ही चली जाएगी, मंत्री रहने का प्रश्न ही नहीं है. गैर सदस्य के मंत्री बनकर छह महीने में चुनाव जीतने वाला प्रावधान भी इन पर लागू नहीं होगा. जो सदस्यता से ही अयोग्य है वह मंत्री नहीं बन सकता. वह दोबारा चुनाव लड़कर जीतकर आए तब बन सकता है.

● राज्यपाल क्या स्वतंत्र रूप से विधानसभा सत्र बुला सकता है?

सत्र बुलाने का अधिकार केवल राज्यपाल को ही है. लेकिन सामान्यतया वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर सत्र बुलाता है. संविधान के अनुच्छेद 163 में स्पष्ट है कि अगर वह अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करता है तो इस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता. इस अनुच्छेद में यह भी स्पष्ट है कि वह किन मामलों में विवेकाधिकार का इस्तेमाल करेगा, इसका फैसला वह खुद करेगा. यह न्यायिक समीक्षा से परे होगा.

● राजस्थान में सीएम ने सत्र बुलाने की तारीख की सिफारिश की लेकिन राज्यपाल ने इसे नहीं माना. यह असंवैधानिक है?

> “यह अकादमिक बहस का विषय बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या उन लोगों पर भी बाध्यकारी हैं जो संविधान की शपथ लेकर पदभार ग्रहण कर चुके हैं”

राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकता है. संविधान के अनुच्छेद 175 के तहत उसे यह भी अधिकार है कि वह किसी भी मामले में सदन को संदेश दे. उसके संदेश का समुचित सम्मान करना होगा. वह कह सकता है कि इस मामले को बाद में देखा जाएगा.

● विश्वासमत हासिल करने की कोई समयसीमा नहीं है. कई बार अदालतों ने समयसीमा तय की है. यह ठीक है?

राज्यपाल ही फ्लोरटेस्ट के लिए कहेगा. संविधान में इसकी कोई समयसीमा नहीं दी गई है. अदालतों ने अपनी सीमा लांघकर कई मामलों में समयसीमा तय की है. यह हमेशा से बहस का विषय रहा है. सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम नहीं है, संविधान सुप्रीम है. संविधान के अनुच्छेद 141 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले निचली अदालतों पर बाध्यकारी हैं. लेकिन यह अकादमिक बहस का विषय बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या उन लोगों पर भी बाध्यकारी हैं जो संविधान की शपथ लेकर पदभार ग्रहण कर चुके हैं.

● हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का क्या तरीका हो सकता है?

मोटे तौर पर 1963 के बाद दलबदल शुरू हआ. आंकड़ों की अगर बात करें तो दलबदल कानून आने यानी 1986 से 20 साल पहले के मुकाबले कानून लागू होने के बाद दलबदल अपेक्षाकृत कई गुना बढ़ गया. इसे कानून से नहीं बल्कि व्यवस्था में सुधार से ही रोका जा सकता है. इस पर मेरी एक किताब भी है.

● राजनैतिक दलों के लिए कानून कम हैं क्या?

राजनैतिक दलों के लिए कोई कानून नहीं है. ये किसी कानून में नहीं आते. समाज के लिए कानून है, कंपनियों के लिए कानून है लेकिन इनके लिए नहीं है. हाल ही में आयकर कानून के दायरे में इन्हें लाया गया है. इससे पहले ये सिर्फ चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराती रही हैं बतौर राष्ट्रीय या राज्य पार्टी. सिस्टमिक रिफॉर्म की जरूरत है. पार्टियों को नियंत्रित करने के लिए कानून की जरूरत है. खासतौर पर उनके वित्त का ऑडिट होना चाहिए कि पैसा उनके पास कहां से आया और ये कैसे खर्च किया गया? चुनाव के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत होती है? ये कहां से आता है? जाहिर है यह भ्रष्टाचार और अपराध के जरिए आता है. इसे रोकना होगा. ■

www.readwhere.com

फ्लोर टेस्ट के लिए कितना समय

(पिछले छह वर्षों के आंकड़े)

उत्तराखंड

10 दिन—मार्च 2016

हरीश रावत सरकार को कांग्रेस के 9 विधायकों की बगावत के बाद 19 मार्च को राज्यपाल ने 28 मार्च तक बहुमत साबित करने को कहा यानी 10 दिन का वक्त दिया. लेकिन इससे पहले वहां राष्ट्रपति शासन लग गया जिसे हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया और मई में बहुतम परीक्षण में पास होने के बाद सरकार बहाल हो गई.

अरुणाचल प्रदेश

48 घंटे—जुलाई 2016

सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई को कांग्रेस की नबाम तुकी सरकार को बहाल करने का आदेश दिया. इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से 16 जुलाई तक बहुतम साबित करने को कहा. तुकी ने फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले यहां राष्ट्रपति शासन लगा था क्योंकि सत्तारुढ़ कांग्रेस के विधायकों ने बगावत कर दी थी.

गोवा

15 दिन—मार्च 2017

विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी लेकिन इस बीच तत्कालीन केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर ने बहुमत का दावा करने का पत्र राज्यपाल को भेजा. राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाते हुए 15 दिन का समय बहुमत साबित करने के लिए दिया. पर्रीकर ने इससे पहले ही बहुमत साबित कर दिया.

कर्नाटक

15 दिन—मई 2018

विधानसभा चुनाव में खंडित जनादेश आया और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी. बी.एस. येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाकर राज्यपाल ने 15 दिन का समय बहुमत साबित करने के लिए दिया. लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे घटाकर 24 घंटे कर दिया. जुलाई 2019 में चलते सत्र के दौरान 15 विधायकों के इस्तीफा देने से एच.डी. कुमारस्वामी की गठबंधन वाली सरकार अल्पमत में आई. तब इस्तीफे पर फैसला स्पीकर ने लटकाकर रखा था और उन पर अयोग्यता की कार्रवाई शुरू हो रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस्तीफे पर फैसले के लिए स्पीकर स्वतंत्र हैं, लेकिन विधायकों को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता (यानी बागी विधायक पार्टी व्हिप से मुक्त हो गए थे). सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन विश्वासमत परीक्षण होना था.

मध्य प्रदेश

1 दिन—मार्च 2020

कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद उनके वफादार विधायकों-मंत्रियों ने पद से त्यागपत्र दे दिया और मुख्यमंत्री कमलनाथ की कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई. राज्यपाल ने एक दिन के भीतर बहुमत साबित करने को कहा लेकिन स्पीकर ने कोरोना का हवाला देते हुए 16 मार्च को सदन 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन का वक्त देते हुए बहुमत परीक्षण कराने को कहा पर इससे पहले ही सीएम ने इस्तीफा दे दिया.

को निर्देश देने में न्यायालय की कुछ सीमाएं हैं.

माथुर के मुताबिक, विधानसभा प्रक्रिया के नियमों के मुताबिक, विधानसभा का सत्र आहूत करने पर स्पीकर 21 दिन का नोटिस प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे. और वह प्रत्येक सदस्य तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचेगा. यदि कम समय में सत्र बुलाना है तो नोटिस भेजने की व्यवस्था करना स्पीकर का काम है. राज्यपाल सत्र दो दिन में आहूत करने की वजह सरकार से पूछ सकते हैं. राजस्थान में सरकार के बहुमत को न तो चुनौती दी गई थी और न ही कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था इसलिए विश्वास मत हासिल करने का भी सवाल नहीं उठता.

मंत्रिपरिषद जो भी सलाह राज्यपाल को दे वह कानून सम्मत, स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए. (राजस्थान के मामले में मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार की तरफ से सत्र जल्द आहूत करने की स्पष्ट वजह राज्यपाल को भेजे नोट में नहीं लिखी गई). विश्वासमत के मामले में जब स्पीकर की भूमिका बहुत अच्छी नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट अपना पर्यवेक्षक भी भेज सकता है. माथुर कहते हैं, राज्यपाल के मामले में राजस्थान मंत्रिपरिषद सिर्फ अनुच्छेद 174 पर जोर दे रही है लेकिन इसे संपूर्णता में देखने के लिए अनुच्छेद 163 को भी देखना होगा. वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर तिवारी का कहना है कि राज्यपाल अगर केंद्र सरकार की रबड़ स्टांप नहीं है तो वह राज्य सरकार की रबड़ स्टांप भी नहीं है कि मुख्यमंत्री जो कागज भेजें उस पर दस्तखत कर दे.

राज्यपाल की भूमिका और बहुमत परीक्षण पर अब तक सबसे ज्यादा जिस मामले का उदाहरण दिया जाता है वह है एस.आर. बोम्मई केस. दरअसल, 1989 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई की पार्टी के 18 विधायक बागी हो गए. लेकिन बोम्मई ने कहा सरकार अल्पमत में नहीं है. राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट करने की बजाए राज्यपाल ने वहां राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी. केस में 1994 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आया जिसमें ज्यादातर बातें अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में थीं लेकिन फ्लोर टेस्ट और राज्यपाल के विवेक के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी. कोर्ट ने कहा कि सरकार बहुमत है या नहीं इसका फैसला सदन के भीतर होगा, न कि राज्यपाल की मर्जी से होगा.

हाइकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस.आर. सिंह के मुताबिक, राजस्थान के राज्यपाल ने अब 14 अगस्त तक का समय दे दिया है इसलिए विवाद जैसी कोई बात नहीं लगती. कैबिनेट नोट में शायद विश्वास मत हासिल करने की बात नहीं कही थी इसलिए राज्यपाल ने तत्काल सत्र नहीं बुलाया. बहरहाल, राजस्थान के मामले में अब सबकी निगाहें विधानसभा के सत्र पर टिकी हैं और सत्र में ही बागी विधायकों की स्थिति, स्पीकर, मुख्यमंत्री और राज्यपाल का रुख स्पष्ट हो सकेगा. ■

www.readwhere.com

अंबार
दिल्ली के एक कूड़ाघर में प्लास्टिक कचरे का ढेर

चंद्रदीप कुमार

तेरे बिना जिया जाए ना

कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में यातायात बंद होने और फैक्ट्रियों का चक्का थमने से प्रदूषण घटा लेकिन उसी दौरान महामारी की आड़ में प्लास्टिक फिर से हमारी जिंदगी में बुरी तरह से आ घुसी. उसका इस्तेमाल बंद कर प्रदूषण कम करने की पूरी मुहिम ही लडखड़ा गई

शुभम शंखधर

यह बीते हफ्ते की बात है जब नवकार ग्रुप ऑफ कंपनीज के निदेशक पंकज जैन गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी में विशेषज्ञों के साथ बैठकर कारोबार को पटरी पर लाने की रणनीति तैयार कर रहे थे. पिछले साल उन्होंने करीब सात करोड़ रुपए का निवेश करके मक्के के स्टार्च से तैयार होने वाले कंपोजिटेबल उत्पाद बाजार में उतारे थे जो सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प थे. लेकिन अब वे वापस प्लास्टिक के उत्पादों पर शिफ्ट होने की योजना बना रहे हैं. क्यों भला?

दरअसल, इसलिए क्योंकि बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक फिर से चलन में आ रहा है, जिसे बंद करने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से किया था.

लॉकडाउन में मिली ढील के बाद जब गाजियाबाद की शिप्रा सन सिटी में रहने वाली 40 वर्षीया पूनम पहली बार राशन और सब्जी लेने बाहर निकलीं तो मास्क वाले चेहरों तथा सोशल डिस्टेंसिंग के बीच एक और बदलाव ने उन्हें चौंका दिया. कोविड-19 से पहले तक जो दुकानदार और रेहड़ी वाले उन्हें घर से थैला लाने की नसीहत देते थे वे अब खुलेआम प्लास्टिक बैग (पॉलीबैग) में सामान पैक करके बेच रहे थे. पूनम ने वजह जाननी चाही तो सब्जी का ठेला लगाने वाली एक महिला से दो-टूक जवाब मिला, ''जब पीछे से ही माल नहीं आ रहा था तो हमारी मजबूरी थी. अब प्लास्टिक के थैले आराम से मिल रहे हैं, तो हम भी दे रहे.''

दरअसल, मामला केवल पॉलीबैग का नहीं है. कोविड-19 की आड़ में प्लास्टिक (मोटे तौर पर एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाने वाले या 50 माइक्रॉन से कम के) से बने विभिन्न उत्पाद अब बाजार में धड़ल्ले से मिल रहे हैं, जिनके उत्पादन और इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के प्रयास बीते दो साल से केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से किए जा रहे थे.

जैन कहते हैं, ''देश में जब सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने के अभियान ने जोर पकड़ा तो हमने भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभाते हुए प्लास्टिक के विकल्प

www.readwhere.com

खड़े किए.'' लेकिन धीरे-धीरे प्लास्टिक के उत्पाद फिर से बाजार में आ गए. अब इन्हें सरकारी नीतियों की खामी कह लीजिए या उनके क्रियान्वयन में ढिलाई लेकिन हकीकत यही है कि पहले से ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक के उत्पाद बाजार में आ गए और हमारा धंधा बैठ गया.'' पिछले साल प्रधानमंत्री ने जब सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने का आह्वान किया तो एक-डेढ़ महीने तक सारी फैक्ट्रियां बंद रहीं, बाजार में कैरी बैग के इस्तेमाल पर जुर्माने लगे, लेकिन अब हालात जुदा हैं. ज्यादातर फैक्ट्रियां चालू हैं और हर तरह का माल पहले से ज्यादा बनाया और बेचा जा रहा है.

कोविड-19 ने रही-सही कसर भी पूरी कर दी. महामारी के दौरान प्लास्टिक से बने विभिन्न उत्पाद अब बाजार में धड़ल्ले से मिल रहे हैं. वजहें कई हैं. एक तो पहलू स्वच्छता का है; दूसरे, दो लोगों के बीच संपर्क न हो जिससे संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके इसके चलते कम्युनिटी किचन के भीतर, और फिर जरूरतमंदों को खाना बांटने के लिए डिस्पोजेबल कप प्लेट, गार्बेज बैग, सील बंद पानी की छोटी बोतलें. बदले सामाजिक परिवेश में ऐसे उत्पादों की मांग एकाएक बढ़ गई है. मुख्य तौर पर ये ही वे उत्पाद हैं जिनकी वजह से प्लास्टिक एक बड़ी समस्या में तब्दील होता है. इस्तेमाल किए जाने के बाद इन्हें इकट्ठा करके रिसाइकल करना टेढ़ा काम है. इनसे प्रदूषण भी बढ़ता है और आवारा पशुओं के खाने में आने से यही प्लास्टिक उनके प्राण लेने का सबब भी बनता है.

दिल्ली के नरेला और बवाना औद्योगिक क्षेत्र में चालू प्लास्टिक फैक्ट्रियों से जुड़े कारोबारियों से बात करके पता चलता है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते के बाद से मांग तेजी से बढ़ी. कोविड-19 का संकट इतना गहरा था कि बाकी चीजों को पीछे छोड़कर बाजार में सबसे पहले जरूरत ऐसे उत्पादों को उपलब्ध कराने की थी, जिससे हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके. इन्हीं परिस्थितियों ने प्लास्टिक की वापसी के लगभग बंद हो चुके रास्ते दोबारा खोल दिए.

ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष (एनवायरनमेंट कमेटी) अखिलेश भार्गव कहते हैं, ''प्लास्टिक को बैन करने के लिए हम गलत दिशा में कोशिश कर रहे थे.'' यही कारण है कि कोविड की आपदा के बीच जब करोड़ों प्रवासी मजदूरों को खाना बांटने की नौबत आई तो उन्हें पैक करने के लिए प्लास्टिक के कैरी बैग ही सबसे उपयुक्त विकल्प बनकर उभरे. अपनी बात को विस्तार से समझाते हुए वे कहते हैं, ''समस्या प्लास्टिक नहीं बल्कि उससे होने वाला प्रदूषण है. उसे कम करने के लिए प्लास्टिक के कलेक्शन और रिसाइक्लिंग पर जोर देने की जरूरत है. इसके लिए प्लास्टिक को बैन कर देना कोई विकल्प नहीं बल्कि सरकार, इंडस्ट्री और जनता को साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है.'' पिछले दो साल में प्लास्टिक के उपयोग के प्रति किए गए जागरूकता अभियान का यह असर हुआ था कि लोग अपनी आदतें बदलने लगे थे. लेकिन मौजूदा हालात में प्लास्टिक से सस्ता और बेहतर विकल्प उपलब्ध न होने का ही नतीजा था कि प्लास्टिक के इस्तेमाल पर अंकुश नहीं लगाया जा सका.

एक मसला तकनीकी पहलुओं की अस्पष्टता का भी है. इंडियन पॉल्युशन कंट्रोल एसोसिएशन के संस्थापक निदेशक आशीष जैन कहते हैं, ''प्लास्टिक को बैन करने की बात करना और जमीन पर इसके लिए सार्थक पहल करना, दो अलग-अलग बातें हैं. प्लास्टिक बैन को लेकर दो साल से अभियान चलाए जाने के बावजूद अभी तक यही नहीं स्पष्ट है कि सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या? पूरे देश में इसकी एक-सी कोई परिभाषा नहीं.'' आशीष बताते हैं कि कागजों पर तो 21 राज्यों में प्लास्टिक के कैरी बैग पूरी तरह बंद हैं, लेकिन 11-12 राज्यों में अभी भी गैर-कानूनी ढंग से ये बन और बिक रहे हैं. बाकी राज्यों में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. वे कहते हैं, ''प्लास्टिक को लेकर जब तक पूरे देश में एक-सा नियम नहीं होगा, इस पर अंकुश लगा पाना बहुत कठिन है. सरकार अगर वाकई प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को खत्म करना चाहती है तो एक रणनीति के तहत काम करना होगा. सरकारी नोटिफिकेशन निकालकर, जब-तब छापेमारी करके यह कर पाना मुश्किल है.''

वे एक चूके हुए मौके का भी जिक्र करते हुए कहते हैं, ''प्लास्टिक को बैन करने का एक सुनहरा मौका हमने पिछले साल 2 अक्तूबर को गंवा दिया.'' 15 अगस्त को

प्लास्टिक पर अंकुश लगाने के लिए उसका सुलभ विकल्प पेश करना होगा और पूरे देश में एक-सा नियम लागू करना होगा

80,000
करोड़ रुपए
सिंगल यूज प्लास्टिक के बाजार का आकार

26,000
टन
प्लास्टिक कचरा रोज पैदा होता है

60
फीसद
हिस्सा ही रिसाइकल

11
किलो
प्रति व्यक्ति प्लास्टिक उपभोग प्रति वर्ष

वैश्विक औसत 28 किलो प्रति वर्ष

10,000
प्रतिष्ठान
करीब छोटे-बड़े इससे जुड़े हैं

3-4
लाख
लोगों को रोजगार मिला है

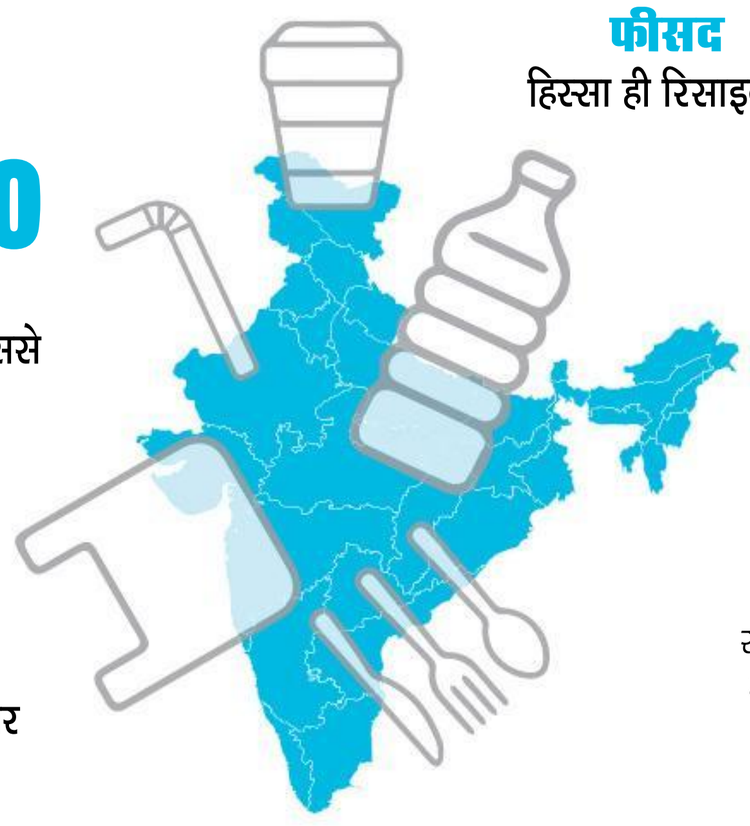

जो रिसाइकल नहीं हो पाते उसमें प्लास्टिक के कैरी बैग, स्ट्रॉ, डिस्पोजल कप प्लेट जैसे उत्पाद

स्रोतः ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन; सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड; प्लास्टिक उद्योग

www.readwhere.com

सिंगल यूज प्लास्टिक

जब प्रधानमंत्री ने लाल किले से प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने का आह्वान किया तो एक उम्मीद जगी थी कि 2 अक्तूबर को सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन की घोषणा हो जाएगी. इसे आंदोलन की तरह आगे बढ़ाया जा रहा था और लोग भी जागरूक होकर मानसिक रूप से तैयार हो रहे थे लेकिन 2 अक्तूबर को प्लास्टिक बैन को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई. इसके बाद से हम लगातार इस प्रयास को कमजोर पड़ते देख रहे हैं. कोविड-19 ने इस पूरी पहल को ही सिर के बल खड़ा कर दिया.

नवकार ग्रुप के दूसरे निदेशक संजीव जैन भी बातों-बातों में एक गंभीर टिप्पणी करते हैं, ''सारा काम बिना बिल के चल रहा है. आप कहीं ढूंढ़ने चले जाइए, आपको कैरी बैग (पॉलीथीन) का एक पक्का बिल नहीं मिलेगा. अगर बिल है ही नहीं तो बाजार में माल आ कहां से रहा है? इससे बेहतर तो यह है कि सरकार बैन हटाकर इस पर टैक्स लगा दे. कम से कम सरकार की कमाई का एक जरिया बढ़ेगा.'' दरअसल, 50 माइक्रॉन से नीचे की प्लास्टिक पर देश के अधिकतर राज्यों में बैन है, इसलिए न तो कोई कारोबारी पक्के बिल पर काम करता है और न ही इस बारे में कुछ खुलकर बताता है.

पंकज जैन एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हैं, ''गुरुग्राम में एक बड़ी कंपनी हमारी ग्राहक थी. हमने उसे प्लास्टिक से अपने उत्पाद पर कन्वर्ट किया था. लेकिन अब वे फिर प्लास्टिक पर वापस लौट गए. दरअसल, प्लास्टिक की तुलना में वैकल्पिक उत्पाद लगभग दोगुनी कीमत पर मिलते हैं.'' काम धंधा मंदा है तो व्यापारी सस्ते विकल्प की ओर बढ़ते हैं.

सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट के डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर दिनेश बंडेला कहते हैं, ''महामारी नहीं भी आती तब भी 2022 तक प्लास्टिक को खत्म करने के लक्ष्य तक पहुंचना असंभव था.'' अपना तर्क पेश करते हुए वे कहते हैं, ''अभी राज्यों ने अपने हिसाब से प्लास्टिक उत्पादों पर पाबंदी लगा रखी है. मसलन, महाराष्ट्र में 16, कर्नाटक में 18, तमिलनाडु में 16 प्लास्टिक उत्पादों को बंद किया गया. राज्य अपने हिसाब से करें, इससे बेहतर यह होता कि सरकार एक मापदंड तैयार करती और सभी राज्य उसे फॉलो करते. इससे हम यह पता लगा सकते थे कि इस दिशा में हम कहां तक पहुंचे और कितना जाना बाकी है. लेकिन अभी जब हमारे पास न तो सिंगल यूज प्लास्टिक की कोई एक निश्चित परिभाषा है और न ही कोई एक-से नियम तो इनको अमल में लाना तो दूर की कौड़ी है.'' प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की दिशा में किए गए प्रयासों के मनचाहे नतीजे मिलें और सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम किया जा सके, इसके लिए दो काम करने जरूरी हैं. पहला, प्लास्टिक जितना सस्ता और सुलभ विकल्प उपलब्ध करवाया जाए और दूसरा, पूरे देश में एक से नियम बनाकर उसे सख्ती से उनका क्रियान्वयन करवाया जाए.

''प्लास्टिक को बैन करने का एक सुनहरा मौका हमने पिछले साल 2 अक्तूबर को गंवा दिया''

आशीष जैन
संस्थापक निदेशक, आइपीसीए

''अभी हमारे पास न तो सिंगल यूज प्लास्टिक की कोई एक निश्चित परिभाषा है और न ही कोई एक जैसे नियम''

दिनेश बंडेला
डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर, सीएसई

यदि कोई उत्पाद प्रतिबंधित हो तो फिर वह पूरे देश में प्रतिबंधित हो.

दिनेश एक और बात की ओर इशारा करते हैं. वे कहते हैं कि महामारी ने कई तरह से प्लास्टिक के इस्तेमाल को हमारे जीवन में बढ़ा दिया है. मसलन, कोविड-19 से पहले लोग रोजाना मास्क या ग्लव्स नहीं बदलते थे. लेकिन अब मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स, पीपीई, शू कवर जैसे विभिन्न उत्पाद जो कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इन्हें बनाने में भी पोलीप्रोपेलीन का इस्तेमाल हो रहा, जो प्लास्टिक की ही एक किस्म है. वे कहते हैं इन्हें इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी है लेकिन इस कचरे को सही तरह से अलग करके इसका निबटारा कैसे किया जाए, इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने इस संबंध में अपने नए दिशानिर्देश में कहा है कि इस्तेमाल किए जा चुके मास्क और दस्तानों का निबटारा करने से पहले उन्हें काट कर कम से कम 72 घंटे तक कागज के थैलों में रखा जाना चाहिए. अब तक कोविड-19 से जुड़े बायो-मेडिकल कचरे पर चार बार दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं. ये नियम सभी के लिए हैं, यह जरूरी नहीं कि मास्क या दस्तानें संक्रमित व्यक्ति ने इस्तेमाल किए हों. सीपीसीबी ने शॉपिंग मॉल जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और कार्यालयों को भी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के निबटारे के लिए इसी कार्यप्रणाली का पालन करने का निर्देश दिया है. सीपीसीबी ने अपने ताजा दिशानिर्देशों में कहा, ''वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, शॉपिंग मॉल, संस्थानों, कार्यालयों में बेकार पीपीई को अलग कूड़ेदान में तीन दिन तक रखना चाहिए, उनका निबटारा उन्हें काट कर ठोस कचरे की तरह करना चाहिए.'' इसके अलावा संक्रमित रोगियों की ओर से छोड़े गए भोजन या पानी की खाली बोतलों आदि को बायो-मेडिकल कचरे के साथ एकत्र नहीं किया चाहिए.

कोविड-19 के बाद प्लास्टिक कचरे का ढेर कितना बड़ा हो जाएगा इसका अनुमान लगाना मुश्किल है. यह समस्या राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय होगी, यह तय है. प्लास्टिक के खतरे और इसके उपयोग के सही तरीकों के प्रति जागरूकता बढ़ाकर ही इस लड़ाई को जीता जा सकता है. नीतियों में अनिश्चितता से कारोबारियों के बीच असमंजस गहराता है और आंदोलन के उत्साह में भी बल पड़ने लगते हैं. ■

www.readwhere.com

मंदिर महिमा

अयोध्या में 5 अगस्त को राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

www.readwhere.com

इंडिया टुडे ग्रुप-कार्वी इनसाइट्स

देश का मिजाज जनमत सर्वेक्षण

मोदी मंत्र का जादू

देश जब एक साथ कई अप्रत्याशित संकटों से जूझ रहा हो तो ऐसे नाजुक वक्त में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता का आखिर राज क्या है?

राज चेंगप्पा

पीआइबी

दुनिया का कोई एक भी शासन प्रमुख नहीं है, जिसकी अगुआई का कोविड-19 महामारी ने इम्तिहान न लिया हो. इतने बेजोड़ और जबरदस्त संकट से सामना होने पर ये नेता अपने राष्ट्र को मुश्किल वक्त से कामयाबी के साथ बाहर निकलने का रास्ता दिखाने की अपनी काबिलियत के दम पर या तो अपनी प्रतिष्ठा बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं. नागरिक अधिकारों के हिमायती अमेरिकी नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक बार कहा था, ''इनसान की निर्णायक कसौटी वहां नहीं है जहां वह सहूलियत के लम्हे में डटा रहता है, बल्कि वहां है जहां वह चुनौती और गहमागहमी के वक्त में डटा रहता है.''

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर तो और भी भारी बोझ है, क्योंकि वे खतरों की खौफनाक तिकड़ी का मुकाबला कर रहे हैं. यह तिकड़ी है—कोविड-19 से उत्पन्न स्वास्थ्य आपदा, पहले ही सुस्त अर्थव्यवस्था पर उसकी मार, और सरहदों पर चीन की आक्रामकता. मगर लगता है अब तक वे इस तिहरे हमले से निबटते और जूझते बखूबी निकल आए हैं. *इंडिया टुडे*-कार्वी इनसाइट्स के छमाही देश का मिजाज जनमत सर्वेक्षण के ताजा संस्करण

www.readwhere.com

इंडिया टुडे देश का मिजाज जनमत सर्वेक्षण

आज लोकसभा चुनाव हुए तो सीटों और वोट हिस्सेदारी का अनुमान

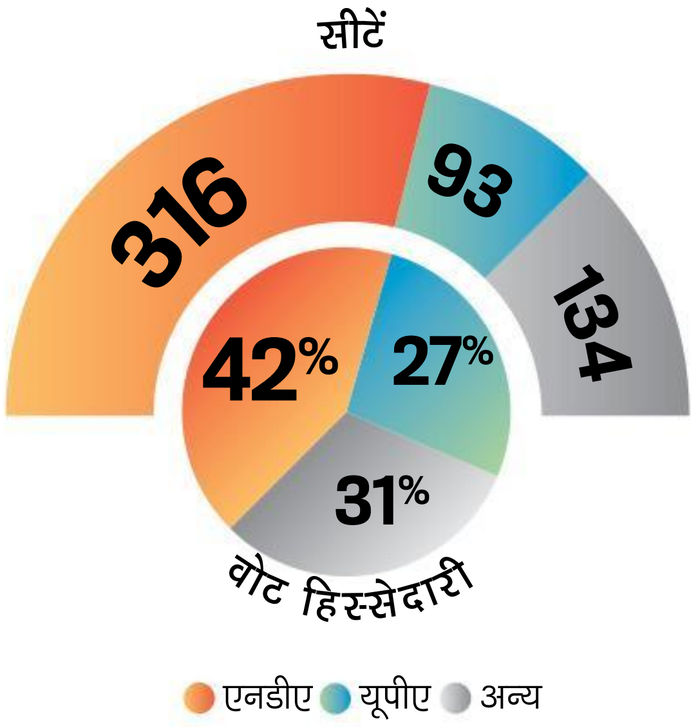

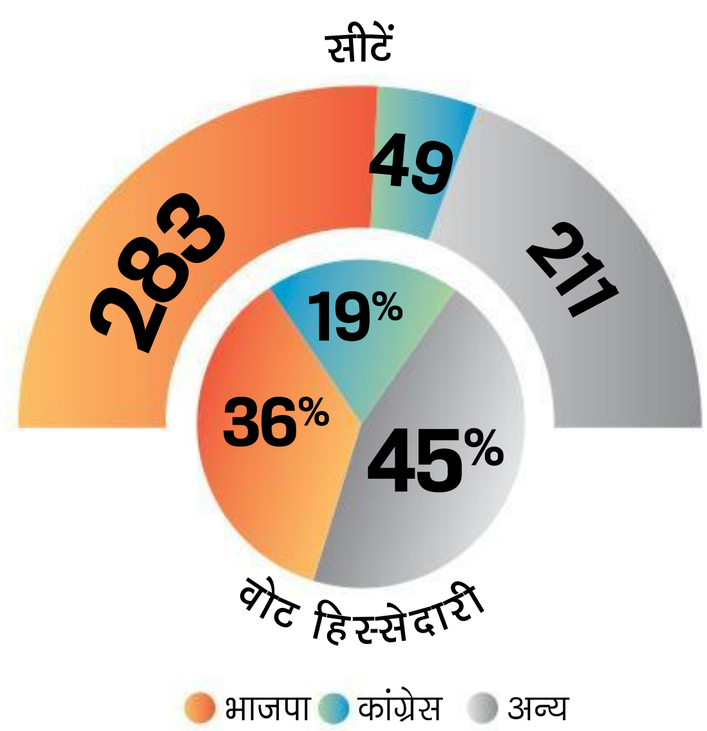

13

सीटों का एनडीए को फायदा क्योंकि पिछले देश का मिजाज सर्वेक्षण से वोट हिस्सेदारी में 1 फीसद अंक की बढ़त है; यूपीए 2 फीसद वोट और 15 सीटें गंवा देगा

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती और असित रॉय

सवाल अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो नतीजे कैसे दिखेंगे?

सीटों का अनुमान

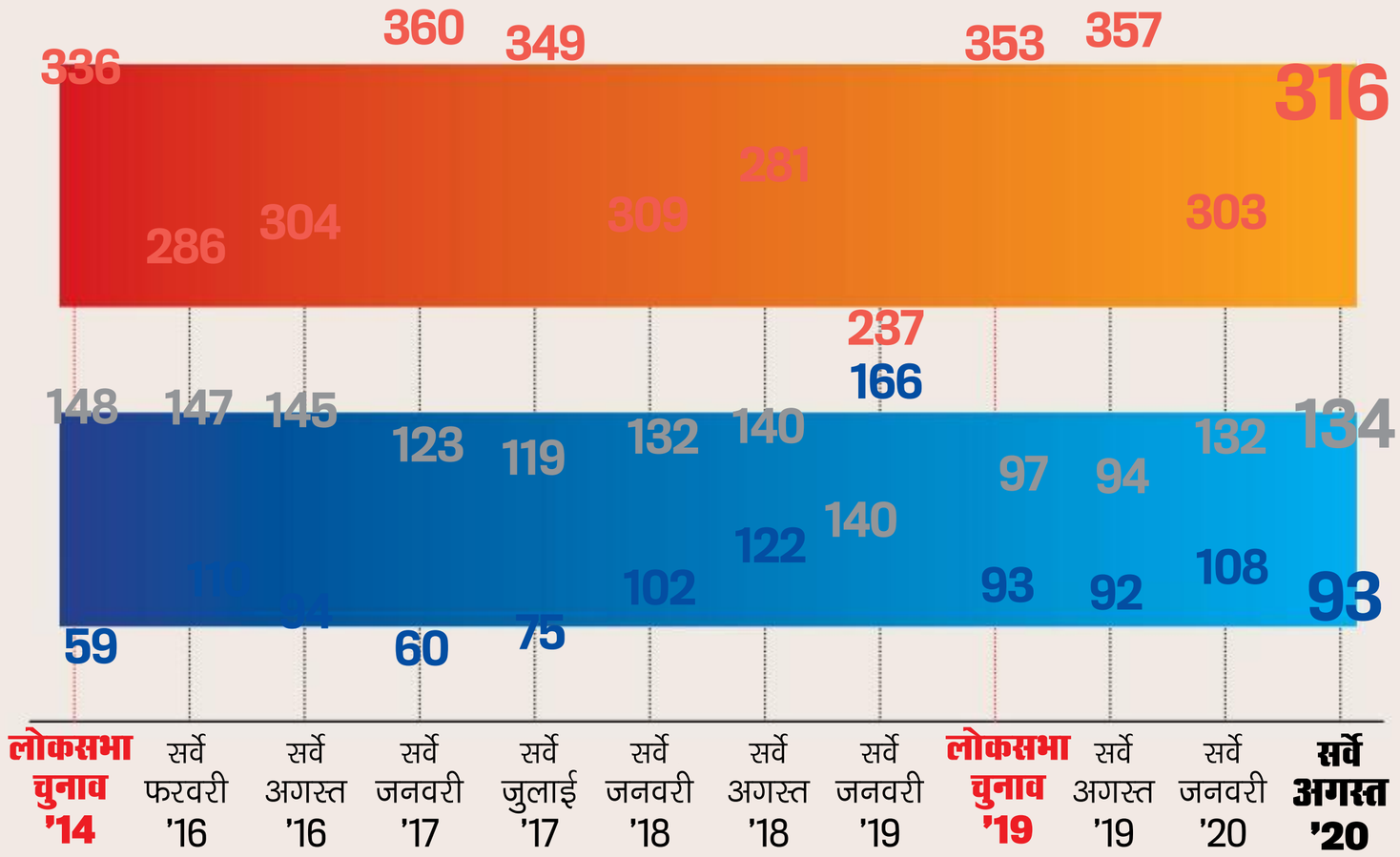

वोट हिस्सेदारी का अनुमान

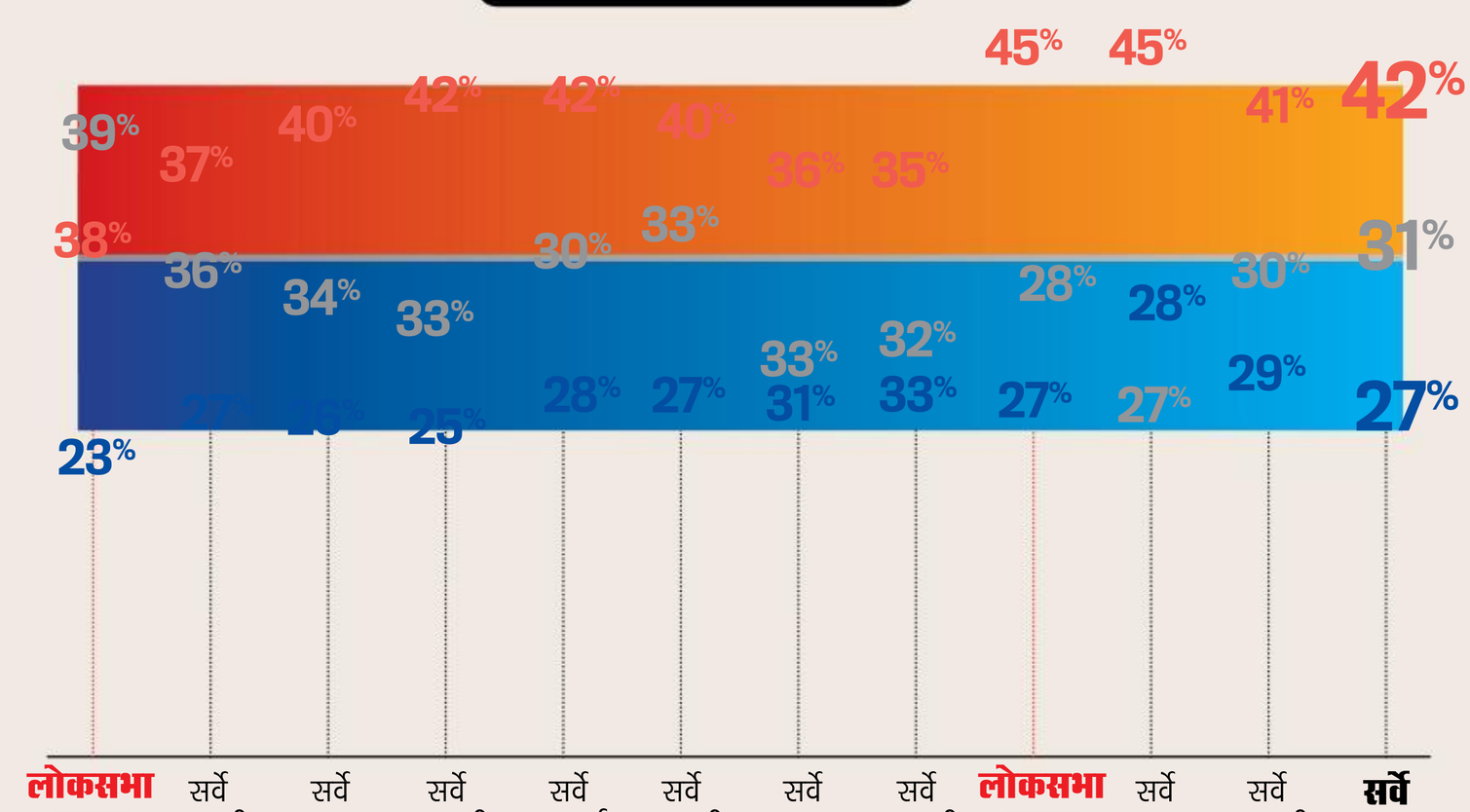

एनडीएः भाजपा, अपना दल, अगप, अन्नाद्रमुक, एआइएनआरएस (ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस), आजसू, बीडीजेएस (भारत धर्म जन सेना), बीपीएफ (बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट), डीएमडीके, जद-यू, केसी-टी (केरल कांग्रेस-थॉमस), लोजपा, पीएमके, पीएनके (पुतिया नीति काच्चि), पीटी (पुतिया तमिलगम), तमिल मनीला कांग्रेस, आरएलपी (राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी), एसडीएफ एनडीपीपी (नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी), एनपीएफ (नगा पीपुल्स फ्रंट), शिरोमणि अकाली दल

यूपीएः कांग्रेस, एआइएमआइएम, द्रमुक, एचएएम, आइयूएमएल, जेडी(एस), एनसी, झामुमो, जेवीएम, केसी(एम), राकांपा राजद, आरएलएसपी, आरएसपी*, एसडब्लूपी (सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी), वीसीके (विदुतलाई चिरुतैगल काच्चि)

अन्यः आम आदमी पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, तृणमूल कांग्रेस, एएमएमके, एयूडीएफ, बीजद, बसपा, बीवीए (बहुजन विकास अघाड़ी), माकपा, भाकपा, जीजीपी, इनेलोद, जेसीसी (जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़), पीडीपी, एमडीएमके, एमएनएफ, एमएनएम (मक्कल निधि), रालोद, शिवसेना, सपा, तेलुगु देशम, टीआरएस, वाइएसआरसीपी, निर्दलीय** और अन्य

www.readwhere.com

आशा का संचार
प्रयागराज में 29 फरवरी को बुजुर्गों और दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण बांटते प्रधानमंत्री मोदी

सवाल अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो किस पार्टी को वोट देंगे?

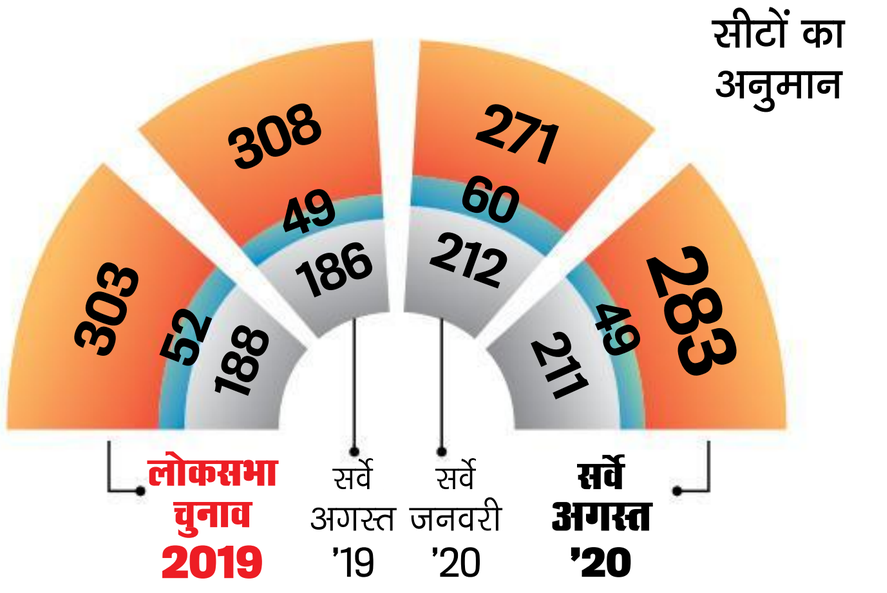

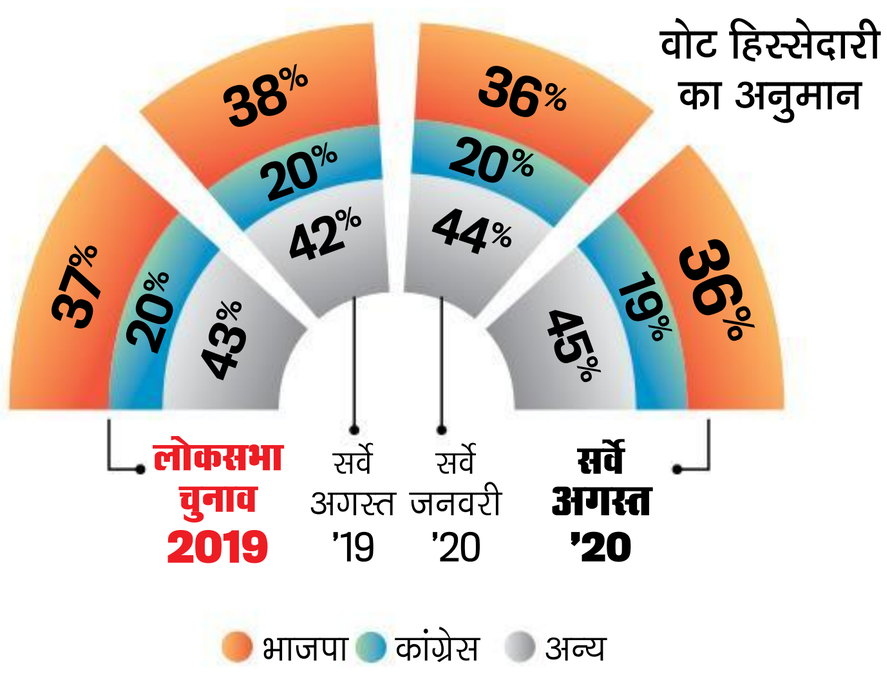

के मुताबिक प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आकाश चूमने लगी है. सर्वेक्षण में 78 फीसद लोगों ने उनके कामकाज को अच्छा से लेकर बेहतरीन तक आंका है, जबकि अगस्त 2019 के सर्वेक्षण में ऐसे लोगों की तादाद 71 फीसद थी (यह मई 2019 के आम चुनाव में उनके शानदार बहुमत के साथ दोबारा निर्वाचित होने के फौरन बाद हुआ था). असल में, तमाम कठिनाइयों के बावजूद मोदी की निजी लोकप्रियता देश का मिजाज सर्वेक्षण में आज जैसी कभी नहीं रही.

78%
लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को बेहतरीन या अच्छा बताया. यह पांच साल में सबसे अव्वल आंकड़ा है

मोदी के लिए जन समर्थन की गवाही सर्वेक्षण के नतीजे इस तरह भी देते हैं कि अगर आज चुनाव हुए, तो भाजपा 283 सीटों के साथ अपने दम बहुमत हासिल कर लेगी, हालांकि यह 2019 के आम चुनाव में उसे हासिल 303 सीटों से 20 कम होंगी. ये नतीजे मोदी के लिए उत्साह बढ़ाने वाले हैं क्योंकि जनवरी 2020 के सर्वेक्षण में भाजपा की सीटों का अनुमान 271 था, जो लोकसभा में अपने दम पर सामान्य बहुमत से एक कम था. एनडीए की सीटें का अनुमान 303 से बढ़कर 316 पर पहुंच गया है, लेकिन यह भी आम चुनाव में उसे मिली 353 सीटों से खासी कम हैं, जबकि कई सहयोगी दल और खासकर शिवसेना उसे छोड़कर चली गई है. जनवरी 2020 में भाजपा और एनडीए दोनों की सीटों के अनुमान में कमी खासकर आर्थिक वृद्धि में तेज गिरावट की वजह से आई थी. अलबत्ता मौजूदा सर्वेक्षण में तिहरे संकट की मार के बावजूद भाजपा और उसी के साथ एनडीए अपनी राजनैतिक किस्मत बुलंद होती देख रही है. अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन सबसे उपयुक्त है? इस सवाल के जवाब में मोदी और उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी राहुल गांधी के बीच फासला 58 फीसद अंकों तक बढ़ गया, जो महज डेढ़ साल पहले 12 फीसद अंक था. इस धारणा में भी इजाफा हुआ है कि वे अब तक के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं (*देखें चार्ट*).

www.readwhere.com

सवाल बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को कैसा पाते हैं?

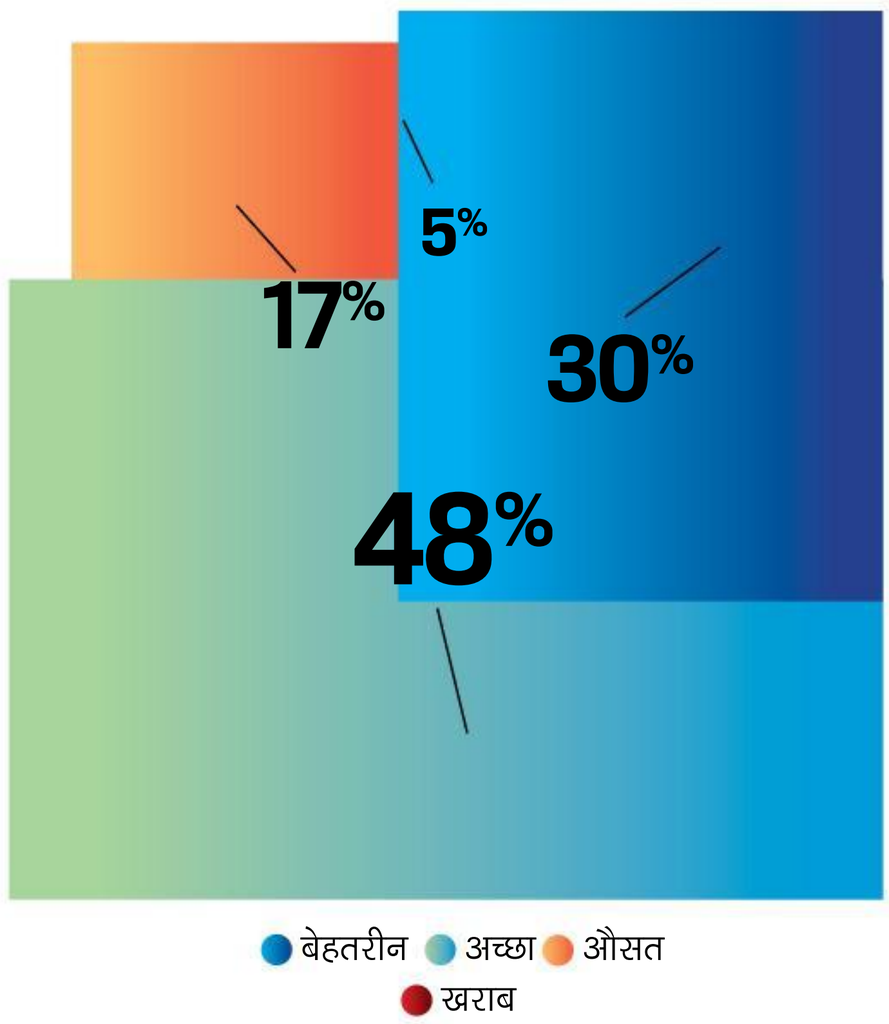

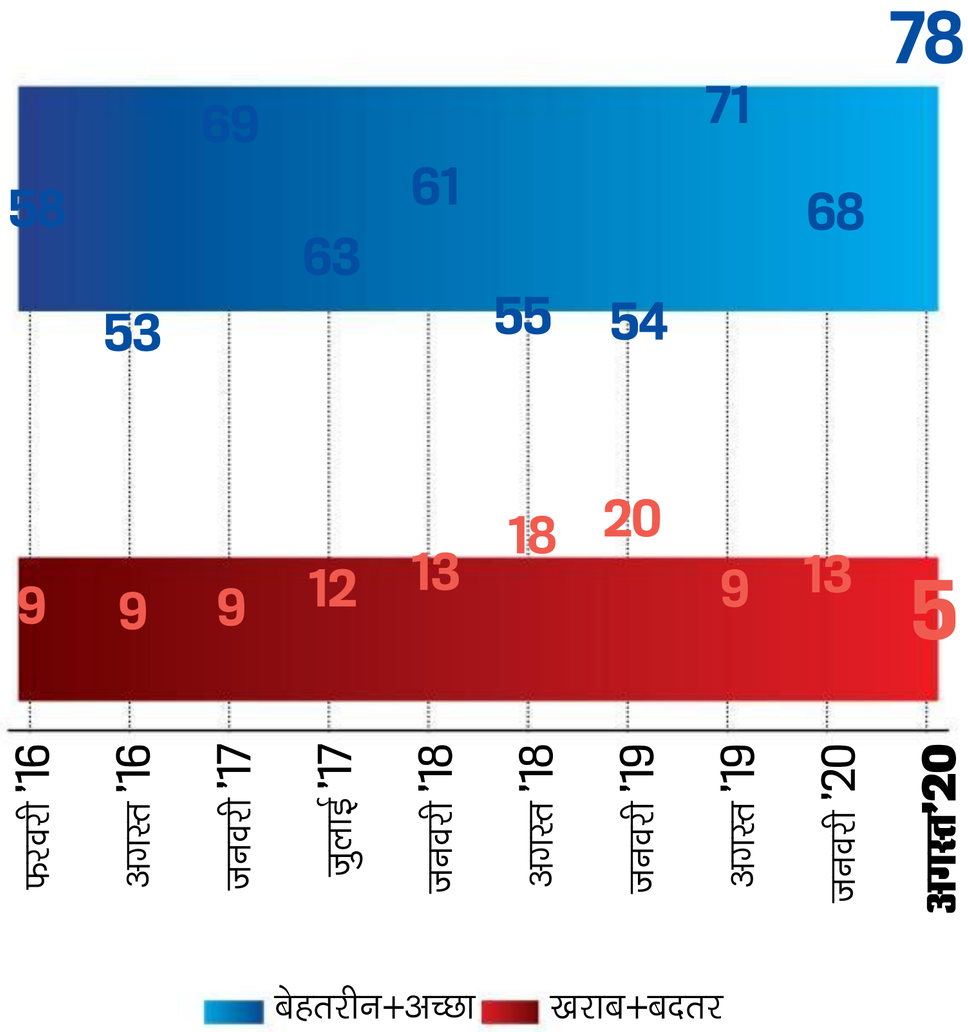

आंकड़े % में

सवाल देश का बेहतरीन प्रधानमंत्री कौन रहा है?

	अगस्त '20	जनवरी '20
नरेंद्र मोदी	**44**	34
अटलबिहारी वाजपेयी	**14**	13
इंदिरा गांधी	**12**	16
जवाहरलाल नेहरू	**7**	8
मनमोहन सिंह	**7**	6
लालबहादुर शास्त्री	**5**	6
राजीव गांधी	**4**	5
मोरारजी देसाई	**2**	2
पी.वी. नरसिंह राव	**1**	1
वी.पी. सिंह	**1**	1

बाकी: पता नहीं/कह नहीं सकते

नरेंद्र मोदी बनाम इंदिरा गांधी
लोकप्रियता का पैमाना

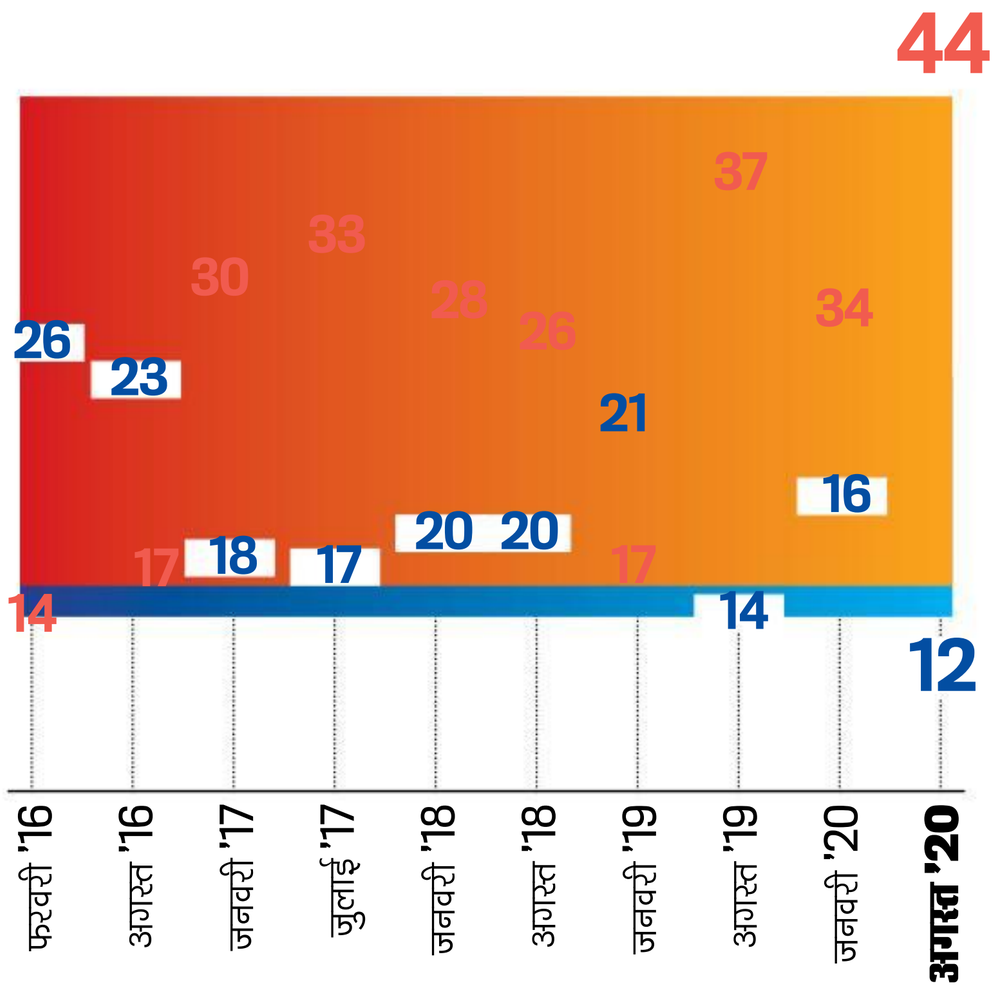

आंकड़े % में

www.readwhere.com

मौजूदा संकटों के बावजूद सर्वेक्षण में मोदी की लोकप्रियता में उल्लेखनीय उछाल की क्या वजहें हैं? मोदी की कामयाबी का मंत्र क्या है? इस अप्रैल में *हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू* (*एचबीआर*) में प्रकाशित सूझबूझ भरे लेख में मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्रिस निकोलस, शोमा चटर्जी हेडन और क्रिस टेंडलर ने कोविड-19 जैसे बड़े संकट से निबटने में नेताओं के चार खास तौर-तरीकों की चर्चा की है. एक, तेजी से फैसले करो, चाहे सटीक न हो; दूसरे, हालात के हिसाब से बदलो; तीसरे, भरोसे से काम करो; और चौथे, लोगों को साथ लेकर चलो. मोदी इन चारों पैमाने पर न सिर्फ खरे उतरे, बल्कि अपनी तरफ से कुछ जोड़ते भी दिखे. इस तरह से उन्होंने अपनी नेतृत्व शैली को *एचबीआर* के अध्ययन के अनुकूल साबित किया. तेजी से फैसले लेने के मामले को ही देखें. लेख कहता है, ''हालात हर दिन—यहां तक कि हर घंटे—बदल रहे हैं. श्रेष्ठ नेता उपलब्ध जानकारियों के मुताबिक फौरन तय करता है कि क्या सबसे जरूरी है और गहरी छानबीन में समय जाया करने के बजाए पूरे भरोसे से फैसला करता है.'' जब कोविड-19 की बात आई तो मोदी ने ठीक यही किया. उन्होंने 24 मार्च को महज चार घंटे के नोटिस पर देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी.

कोविड चुनौती का मुकाबला

पर्याप्त चेतावनी के बगैर लॉकडाउन लगाने के मोदी के फैसले की कई लोगों ने यह कहकर आलोचना की है कि सख्त लॉकडाउन लगाने की भला क्या जरूरत थी जिससे अर्थव्यवस्था को साफ तौर पर नुक्सान पहुंचा. लेकिन वे जानते थे कि अगर बीमारी तेजी से फैली, तो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी महामारी को संभालने की हालत में नहीं है. लिहाजा प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के जरिए वक्त हासिल करने का फैसला किया ताकि इस बीच मरीजों के इलाज की देश की क्षमता को मजबूत कर सकें और हजारों जिंदगियां बचाई जा सकें.

पहले कुछ दिन जरूर अफरातफरी मच गई, लेकिन आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ प्रमुख सचिव डॉ. पी.के. मिश्र की सलाह मानकर मोदी ने सेंट्रल कमान बनाने का फैसला किया. यह एक किस्म का 'वॉर रूम' था (जिसकी सलाह *एचबीआर* के लेखक भी देते हैं) जहां वरिष्ठ सचिव और विशेषज्ञों की अगली कतार को तैनात करके इतने अधिकार और शक्तियां दी गईं कि वे कोविड की वजह से पैदा होने वाली तमाम मुश्किलों से निबट सकें. इन 11 विशेषज्ञ समूहों ने बेहद अहम दवाइयों और उपचार केंद्रों की उपलब्धता से लेकर जरूरी चीजों के लिए

सवाल देश का अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे काबिल कौन ?

मोदी बनाम राहुल
फासला बढ़ा

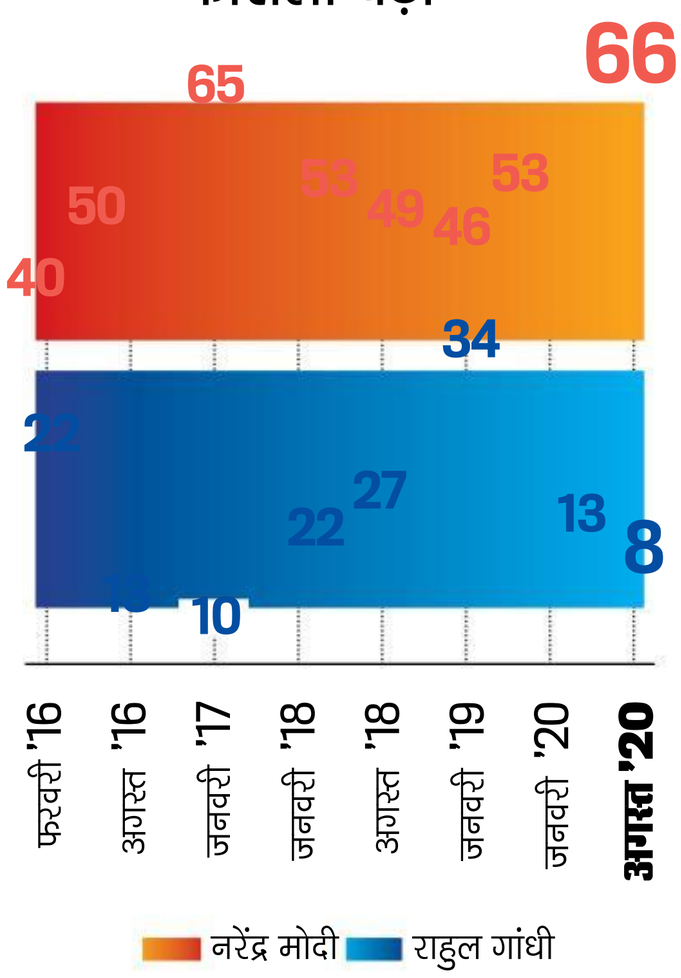

आंकड़े % में

		अगस्त '20	जनवरी '20
1	नरेंद्र मोदी	66	53
2	राहुल गांधी	8	13
3	सोनिया गांधी	5	7
4	अमित शाह	4	4
5	अरविंद केजरीवाल	3	2
6	योगी आदित्यनाथ	3	1
7	अखिलेश यादव	3	1
8	प्रियंका गांधी	2	3
9	ममता बनर्जी	2	2
10	राजनाथ सिंह	1	2
11	नितिन गडकरी	1	1
12	शरद पवार	1	1
13	उद्धव ठाकरे	1	1
14	मायावती	1	1

आंकड़े बराबर किए गए

www.readwhere.com

आपूर्ति शृंखलाओं और लॉजिस्टिक्स में सहूलियत देने जैसे तमाम प्रमुख मुद्दों पर फैसले किए. मोदी ने लॉकडाउन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले लोगों के आर्थिक कल्याण के कदम भी उठाए.

नतीजे जोरदार थे. जब लॉकडाउन शुरू हुआ, देश को मास्क, दस्ताने और बॉडीसूट सरीखे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (पीपीई) आयात करने पड़े थे. मगर दो महीनों के भीतर भारत पीपीई किट के मामले में आत्मनिर्भर बन गया, जब भारतीय कंपनियों ने इनके निर्माण के लिए एक साथ कमर कस ली. कोविड-19 की जांच की सुविधाएं मार्च में बहुत बुरी हालत में थीं, जब एक दिन में मुश्किल से 5,000 टेस्ट किए जा रहे थे. इन्हें बढ़ाया गया और अब हर रोज 6,64,000 टेस्ट किए जा रहे हैं. गंभीर रूप से बीमार कोविड के मरीजों (संक्रमण की चपेट में आए 2 फीसद को आइसीयू सुविधाओं की जरूरत पड़ती है) की देखभाल के लिए बेहद अहम वेंटिलेटर भी कम तादाद में मौजूद थे. इनका घरेलू उत्पादन भी ताबड़तोड़ बढ़ाया गया.

लॉकडाउन शुरू होने के बाद से हमारे यहां 20 लाख के करीब मामले भले हों, लेकिन संक्रमण के कुल मामलों के अनुपात में मृत्यु दर 2.07 फीसद है जो दुनिया में सबसे कम है. सबसे अहम बात यह कि मोदी ने देश को सीधे जानकारियां देने और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जोड़ने की जिम्मेदारी की अगुआई की, ताकि वे केंद्र के साथ तालमेल बिठाकर यह जंग लड़ सकें. उन्होंने उन खूबियों का प्रदर्शन किया, जिनका जिक्र फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स द गॉल ने किया था, ''संकट से दो-चार होने पर चरित्रवान आदमी खुद अपने पर भरोसा रखता है. वह अपने काम की छाप छोड़ता है, उसकी जिम्मेदारी लेता है, उसे अपना बना लेता है.''

> कोविड की जंग में मोदी ने लोगों से **संवाद करने का बीड़ा उठाया** और मुख्यमंत्रियों को जोड़ा, ताकि सभी व्यवस्थाएं सही ढंग से चलें

इससे शायद हमारे सर्वेक्षण के उन दो परस्पर विरोधी नतीजों की वजह का भी पता चलता है कि 25 फीसद लोग कोविड-19 महामारी से निबटने के तरीके को मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी मानते हैं लेकिन इसके लिए मोदी को दोष नहीं देते. असल में, 77 फीसद लोग महामारी से मोदी के निबटने के तरीके को अच्छा या बेहतरीन आंकते हैं. यही नहीं, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के संकट पर मोदी सरकार का रवैया बेहद खराब रहा, लेकिन इसके लिए भी मोदी को दोष नहीं दिया जाता. यह बताता है कि इस सरकार की कमियों-खामियों के बावजूद मतदाता मानते हैं कि मोदी का अभी कोई विकल्प नहीं है. उनकी नजरों में वे ऐसे नेता हैं, जो कुछ भी गलत कर ही नहीं सकते.

खस्ताहाल अर्थव्यवस्था का इलाज

एचबीआर का लेख संकट से घिरे मजबूत नेता के व्यवहार की दूसरी खूबी, तेजी से बदलते हालात के मुताबिक फैसले लेने की क्षमता बताता है. लेख में इसके गुर बताए गए हैं कि एक, तय करो कि क्या नहीं करना है. फिर जो करना है, उसकी प्राथमिकता तय करो और उसे सख्ती से करो; और दूसरे, पुराने कायदों को छोड़ो और नई

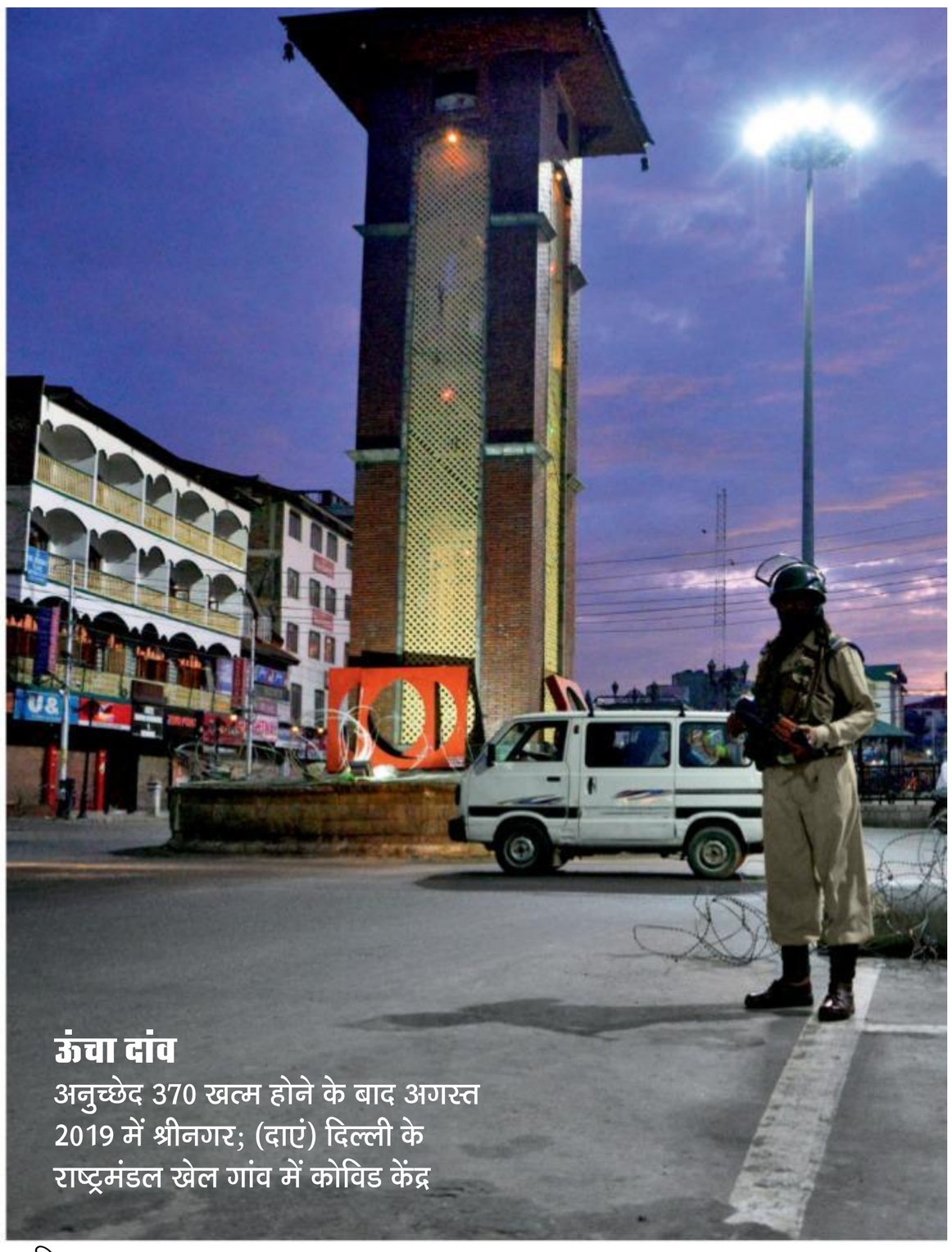

ऊंचा दांव
अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अगस्त 2019 में श्रीनगर; (दाएं) दिल्ली के राष्ट्रमंडल खेल गांव में कोविड केंद्र

यासिर इकबाल

सवाल आप एनडीए सरकार के पूरे कामकाज से कितने संतुष्ट हैं?

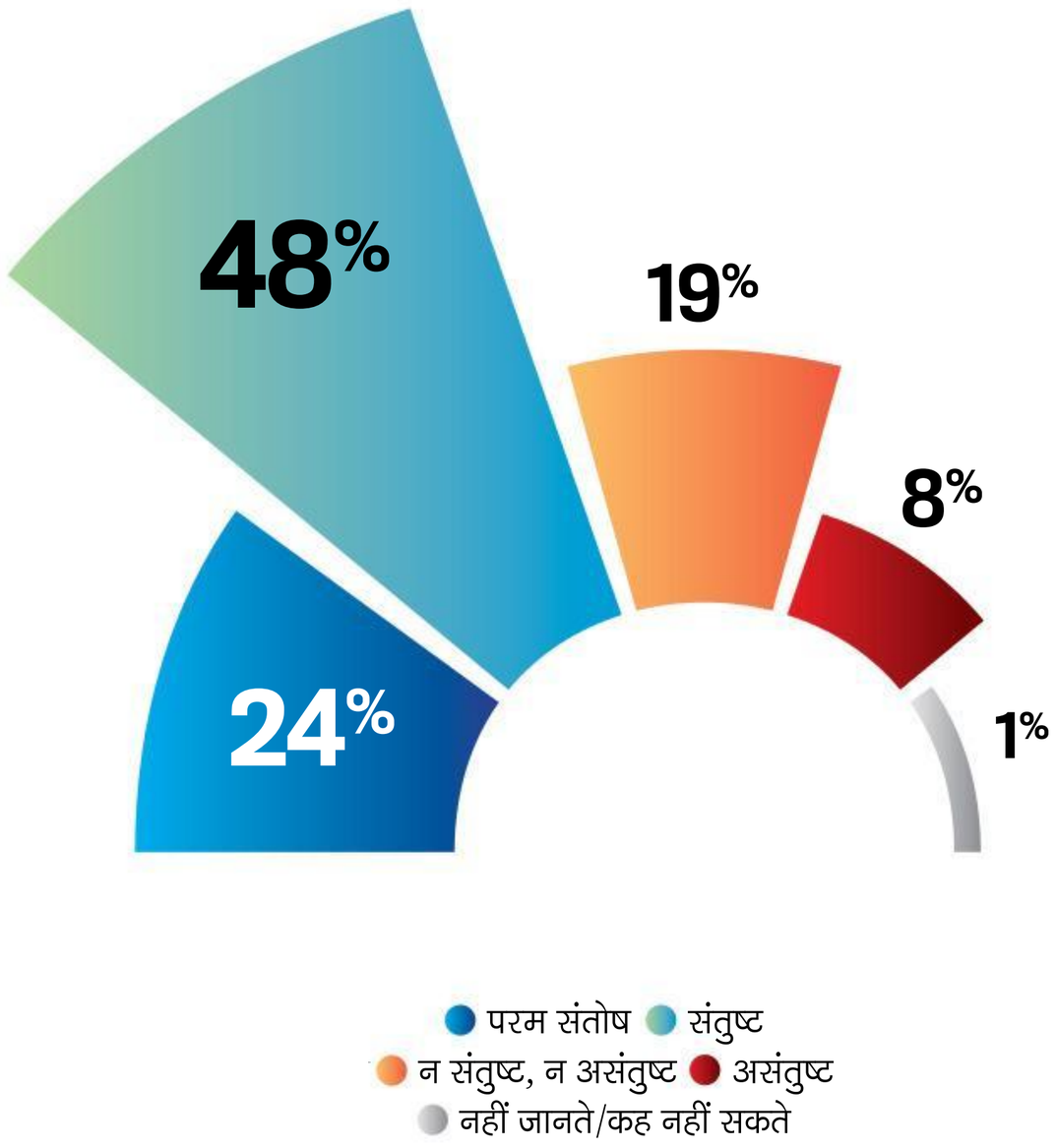

www.readwhere.com

16%

25%

पंकज नांगिया

सवाल मोदी सरकार की कोई एक सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटाया जाना	
अयोध्या के मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय	13
बुनियादी सुविधाओं में सुधार	11
भ्रष्टाचार-मुक्त शासन	9
काला धन के विरुद्ध कार्रवाई	9
कोविड-19 से निबटने के तरीके	7
नोटबंदी	6
गरीबों और किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं	6
जीएसटी पर अमल	5
स्वच्छता अभियान	3
दुनिया में भारत की छवि बेहतर बनाना	2
आतंक के खिलाफ सख्त रवैया	2
डिजिटलीकरण अभियान	2
महिला सशक्तीकरण	2
मेक इन इंडिया कार्यक्रम	2
संसद में नागरिकता संशोधन कानून पारित	1
आयुष्मान भारत योजना	1

बाकीः पता नहीं/कह नहीं सकते — आंकड़े % में

सवाल मोदी सरकार की कोई एक सबसे बड़ी नाकामी क्या है?

कोविड-19 से निबटने का तरीका	
बेरोजगारी	23
लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों का पलायन	14
महंगाई	11
अर्थव्यवस्था	7
स्वास्थ्य ढांचे में सुधार करने में नाकामी	6
किसानों की समस्या	6
जम्मू-कश्मीर में अशांति	1
नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध प्रदर्शन	1
सांप्रदायिक हिंसा और अल्पसंख्यकों में डर	1
चीन, नेपाल और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ रिश्तों में खटास	1

बाकीः पता नहीं/कह नहीं सकते — आंकड़े % में

अनुच्छेद 370 का खात्मा पिछले छह महीने में सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बनी हुई है

www.readwhere.com

मोदी सरकार के बेहतरीन कामकाज वाले 10 मंत्री

अमित शाह
39 [43]

राजनाथ सिंह
17 [39]

नितिन गडकरी
10 [34]

निर्मला सीतारमण
9 [26]

रविशंकर प्रसाद
3 [16]

पीयूष गोयल
2 [24]

स्मृति ईरानी
2 [22]

धर्मेंद्र प्रधान
2 [–]

एस. जयशंकर
1 [–]

रामविलास पासवान
1 [15]

आंकड़े % में; [ ] के आंकड़े देश का मिजाज सर्वेक्षण जनवरी '20 के

योजनाएं बनाओ. जब रसातल में जाती अर्थव्यवस्था को सहारा देने की बात आई तो मोदी कुछ हद तक इसी सलाह पर चलते दिखाई दिए. जब देशव्यापी लॉकडाउन के बोझ से अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठने लगा, तो मोदी ने हालात के मुताबिक तेजी से बदलाव किया और जान (जिंदगी) पर जोर देने के बाद उसके साथ जहान (आजीविकाएं बचाने) को जोड़ दिया. उनके प्रमुख सचिव मिश्र तस्दीक करते हैं कि महामारी की शुरुआत से ही मोदी का प्राथमिक ध्यान अर्थव्यवस्था पर रहा है. उन्होंने *इंडिया टुडे* से कहा, ''कइयों को लगा कि प्रधानमंत्री केवल सामाजिक और स्वास्थ्य के मुद्दों पर जोर दे रहे हैं. लेकिन कोविड संकट की बिल्कुल शुरुआत से ही इस पूरे दौरान उनका ज्यादा ध्यान अर्थव्यवस्था पर रहा है. यहां तक कि अब भी वे लगातार आर्थिक वृद्धि के उपायों पर जोर दे रहे हैं ताकि काम पूरे होना पक्का किया जा सके.'' देश का मिजाज सर्वेक्षण में लोग मानते हैं कि मोदी आर्थिक संकट को अच्छी तरह संभाल रहे हैं.

अमेरिका समेत ज्यादातर विकसित देशों ने अपनी गिरती अर्थव्यवस्थाओं को ऊपर उठाने के लिए जहां नकद हस्तांतरण सहित भारी-भरकम वित्तीय प्रोत्साहन पैकेजों का ऐलान किया, मोदी नियमों और रणनीतियों की इस किताब या 2008 के वित्तीय संकट के वक्त अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री की किताब के खिलाफ चले गए. उनके सलाहकार मानते हैं कि 2008 में मनमोहन सिंह ने जो वित्तीय प्रोत्साहन दिया था, उसका नतीजा ढांचागत कमजोरियों की शक्ल में सामने आया और जिसकी वजह से दूसरी चीजों के अलावा मौजूदा एनपीए का संकट पैदा हुआ. यही नहीं, इस हकीकत ने भी मोदी के पैरों में बेड़ियां डाल दीं कि भारत की माली हालत महामारी की चपेट में आने से पहले ही सेहतमंद नहीं थी. जीडीपी वृद्धि दर गिरकर हाल के वर्षों की सबसे निचली दरों में पहुंच गई थी, बैंकों का संकट था ही और सरकार के लिए राजकोषीय घाटे के अपने लक्ष्य पूरे कर पाना मुश्किल हो गया था. अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए मोदी अंधाधुंध उपायों का सहारा लेने के इच्छुक नहीं थे. वे राजकोषीय समझदारी की अपनी फितरत के रास्ते पर ही चले और उन्होंने चुनिंदा नकद सहायता का ही ऐलान किया. उन्होंने जरूरतमंदों यानी किसानों, प्रवासी मजदूरों, गरीबों और महिलाओं पर ही ध्यान दिया. दूसरों और खासकर उद्योगों के लिए

> मोदी ने **अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा** देने के लिए नकद हस्तांतरण के बदले वित्तीय समझदारी को तवज्जो दी, क्योंकि लोगों में खर्च करने की जगह बचाने की फितरत है.

www.readwhere.com

सवाल कोविड-19 से निबटने के प्रधानमंत्री मोदी के तरीकों पर आपकी क्या राय है?

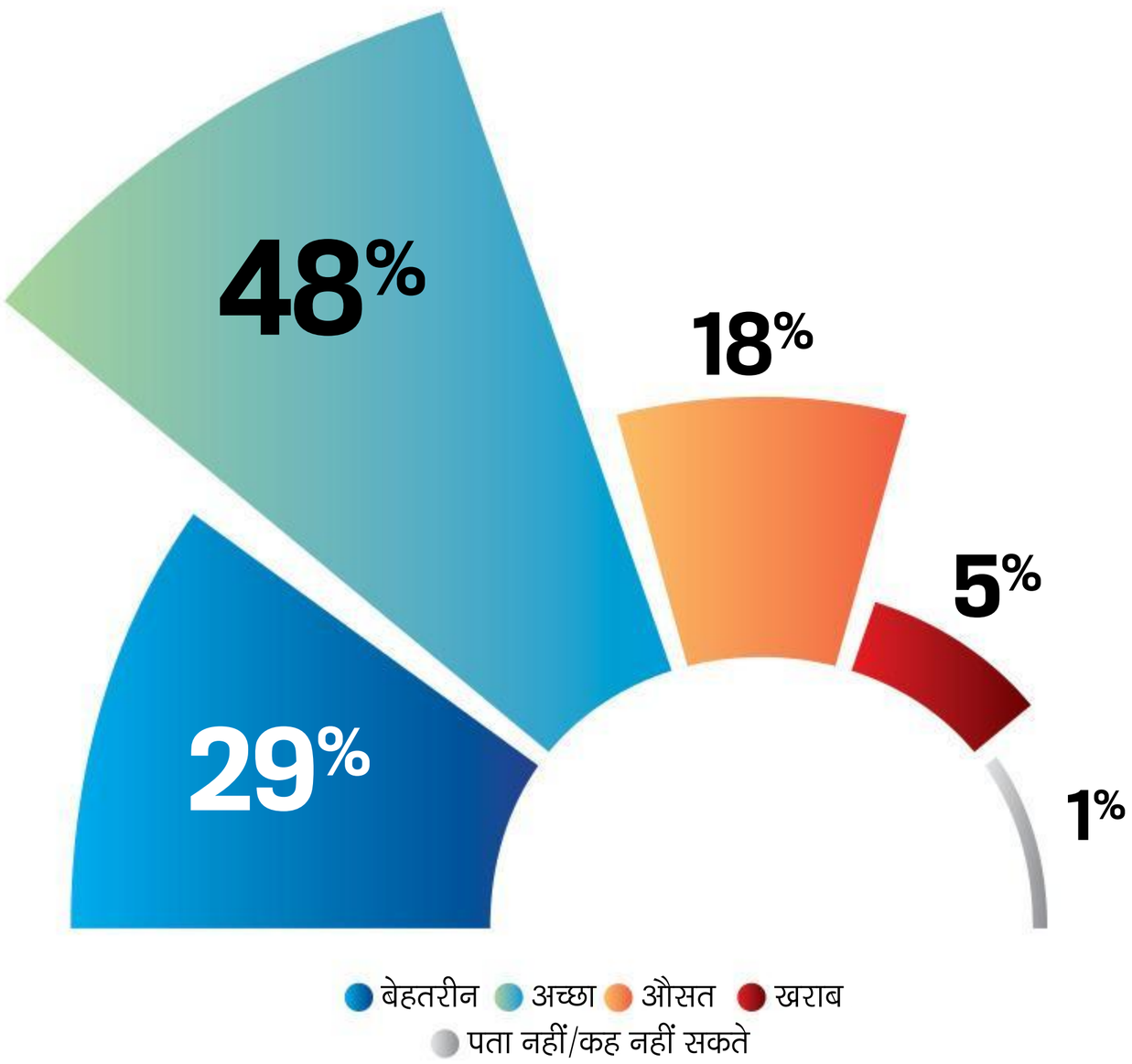

आंकड़े पूर्ण संख्या तक पूरे किए गए

सवाल फिलहाल देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है?

कोविड-19 महामारी	70
बेरोजगारी	12
आर्थिक मंदी	4
चीन से टकराव	4
महंगाई	3
भ्रष्टाचार	2
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें	1
सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं	1
बढ़ती असहिष्णुता और भय का वातावरण	1

बाकी: पता नहीं/कह नहीं सकते

आंकड़े % में

34%

दक्षिण भारत के लोगों का मानना है कि कोविड-19 के प्रति मोदी सरकार का रवैया बेहद खराब रहा है. यह देश के सभी क्षेत्रों में सर्वाधिक है

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खास तौर पर कुटीर, लघु और मझोले उद्यमों के लिए कर्जों पर मोरेटोरियम का ऐलान किया.

आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज इस नजरिए की वजह बताते हैं. उनका कहना है कि इसके पुख्ता सबूत हैं कि नकद हस्तांतरण से मांग को बढ़ावा नहीं मिलता, क्योंकि लोगों का रुझान धन को बचाकर रख लेने का होता है. वे बताते हैं कि तीन ए रेटिंग वाली कंपनियों ने भी कर्ज चुकाने के बजाए कर्जों पर मोरेटोरियम का लाभ लिया क्योंकि वे नकद बचाकर रख लेना चाहती थीं. यही महिलाओं के बारे में भी सच है जिन्हें कोविड संकट से निजात पाने के लिए तीन महीनों तक प्रति माह 500 रुपए उनके जन धन खातों में अदा किए गए. इस योजना में 30,000 करोड़ रुपए बांटे गए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने यह रकम खर्च नहीं की और ऐसे खातों में बैंकों की जमाराशि बढ़कर 17,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई. टीम मोदी ने तय किया कि इसके बजाए खासकर एमएसएमई को कर्जों में राहत देना कहीं बेहतर है, ताकि वे दोबारा कामकाज शुरू कर सकें, लोग फिर काम पर लौटें और अर्थव्यवस्था का पहिया फिर घूमने लगे. सरकार ने एमएसएमई को ऐसे मोरेटोरियम के लिए पात्रता का स्तर 100 करोड़ रुपए के टर्नओवर से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया, ताकि इसके दायरे में 90 फीसद के करीब एमएसएमई आ जाएं. बजाज के मुताबिक जीएसटी संग्रह सहित प्रमुख संकेतक अभी तक बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में सुधार आने लगा है, इसके बावजूद उसे लेकर चिंताएं बनी हुई हैं क्योंकि महामारी क्या शक्ल लेगी, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता. अलबत्ता वे मानते हैं कि अगर वैक्सीन आ जाती है तो इससे धारणाएं बदलेंगी और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आएगी. बजाज कहते हैं, ''हम वी (अंग्रेजी के अक्षर) आकार की रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं.''

मोदी ने बार-बार साबित किया है कि मुश्किल को मौके में बदलने में उन्हें महारत हासिल है. अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी ने एक बार कहा था, ''जब चीनी में लिखा जाता है, तो 'संकट' शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है. एक का मतलब है खतरा और दूसरे का मतलब है मौका.'' मोदी ने तय किया कि कोविड की वजह से जो भारी-भरकम और जबरदस्त कायापलट हुआ है, वह लंबे वक्त से टलते आ रहे सुधारों को अंजाम देने का माकूल मौका है. इसीलिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान का ऐलान किया और इसके तहत कृषि, रक्षा, अंतरिक्ष, विमानन, एटमी ऊर्जा और शिक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में कहीं ज्यादा निजी निवेश और भागीदारी पक्की करने के लिए बड़े नीतिगत बदलाव किए. इन सुधारों को रफ्तार देने के लिए मोदी ने निजी दिलचस्पी ली, बीसियों बैठकों की अध्यक्षता की और समाधान निकालने तथा रुकावटों को खत्म करने के काम में पीएमओ को

www.readwhere.com

भी लगा दिया. देश का मिजाज सर्वे पूरे दिल से आत्मनिर्भर भारत अभियान का अनुमोदन करता है. बहुसंख्यक उत्तरदाताओं ने यह भी कहा कि कोविड संकट से निबटने के लिए मोदी सरकार ने जो 20 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया, वह उनकी कुछ आर्थिक तकलीफों के हल्का करने में मदद करेगा.

बड़े मुद्दों पर वादे पूरे

हाल के वक्त में कम ही नेता हैं जो देश की धड़कन को मोदी से बेहतर महसूस कर पाए हैं. देश का मिजाज सर्वेक्षण में उनकी उपलब्धियों की फेहरिस्त में सबसे ऊपर दो मुद्दे आए हैं, जो संघ परिवार के दिल के करीब हैं. ये हैं—कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण. इसके साथ ही हम *एचबीआर* के लेख में दर्ज व्यवहार की तीसरी खूबी पर आते हैं—भरोसेमंद ढंग से काम पूरे करना. मोदी ने पक्का किया कि इन दो मुद्दों और साथ ही नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को, जिसका जिक्र पार्टी के घोषणापत्र में भी है, अपने दूसरे कार्यकाल के पहले छह महीनों में अंजाम पर पहुंचा दिया जाए. हालांकि यह तो कहना ही होगा कि यह सुप्रीम कोर्ट ही था जिसने हिंदू समुदाय के हक में राम मंदिर का फैसला सुनाया, हालांकि संघ परिवार को तेज रफ्तार से सुनवाई की दरख्वास्त करनी पड़ी थी.

खुद मोदी ने इस मामले में सधी हुई चुप्पी बनाए रखी, खासकर जब वे लगातार अपने इस रुख पर कायम थे कि यह मुद्दा कानून की अदालत में ही तय होना चाहिए. वे अध्यादेश के जरिए इसके समाधान की संघ की आला जमात की तरफ से की गई मांग के आगे नहीं झुके. फैसला सुनाए जाने से एक दिन पहले मोदी ने शांति बनाए रखने की अपील की और हिंदुत्व के समर्थकों से कहा कि वे जीत की खुशी के प्रदर्शन से परहेज करें. 5 अगस्त को भी राम मंदिर के शिलान्यास समारोह का इस्तेमाल भी उन्होंने सभी धर्मों की राष्ट्रीय एकता का संदेश दोहराने के लिए किया. समारोह के बाद मंदिर स्थल पर अपने भाषण में उन्होंने कहा, ''हम सबको याद रखना होगा कि जब भी मानवजाति ने भगवान राम में विश्वास किया, प्रगति हुई है. जब भी हम इस रास्ते से भटके, विनाश के दरवाजे खुल गए. हमें सभी की सहायता और भरोसे के साथ हरेक का विकास पक्का करना होगा.''

चीन से निबटना

इस मई में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी आक्रामकता के चलते 45 साल में पहली बार सरहदी टकरावों में दोनों तरफ के सैनिकों की जानें गईं. इसने दोनों सेना को सैन्य दस्तों के जबरदस्त जमावड़े और खतरनाक सैन्य गतिरोध की तरफ धकेल दिया. यह मोदी का करगिल लम्हा था. अपने वक्त में जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में एलओसी पर पाकिस्तानी सैन्य दस्तों को चोरी-छिपे घुसते और ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमाते देखा था, उसी तरह चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) लद्दाख के कई इलाकों में घुस आई. एलओसी से सटे जिन क्षेत्रों पर भारत अपना दावा करता है, उन क्षेत्रों में पीएलए के सैन्य दस्ते कब्जा जमाने में कैसे कामयाब हो गए, बाद में इसके संपूर्ण पोस्टमार्टम की जरूरत है. लेकिन मोदी को एक सर्वदलीय बैठक में यह कहने के लिए चौतरफा आलोचना झेलनी पड़ी कि चीनियों ने भारतीय भूभाग पर कोई कब्जा नहीं किया है.

शायद मोदी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यह संकेत दे रहे थे कि वे

विक्रम शर्मा

प्र. नागरिकता संशोधन कानून, 2019 पर आपकी राय क्या है?

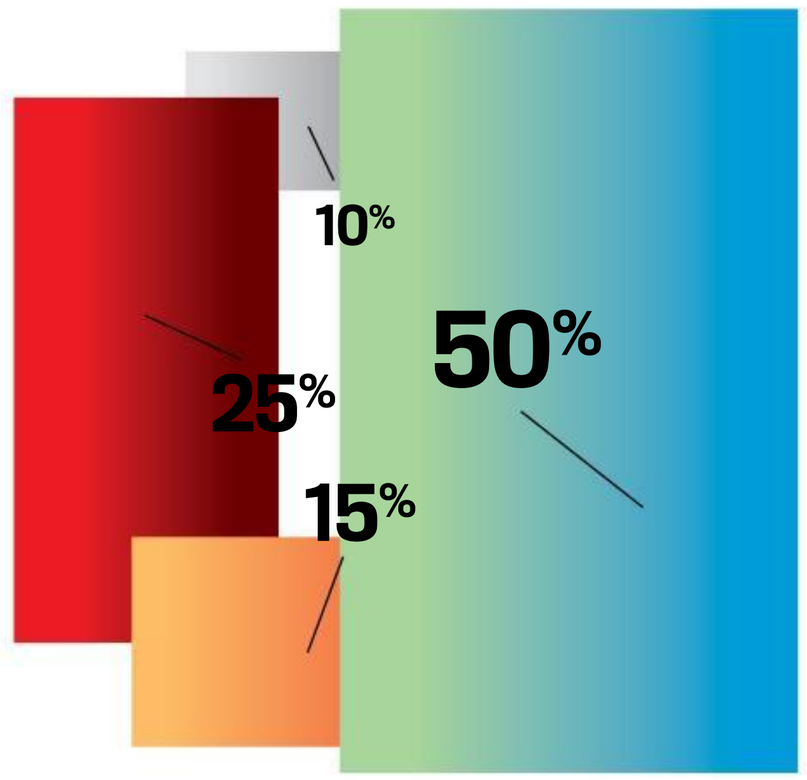

www.readwhere.com

सर्वेक्षण का तरीका

इंडिया टुडे के लिए देश का मिजाज जनमत सर्वेक्षण दिल्ली स्थित बाजार अनुसंधान एजेंसी, कार्वी इनसाइट्स ने 15 जुलाई से 27 जुलाई 2020 के बीच किया. यह सर्वेक्षण परंपरागत रूप से लोगों से बातचीत के आधार पर किया गया है. हालांकि, सर्वेक्षण के इस संस्करण में, कोविड-19 से उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति के कारण बातचीत पहले से तैयार एक मानक प्रश्नावली, जिसका क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद भी किया गया था, का उपयोग करके टेलीफोन के जरिए की गई. 19 राज्यों—आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 97 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और 194 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 12,021 लोगों से बातचीत की गई जिसमें से 67 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों से और 33 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रों से थे. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, एक निश्चित संख्या में लोगों से बातचीत की गई. देश का मिजाज जनमत सर्वेक्षण के लिए फील्डवर्क कार्वी इनसाइट्स के अध्यक्ष रंजीत छिब की देखरेख में किया गया. कार्वी के उपाध्यक्ष देबाशीष चटर्जी और सहायक प्रबंधक सोनल तलवार इस कार्य में उनके सहयोगी थे.

शांतिपूर्ण समाधान का दरवाजा खुला छोड़ रहे हैं. ये वही राष्ट्रपति शी थे, जिनके साथ मोदी ने बार-बार की मुलाकातों के बाद करीबी रिश्ते विकसित किए थे. तो भी, अगर चीनियों ने अपने मन में यह गलतफहमी पाल ली थी कि उन्होंने मोदी को घेर लिया है, तो मोदी ने चीन के कारोबारी हितों के खिलाफ आक्रामक कदम उठाकर और एलएसी पर भारत की सैन्य ताकत का जमावड़ा करके तेजी से वह गलतफहमी दूर कर दी. इन कदमों में सबसे अहम थी 50 से ज्यादा लोकप्रिय चीनी ऐप पर पाबंदी. इनमें प्रतिमान बन चुका टिकटॉक भी शामिल था. फिर न केवल चीनी ऐप बल्कि साथ ही दूसरे सामान के भी बहिष्कार के लिए जनभावना को उभारा गया. एलएसी पर ढिलाई के लिए मोदी को दोषी ठहराने के बजाए पूरा मामला चीनियों के महान विश्वासघात की तरह चित्रित और पेश किया गया. देश का मिजाज सर्वे में बहुसंख्यक लोग मानते हैं कि मोदी ने चीनियों को मुहंतोड़ जवाब दिया है. यही नहीं, वे सस्ते चीनी सामान खरीदने के बजाए उनके विकल्पों की ज्यादा कीमत अदा करने को तैयार हैं. वे यह भी मानते हैं कि अगर दोनों देशों के बीच जंग छिड़ती है तो भारत विजेता बनकर उभरेगा. यहां मोदी व्यवहार की उस चौथी खूबी को पूरा करते हैं जिसका जिक्र *एचबीआर* का लेख करता है—लोगों से जुड़ो.

चीन के संकट में मोदी ने अब तक फौलादी संकल्प और धैर्य का प्रदर्शन किया है, जो अपने तरीके में करीब-करीब चर्चिल की तरह का है. युद्ध के वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे चर्चिल की यह बात खासी मशहूर है, ''हम न गिरेंगे न लड़खड़ाएंगे; हम न कमजोर होंगे न थकेंगे. न तो जंग का अकस्मात सदमा और न ही एहतियात और मशक्कत के लंबे इम्तिहान हमें धूल धूसरित कर पाएंगे.'' मोदी ने भी अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के रिश्तों का लाभ लिया और उनके नेताओं से चीन की आक्रामक हरकतों की निंदा-भर्त्सना करवाई. भारत अपने इलाकों में चीनी आक्रामकता को दक्षिण चीन सागर में और उसकी दिलचस्पी के दूसरे इलाकों में चीन की कार्रवाइयों के समानांतर खड़ा कर सका. अमेरिका ने इसी काम को आगे बढ़ाया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि अगर माइक्रोसॉफ्ट के साथ खरीद का सौदा परवान नहीं चढ़ा तो वे टिकटॉक पर रोक लगा देंगे. इस तरह मोदी चीन को लेकर भारत की समस्या को दुनिया भर के सरोकार और चिंता में बदलने में कामयाब रहे.

28%

शहरी लोगों की राय में कोविड-19 के प्रति रवैया सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है. ग्रामीण उत्तरदाताओं की बड़ी चिंता बेरोजगारी (25 फीसद) है

मोदी की लोकप्रियता जहां अब भी उफान पर है, वहीं पिछले देश का मिजाज सर्वे बताते हैं कि जनता की तरफ से मिलने वाली यह वाहवाही बेहद क्षणभंगुर हो सकती है. अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने जब नवंबर 2016 में काले धन को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश में रातोरात ऊंचे मूल्य के मौद्रिक नोट बंद कर दिए थे, तब जनवरी 2017 के सर्वे में उनकी लोकप्रियता रेटिंग काफी बढ़ गई थी, बावजूद इसके कि नोटबंदी की वजह से गरीबों और मध्यम वर्ग को खासी मुसीबतें उठानी पड़ी थीं. लेकिन जब इस फैसले का बेअसर होना जाहिर हो गया, तो बाद के सर्वेक्षणों में सरकार की उपलब्धियों की फेहरिस्त में नोटबंदी निचले पायदानों पर चली गई. आज देश जिस संकट से दो-चार है, वह अभी गया नहीं है. मोदी सरकार के आर्थिक कामकाज को मनमोहन सिंह सरकार के आर्थिक कामकाज से बेहतर मानने वाले लोगों की तादाद एक साल पहले के 60 फीसदी से गिरकर अब 43 फीसदी पर आ गई है और यूपीए-2 के बराबर मानने वालों की तादाद भी उससे आगे निकल गई है. कांग्रेस से बेहतर काम का वादा करने वाली सरकार के लिए यह अच्छी खबर नहीं है.

मौजूदा सर्वेक्षण में लोग कोविड-19 से निबटने और नौकरियां देने को सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं के तौर पर देखते हैं. प्रधानमंत्री को उनकी चिंताओं को सुनना चाहिए. उनके सहयोगी कहते हैं कि वे आर्थिक विशेषज्ञों के साथ सिलसिलेवार बैठकें करके पता लगा रहे हैं कि वैश्विक और भारतीय दोनों अर्थव्यवस्थाओं की क्या स्थिति है और तेजी से इसकी बहाली पक्की करने के लिए सरकार को आगे और क्या कदम उठाने की जरूरत है. इन बैठकों में मोदी ज्यादातर सुनते हैं और केवल जरूरी होने पर ही टोकते या बोलते हैं. पीएमओ कार्रवाई के बिंदुओं को दर्ज करता रहता है. प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए घोषित अपनी सरकार की तमाम योजनाओं और उपायों को अमल में लाने पर भी ध्यान दे रहे हैं. वे वही कर रहे हैं, जिसकी वकालत मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर करते हैं, ''नेता संवाद करते हैं ताकि उनके आसपास के लोग जानें कि वे क्या करने का जतन कर रहे हैं. वे जानते हैं कि मिशन की स्थापना कैसे की जाए.'' मोदी ने दिखाया है कि संकट उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को प्रेरित करता है. निर्णायक नेता की यही कसौटी है. देश के लिए भी यही अच्छा है. ■

www.readwhere.com

इंडिया टुडे ग्रुप-कार्वी इनसाइट्स

देश का मिजाज
जनमत सर्वेक्षण

अर्थव्यवस्था

स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में

अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के विनाशकारी असर के बावजूद लोग इससे निबटने के लिए मोदी सरकार का व्यापक समर्थन करते दिखाई देते हैं

एम.जी. अरुण

बोलता सन्नाटा
दिल्ली के सदर बाजार का अप्रैल का एक दृश्य, सामान्य दिनों में यहां चलने को जगह न मिलती थी

www.readwhere.com

इस साल दुनिया भर की सरकारें जबरदस्त पसोपेश में पड़ गईं. कोविड-19 ने उन्हें बस इतनी रियायत बख्शी कि या तो वे ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने नागरिकों की जान या फिर अधिकतम संख्या में उनकी आवीजिका बचा लें. ज्यादातर की तरह भारत सरकार ने भी जान बचाने का विकल्प चुना. ऐसा करते हुए उसे आजाद भारत की एक सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा और वह थी अर्थव्यवस्था का तेजी से गर्त में धंसते जाना. ज्यादातर विश्लेषक संपूर्ण मंदी की आशंका को खारिज करते हुए कहते हैं कि यह बुरी हालत कुछेक तिमाहियों तक सीमित रहेगी, वहीं इस हकीकत से बचा नहीं जा सकता कि भारत की वृद्धि दर जबरदस्त गिरावट के दौर में पहुंच गई है. जहां इस बात को लेकर बहस चल रही है कि यह गिरावट कितनी है, यानी क्या भारत की वृद्धि दर पांच फीसद या उससे भी नीचे तक गिर गई है?

पंकज नांगिया

वहीं कोविड-19 की वजह से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और उसके बाद कुछ इलाकों में स्थानीय स्तरों पर लॉकडाउन के जो आर्थिक नुक्सान हुए, वे वाकई हलचल पैदा करने वाले हैं.

फिर हैरानी क्या कि लॉकडाउन के दौरान किए गए इंडिया टुडे देश का मिजाज सर्वे में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के दिमाग में आर्थिक मुद्दे सबसे ज्यादा हावी थे. सर्वे में शामिल 63 फीसद जितनी भारी तादाद में लोगों ने कहा कि हाल में उनकी आमदनी में गिरावट आई है, जबकि 22 फीसद ने कहा कि वे अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं. कृषि और कुछ हद तक 'अनिवार्य वस्तुओं' की आपूर्ति को छोड़कर अर्थव्यवस्था के तकरीबन तमाम क्षेत्रों में 24-25 मार्च की आधी रात के बाद लॉकडाउन के पहले महीने में ठहराव आ गया. आवाजाही पर पाबंदियों और 'अनिवार्य वस्तुओं' की अस्पष्ट परिभाषा का लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर गहरा असर पड़ा, जब हजारों ट्रक राजमार्गों पर फंस गए. केंद्र की ढेरों अधिसूचनाओं से अफरातफरी और बढ़ गई, जब नीतिगत गफलतों के चलते राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय केंद्र के नियम-कायदों की अपने-अपने ढंग से व्याख्याएं करने लगे. यहां तक कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दूसरी जगहों पर कुछ हद तक दोबारा खोलने की इजाजत दी भी गई, तो सामाजिक दूरी के सख्त नियमों के चलते आपूर्ति शृंखलाओं के तहस-नहस होने का खमियाजा कारोबार को भुगतना पड़ा. सबसे ज्यादा गिरावट मांग में आई, सो अलग. नकदी के प्रवाह पर बड़ी चोट पड़ी और हॉस्पिटैलिटी तथा एयरलाइंस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल क्षेत्रों तक की कंपनियों को नौकरी में कटौतियां, तनख्वाहों में काट-छांट और नई भर्तियां बंद करनी पड़ीं. मैनपावर फर्म ग्लोबल कंसल्टेंट की एक रिपार्ट कहती है कि महामारी की वजह से भारत में करीब 13 करोड़ नौकरियों का खत्म होना तय है, जिनमें से 40 फीसद ब्लू-कॉलर नौकरियां यानी हाथ से किए जाने वाले काम होंगे.

महिंद्रा ग्रुप में मानव संसाधन (एचआर) के

सवाल: मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को जिस तरह से संभाला उसे आप किस तरह से देखते हैं?

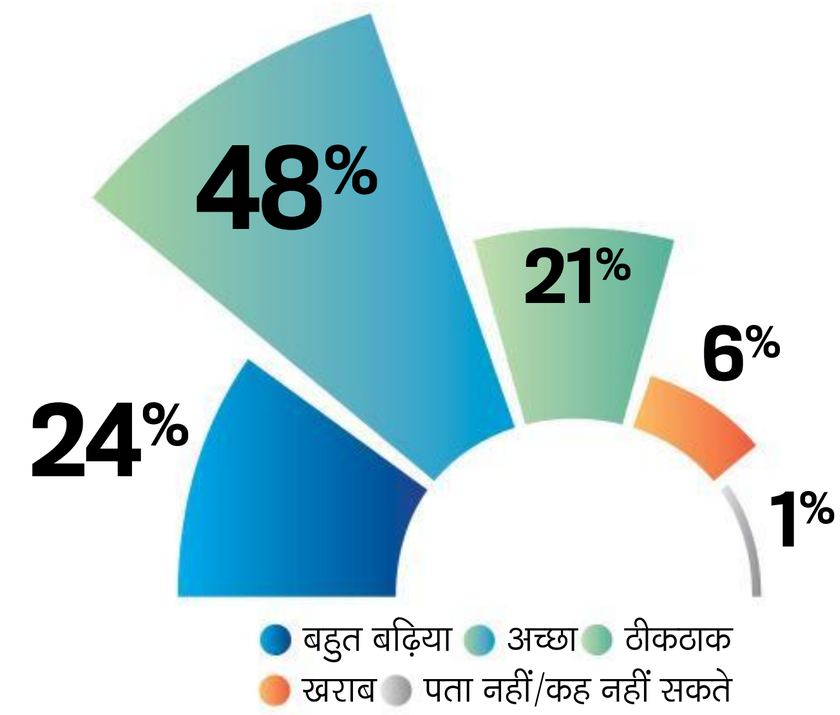

सवाल: 2014 में मोदी के कुर्सी संभालने के बाद से आपके आर्थिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है?

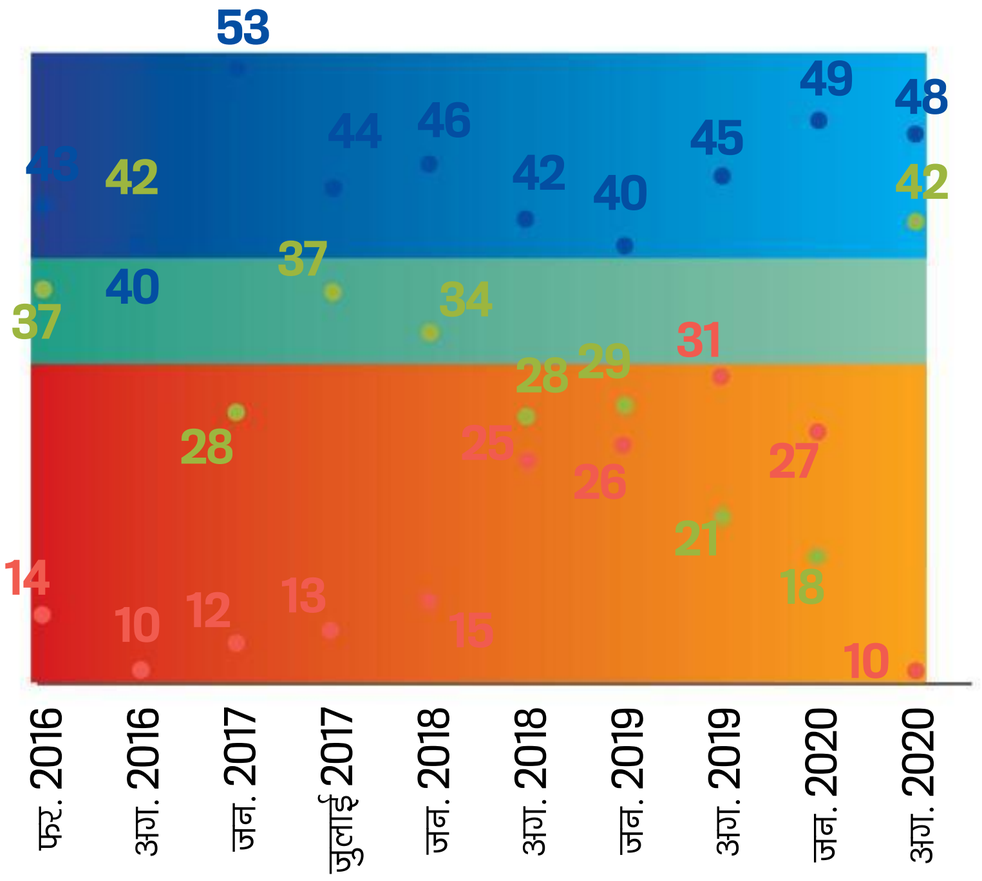

(पता नहीं/कह नहीं सकते भी इसी में शामिल, ग्राफ में नहीं दिखाया गया)

सवाल: अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मनमोहन सिंह सरकार के मुकाबले मोदी सरकार के प्रदर्शन को आप किस तरह से देखते हैं?

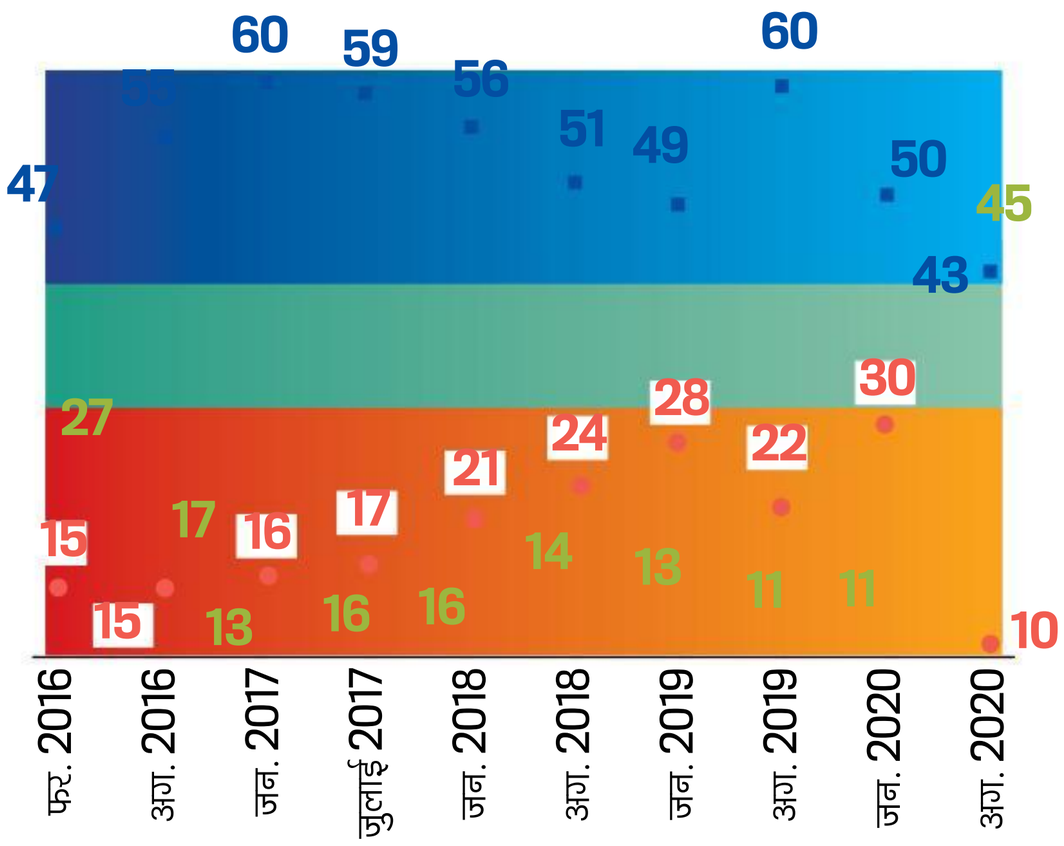

(पता नहीं/कह नहीं सकते भी इसी में शामिल, ग्राफ में नहीं दिखाया गया)

सवाल: कोविड-19 ने आर्थिक रूप से आपके ऊपर कैसा असर डाला?

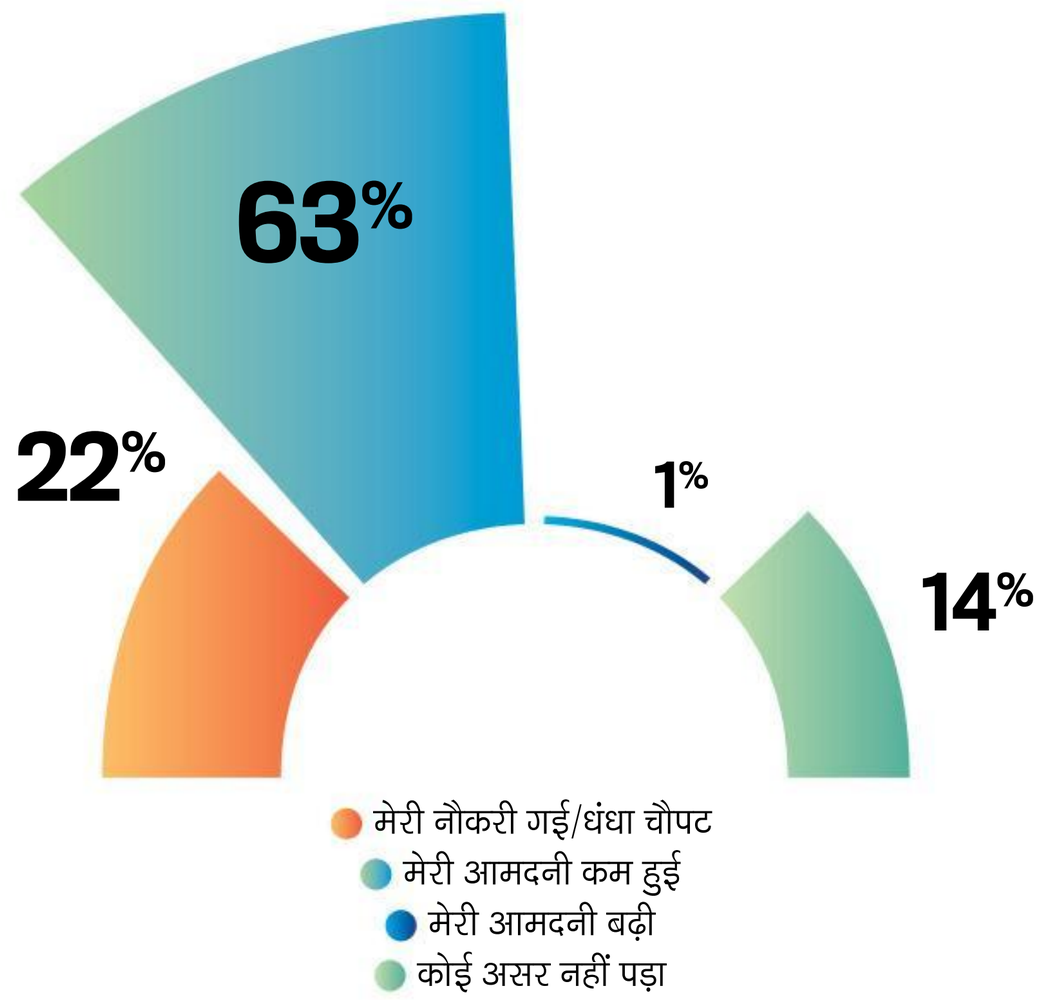

पूर्व प्रेसिडेंट और अब कार्यबल से जुड़े मामलों में कंपनी के सलाहकार राजीव दुबे कहते हैं कि कामगारों में बहुत ज्यादा डर और अनिश्चितता है. कंपनियां अनुभवी कर्मचारियों की भी छंटनी कर रही हैं और ऐसे में ऊंचे स्तर का तनाव साफ दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल सरीखे क्षेत्रों में, जहां मांग रसातल में पहुंच गई है. बाजार हिस्सेदारी के लिहाज से देश की सबसे बड़ी विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने अपने कामगारों में 10 फीसद या करीब 2,300 कर्मचारियों की छंटनी की. क्रिसिल की एक रिपोर्ट एयरलाइन उद्योग पर लॉकडाउन के दूरगामी असर की तरफ इशारा करती है, जो सेवाओं के कुछ हद तक दोबारा शुरू होने के बाद भी पड़ेगा. रेटिंग एजेंसी कहती है कि भारत में हवाई यात्री यातायात घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों क्षेत्रों में क्रमश: 40-45 फीसद और 60-65 फीसद तक घटने की संभावना है. मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र भी गहरी मुश्किल में है. यहां तक कि स्टील और इंजीनयरिंग के भारी सामान का उत्पादन भी लॉकडाउन से पहले के दौर के मुकाबले अब भी करीब आधा ही है. ऐसे में यह होना ही था कि सर्वे में शामिल 23 फीसद लोगों ने कहा कि मोदी सरकार की एक ही सबसे बड़ी नाकामी बेरोजगारी है. इतना ही नहीं, सर्वे में शामिल 54 फीसद लोग अगले छह महीनों में हालात बेहतर होते नहीं देखते या फिर वे भविष्य को लेकर खासे अनिश्चित हैं.

23%

उत्तरदाताओं का मानना था कि बेरोजगारी से न निबट पाना मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बनी हुई है

54%

उत्तरदाताओं की राय में अगले छह महीने में हालात सुधरने के संकेत नहीं दिखते या इस बारे में वे शर्तिया तौर पर कुछ कह नहीं सकते

इस हताश फलक के बावजूद लोग आर्थिक परेशानियों से निबटने के मामले में मोदी सरकार का मोटे तौर पर समर्थन करते दिखाई देते हैं. सर्वे में शामिल 71 फीसद जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने इस क्षेत्र में उसके कामकाज को असाधारण या अच्छा आंका. कुल मिलाकर सरकार यह छाप छोड़ती मालूम देती है कि हालात उसके काबू में हैं, चाहे वह राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के जरिए वायरस से निबटना हो या सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की तरफ से दिए गए 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज के जरिए आर्थिक संकट को संभालना हो. ऐसा लगता नहीं कि इस प्रोत्साहन पैकेज ने उद्योग के लिए बहुत कुछ किया है, बावजूद इसके कि इसमें, मिसाल के तौर पर, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का

www.readwhere.com

सवालः अगले छह महीनों के बारे में आपका क्या अनुमान है?

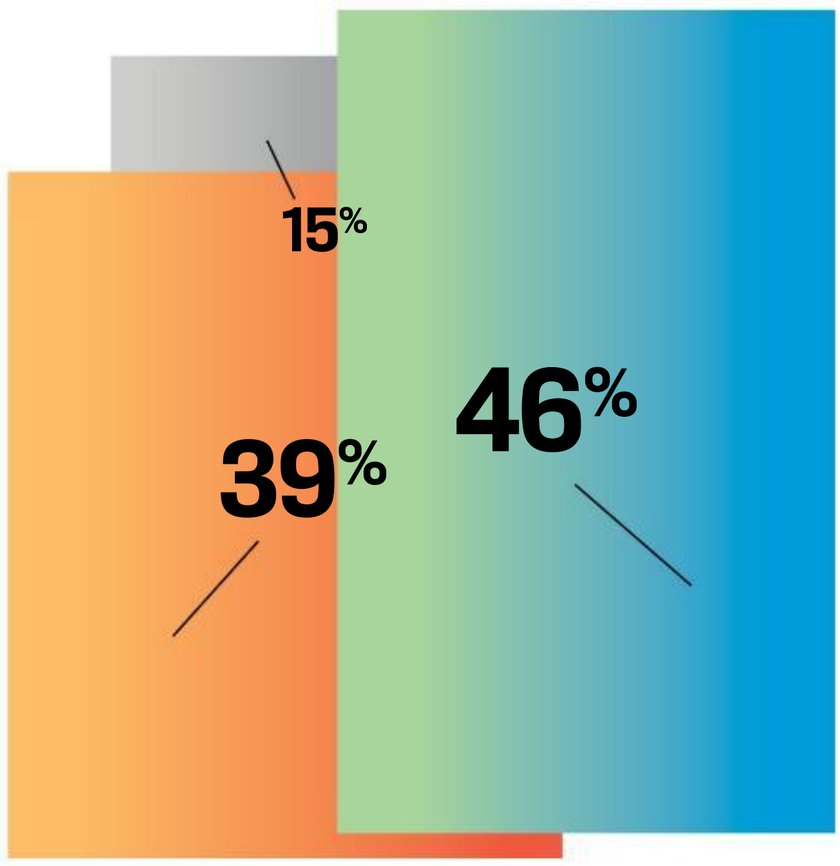

सवालः कोविड-19 के चलते उपजी आर्थिक दुश्वारियों से मोदी सरकार जिस तरह से निबटी, उसे आप किस तरह से देखते हैं?

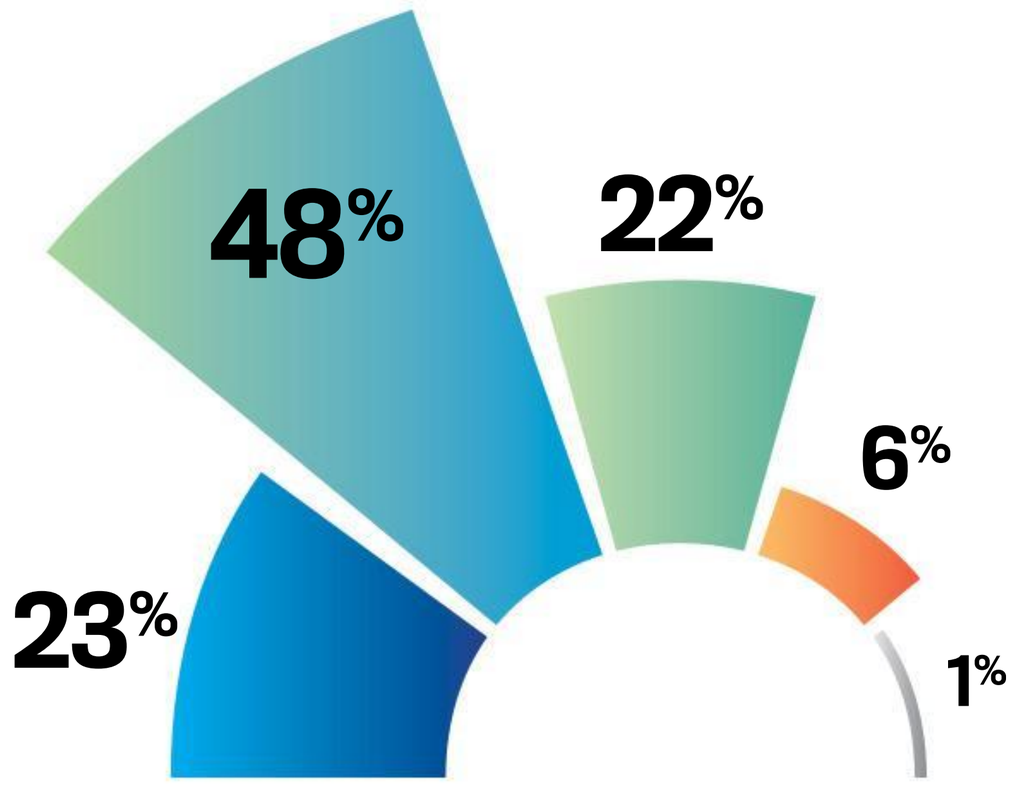

पैकेज भी शामिल है. लेकिन कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहीं बेहतर प्रदर्शन करती मालूम देती हैं. रबी की अच्छी फसल, सरकार की तरफ से खरीद का जबरदस्त अभियान और किसानों को साल में 6,000 रुपए देने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने, लगता है ग्रामीण मांग को बढ़ाने में खासी मदद की है. इस सबने ग्रामीण इलाकों में खुशी के एहसास का माहौल पैदा किया हो सकता है, हालांकि डर इस बात का है कि यह एहसास शायद टिकाऊ न हो. इस मामले में लोगों की राय बंटी दिखाई देती है. सर्वे में शामिल 48 फीसद लोगों ने माना कि 2014 में मोदी के कमान संभालने के बाद उनकी आर्थिक हैसियत में सुधार आया है, वहीं 42 फीसद ने कहा कि उनकी माली हालत जस की तस है, जबकि 10 फीसद ने कहा कि उनकी स्थिति और ज्यादा खराब हुई है. यहां गौर करने लायक बात यह है कि जिन लोगों ने कहा कि मोदी के कमान संभालने के बाद उनकी हालत जस की तस है, उनका प्रतिशत जनवरी 2019, अगस्त 2019 और जनवरी 2020 के देश का मिजाज सर्वेक्षणों के क्रमशः 29 फीसद, 21 फीसद और 18 फीसद से बढ़ गया है. यह बढ़ोतरी उन लोगों की वजह से हुई है जिन्हें पहले लगता था कि मोदी सरकार के मातहत उनकी आर्थिक हैसियत में दरअसल गिरावट आई है. जनवरी 2019 के देश का मिजाज सर्वे में मोदी के मातहत अपनी

सर्वे में शामिल 71% लोगों का कहना था कि **महामारी के आर्थिक असर से बेहतर ढंग से या असाधारण ढंग से** निबटा गया

हालत में गिरावट महसूस करने वाले लोग सर्वे में शामिल कुल लोगों के 26 फीसद थे, जबकि अगस्त 2019 में वे 31 फीसद और जनवरी 2020 में 27 फीसद थे. यही वह समूह है जिसमें देश का मिजाज के मौजूदा सर्वे में तेज गिरावट आई है और वे 10 फीसद रह गए हैं. नजरिए में बदलाव की एक वजह वे तमाम उपाय हो सकते हैं जिनका ऐलान वित्त मंत्री ने लॉकडाउन के बाद के दिनों में किया था और जिनमें वे उपाय भी शामिल थे जिनका लक्ष्य खासकर ग्राणीण इलाके थे.

सर्वे में शामिल 43 फीसद लोगों ने कहा कि मोदी सरकार का आर्थिक कामकाज कांग्रेस की अगुआई वाली यूपीए सरकार के मुकाबले बेहतर रहा है, जबकि 45 फीसद ने कहा कि यह यूपीए के कामकाज के बराबर ही है. केंद्र के समर्थन में साफ बढ़ोतरी भी हुई है. जनवरी 2020 के पिछले देश का मिजाज सर्वे में 30 फीसद लोगों ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को यूपीए से बदतर आंका था. इस सर्वे में यह आंकड़ा गिरकर 10 फीसद पर आ गया है. यहां भी इस सकारात्मक धारणा की वजह रबी की बंपर फसल, खरीफ की रिकॉर्ड बुआई और गांव-देहातों पर केंद्र का जोर रहा हो सकता है, जिससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आया है.

अक्सर कहा जाता है कि अच्छे संकट को कभी बेकार नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि हर संकट अपने साथ कुछ न कुछ रचनात्मक

www.readwhere.com

प्रतिक्रिया का अवसर लेकर आता है. कोविड-19 महामारी ने जो तबाही मचाई, वह तो खैर मचाई ही, लेकिन इसने केंद्र सरकार को साहसी आर्थिक सुधारों की घोषणा का मौका भी दिया. इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'आत्मनिर्भर भारत' का राग भी शामिल है, जिसमें आर्थिक वृद्धि में जान फूंकने की खातिर जमीन और श्रम कानूनों में ढांचागत सुधार और तरलता में बेहतरी के जरिए भारत को मजबूत आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाने का संकल्प लिया गया. सरकार की रणनीति में शामिल चार स्तंभों में सक्षम बुनियादी ढांचा विकसित करना, टेक्नोलॉजी से चलने वाली प्रणालियां विकसित करना, देश की जोश से भरी जनसांख्यिकी को इस्तेमाल में लाना और घरेलू मांग में तेजी लाना शामिल हैं. कोविड-19 से पैदा आर्थिक संकट के बावजूद इन घोषणाओं ने यह धारणा बनाने में योगदान दिया कि संकट को वाकई अच्छी तरह संभाला गया है.

प्रो

त्साहन पैकेज का एक सबसे बड़ा लक्ष्य एमएसएमई क्षेत्र था. इसमें 6 करोड़ फर्म आती हैं, जो भारत के जीडीपी में करीब 29 फीसद का योगदान और तकरीबन 12 करोड़ लोगों को रोजगार देती हैं. यह उन क्षेत्रों में से था जिन पर महामारी और उसके बाद लगाए गए लॉकडाउन की सबसे बदतर मार पड़ी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई क्षेत्र को लक्ष्य करके छह निश्चित पहल का ऐलान किया था. इनमें ये उपाय भी शामिल थे—3 लाख करोड़ रुपए का जमानत मुक्त कर्ज और उसके साथ कर्ज की 100 फीसद गारंटी, जिससे 45 लाख इकाइयों को फायदा मिलने की उम्मीद थी; संकट में फंसे एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए के छोटे कर्ज, जिनसे 2,00,000 फर्मों को फायदा मिल सकता था और इनमें बकाया कर्जों वाली वे फर्म भी थीं जिनके कर्जों को संकटग्रस्त या गैर-निष्पादित परिसंपतियां मान लिया गया था; और 10,000 करोड़ रुपए के साथ एक कोष की स्थापना के जरिए एमएसएमई में 50,000 करोड़ रुपए की अंशपूजी लगाना.

वित्त मंत्री ने जिन अन्य उपायों का ऐलान किया, उनमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), आवासीय वित्त कंपनियों और सूक्ष्मवित्त संस्थाओं (एमएफआइ) के लिए 30,000 करोड़ रुपए की एक विशेष तरलता योजना; एनबीएफसी और एमएफआइ की देनदारियों के लिए 45,000 करोड़ रुपए की आंशिक ऋण गारंटी योजना; और ऊर्जा वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए 90,000 करोड़ रुपए की तरलता मुहैया करने की योजना शामिल थीं. रियल एस्टेट क्षेत्र की फर्मों को भी कुछ राहत दी गई. मसलन, लॉकडाउन की वजह से जिन डेवलपर की परियोजनाएं रुक गई थीं, उन्होंने रेरा (रियल एस्टेट नियामकीय प्राधिकरण) के तहत अनुपालन की समयसीमाओं में ढील के चलते कुछ राहत की सांस ली. वहीं एक निश्चित सीमा से कम

सवाल: क्या महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए लाया गया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आपकी आर्थिक दशा बदलने के लिए काफी था?

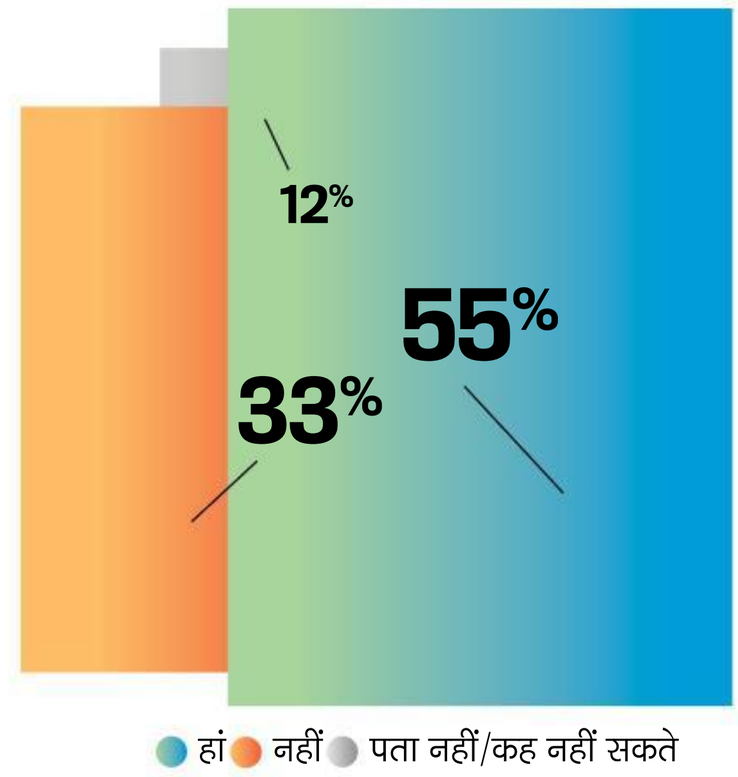

सवाल: नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में आप क्या सोचते हैं?

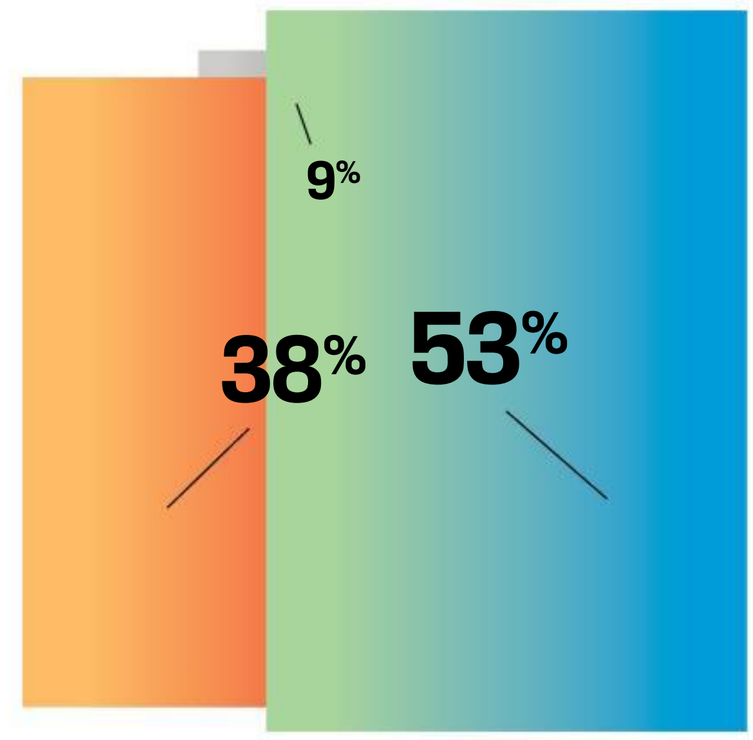

सवाल: क्या आपको लगता है कि सरकार की नीतियों ने बड़े बिजनेस को लाभ पहुंचाया और छोटे कारोबार की अनदेखी की?

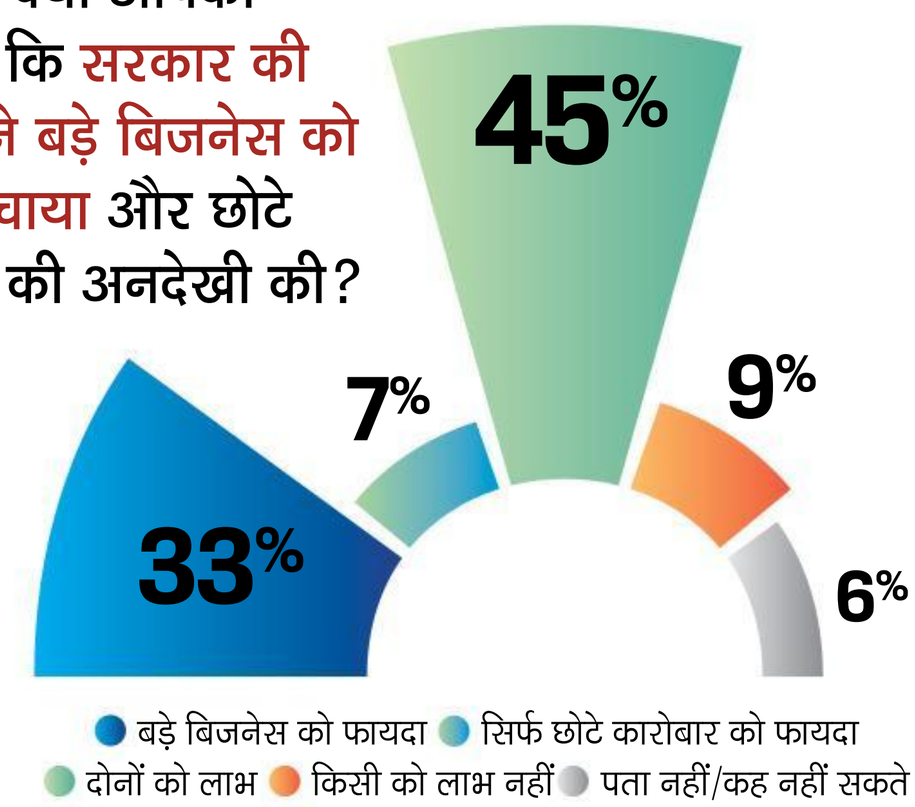

www.readwhere.com

आमदनी वाले शहरी रहवासियों के घर कर्ज पर अनुदान देने वाली कर्ज से जुड़ी सब्सिडी योजना को एक साल बढ़ाकर सस्ते घरों की मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद की गई. जब पूछा गया कि क्या वे आर्थिक संकट से निबटने के लिए सरकार की इन तमाम योजनाओं में से किसी एक के तहत कर्ज लेना चाहेंगे, 58 फीसद उत्तरदाताओं ने कहा कि वे वाकई लेना चाहेंगे, जबकि 34 फीसद ने इसका जवाब नहीं में दिया.

इस बीच, रिजर्व बैंक ने भी तरलता में सुधार के लिए कई कदम उठाए. इनमें बैंकों को कर्ज की अदायगी पर अपने उपभोक्ताओं को तीन माह के मोरेटोरियम की पेशकश की छूट देना और लॉकडाउन की शुरुआत के बाद से ही केवल लंबी अवधि के रेपो ऑपरेशनों के जरिए बैंकिंग प्रणाली में 1.12 लाख करोड़ रुपए की अंशपूंजी डालना शामिल था. हालांकि इन उपायों के असर के आकलन के लिहाज से अभी ये शुरुआती दिन हैं और इनमें से कुछ के असर केवल मध्यम से लंबी अवधि में दिखाई देंगे, लेकिन आम जनता मोटे तौर पर संतुष्ट नजर आती है. सर्वे में शामिल 55 फीसद जितनी अच्छी-खासी संख्या में लोगों ने कहा कि प्रोत्साहन पैकेज उनकी माली हालत में बदलाव लाने के लिए काफी था, जबकि इससे खासे कम 33 फीसद लोगों ने कहा कि नहीं, यह काफी नहीं था. तो भी आम लोगों का एक तबका है जो महसूस करता है कि खासकर जरूरतमंद लोगों के हाथ में और ज्यादा रकम देने के लिहाज से और ज्यादा किया जाना चाहिए था. एमएसएमई क्षेत्र के लिए जरूरत तनख्वाहें देने और मौजूदा कर्जों पर ब्याज चुकाने के लिए मदद देने की थी, न कि नए कर्ज मुहैया करवाने की.

सवाल: आर्थिक संकट से निबटने के लिए सरकार की शुरू की गई योजनाओं में से किसी के तहत क्या आप कर्ज लेंगे?

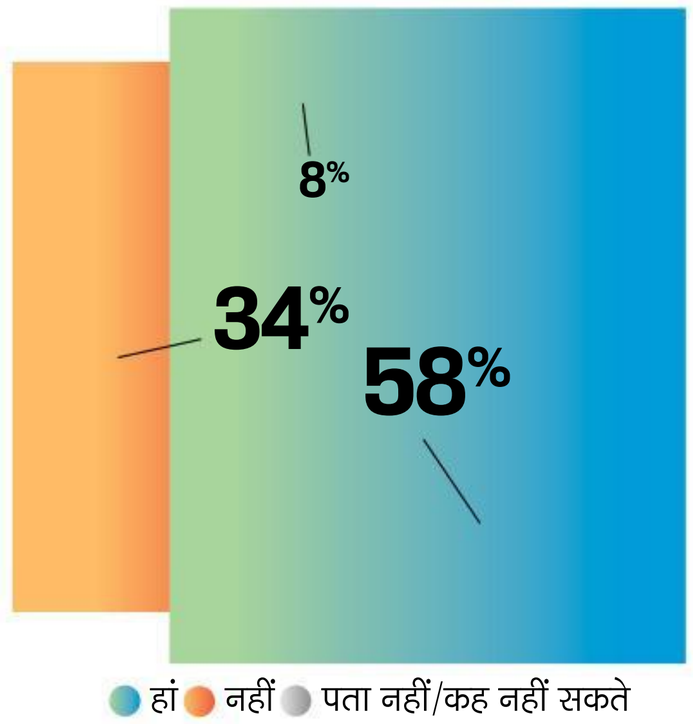

लगता है आत्मनिर्भर भारत अभियान ने किसी न किसी रूप में आम जनता के मन पर अपनी छाप छोड़ी है. सर्वे में शामिल आधे से ज्यादा 53 फीसद लोगों ने कहा कि यह बिल्कुल सही समय पर छेड़ा गया अभियान है, जबकि 38 फीसद की राय है कि भारत के पास आत्मनिर्भर बनने की क्षमता अब भी नहीं है. (सरकार की बुनियादी 'मेक इन इंडिया' पहल बेशुमार नीतिगत देरियों और अफसरशाही के अड़ंगों की बदौलत दम तोड़ चुकी है.) हालांकि कोविड-19 के बाद की दुनिया में, जहां कई देश अपने भीतर ध्यान केंद्रित कर रहे और शायद व्यापार के लिए रुकावटें खड़ी कर रहे होंगे, हो सकता है 'आत्मनिर्भरता' का नया नजरिया ही सही नुस्खा हो. अहम बात अलबत्ता यह है कि भारत अपनी आर्थिक रीढ़ यानी एमएसएमई क्षेत्र को किस तरह खड़ा करता है. चीन का उभार बताता है कि यह हासिल करना मुमकिन भी है और जरूरी भी. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) के चीफ इकोनॉमिस्ट सौम्यकांति घोष ने कहा है कि भारत पांच साल की अवधि में अपने निर्यात 20-194 अरब डॉलर के दायरे में कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा वह तभी कर सकता है जब क्षमताओं का निर्माण करे और चीन से बाजार हिस्सेदारी छीन ले.

इस मामले में अभी बहुत कुछ करना बाकी है. इस साल मई में एसबीआइ के एक नोट में कहा गया कि विश्व बैंक के 'कारोबार करने में आसानी' सूचकांक में रैंकिंग में सुधार लाने के बावजूद भारत अपने पारंपरिक निर्यात बाजारों में भी हाथ-पैर मार रहा है. विशेषज्ञ बताते हैं कि महज बड़े निवेशकों के लिए चीजें आसान बनाने से न तो अर्थव्यवस्था की वृद्धि में मदद मिलती है और न ही देश के भीतरी भूभागों में नौकरियों में इजाफा होता है. भारत को विदेशी निवेशों पर नतीजों से जुड़ी निश्चित शर्तें लगानी होंगी, जैसा चीन ने किया.

दूसरों का कहना है कि हमें नियम-कायदों में उन आंशिक बदलावों की नाकामी से सीखना चाहिए, जो विशेष आर्थिक जोन के लिए किए गए थे, और ऐसे जोन का निर्माण करना चाहिए जो मौजूदा औद्योगिक और श्रम कानूनों से पूरी तरह मुक्त हों और जहां अनुपालन की प्रक्रियाएं ज्यादा सरल हों. उनका कहना है कि सरकार को 'चीनी उत्पादों के बहिष्कार' के नारे से आगे जाना चाहिए और जिन इलाकों में संभावना है, वहां विश्वस्तरीय क्षमताओं का निर्माण करना चाहिए, ताकि भारत वैश्विक फलक पर प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी बन सके.

महामारी के आर्थिक नतीजों को संभालने के लिए सरकार को जो भी वाहवाही मिलती दिखाई दे रही है, उसके बावजूद यह एहसास भी कहीं न कहीं सिर उठा रहा है कि सरकार की नीतियों ने केवल बड़े कारोबारों को फायदा पहुंचाया और छोटे कारोबारों को नजरअंदाज किया है. सर्वे में शामिल एक-तिहाई (33 फीसद) लोगों ने कहा कि सरकार की नीतियों ने बड़े कारोबारियों की मदद की, जबकि 45 फीसद ने कहा कि दोनों को ही फायदा मिला है.

आर्थिक मोर्चे पर आने वाली तमाम डरावनी खबरों के बावजूद देश का मिजाज सर्वे इशारा करता है कि मोदी सरकार कामयाबी के साथ यह बात लोगों के गले उतारने में कामयाब रही है कि वह हालात में सुधार के लिए तमाम उपाय लागू कर रही है और साथ ही लंबे वक्त के लिए भारत को आत्मनिर्भर बना रही है. यह भलीभांति बताता है कि अब तक कोविड-19 को संभालने की अपनी कोशिशों के लिए केंद्र सरकार को सर्वे में शामिल लोगों का इतना ठोस समर्थन क्यों मिल रहा है. अलबत्ता अर्थव्यवस्था अगर लंबे वक्त तक बदहाली के दौर में रहती है और रोजगार तथा आमदनी के मोर्चे पर हालात और बिगड़ते हैं, तो यह भावना छूमंतर होकर नाराजगी में बदल सकती है. इससे आत्मसंतोष के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती. सरकार को अपने असलहे में मौजूद तमाम हथियारों के साथ महामारी और उसके भारी-भरकम आर्थिक नतीजों से लड़ना जारी रखना ही चाहिए. ■

www.readwhere.com

इंडिया टुडे ग्रुप-कार्वी इनसाइट्स

देश का मिजाज जनमत सर्वेक्षण

कोविड -19

डरने की बात नहीं

कोविड महामारी के उफान पर होने के बावजूद जनता का सरकार और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे पर विश्वास मजबूती से बना हुआ है

सोनाली आचार्जी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को जब देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था, उस वक्त दुनियाभर में कोविड का आंकड़ा वास्तव में खतरनाक स्तर पर था. अमेरिका ने 52,690 मामलों और 681 मौतों की सूचना दी थी; इटली में 69,176 मामले और 6,820 मौतें और जर्मनी में 27,436 मामले और 114 मौतें हुईं थी. तब भारत में संक्रमण के 519 मामले थे और 10 लोगों की जान गई थी. देश में जब चौतरफा बंद हुआ तो उसका असर धीरे-धीरे हर क्षेत्र में महसूस होने लगा—आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा आने लगी, रोजाना लाखों की तादाद में लोगों की आजीविका के स्त्रोत खत्म होने लगे और दूसरी बीमारियों का इलाज तक मुश्किल हो गया. इन सबके बीच कोविड संक्रमितों की गिनती भी बढ़ती रही.

आज, भारत कोविड संक्रमित लोगों की संख्या के लिहाज से दुनिया में तीसरे पायदान पर है, लेकिन देश के आकार और इसकी आबादी को देखते हुए इस स्थिति को टालना संभव भी न था. महामारी से लड़ने के दौरान हमारी कुछ उपलब्धियां भी रही हैं: देश भर में अस्पताल के बुनियादी ढांचे में सुधार, कोविड मामलों के लिए अस्पतालों के लिए विशिष्ट मानक प्रोटोकॉल, कोविड की रोकथाम से जुड़े मानदंडों के बारे में अधिक जन जागृति और वायरस शरीर पर कैसे हमला करते हैं, इन सब बातों को लेकर एक बेहतर समझ विकसित हुई है. लॉकडाउन ने राज्य प्रशासन और हमारे स्वास्थ्य तंत्र को उस लंबी दौड़ की तैयारी के लिए समय दिया जो इस लड़ाई के लिए जरूरी है. जो महामारी के शुरुआती महीनों में दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल लोक नायक जय प्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल के चिकित्सा निदेशक रहे डॉ. जेसी पासे कहते हैं, ''मार्च में हम कोविड की समझ बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे—मरीजों का इलाज कैसे करें, उनके लिए बेड की व्यवस्था किस प्रकार करें और कर्मचारियों की सुरक्षा कैसे करें. हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली अपने

चलो लौट चलें
मुंबई में घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन ले जाए जाने का इंतजार करते प्रवासी मजदूर

मंदार देवधर

सवालः कोविड-19 से निबटने के मामले में दूसरे देशों के मुकाबले भारत की सामूहिक प्रतिक्रिया कैसी रही है?

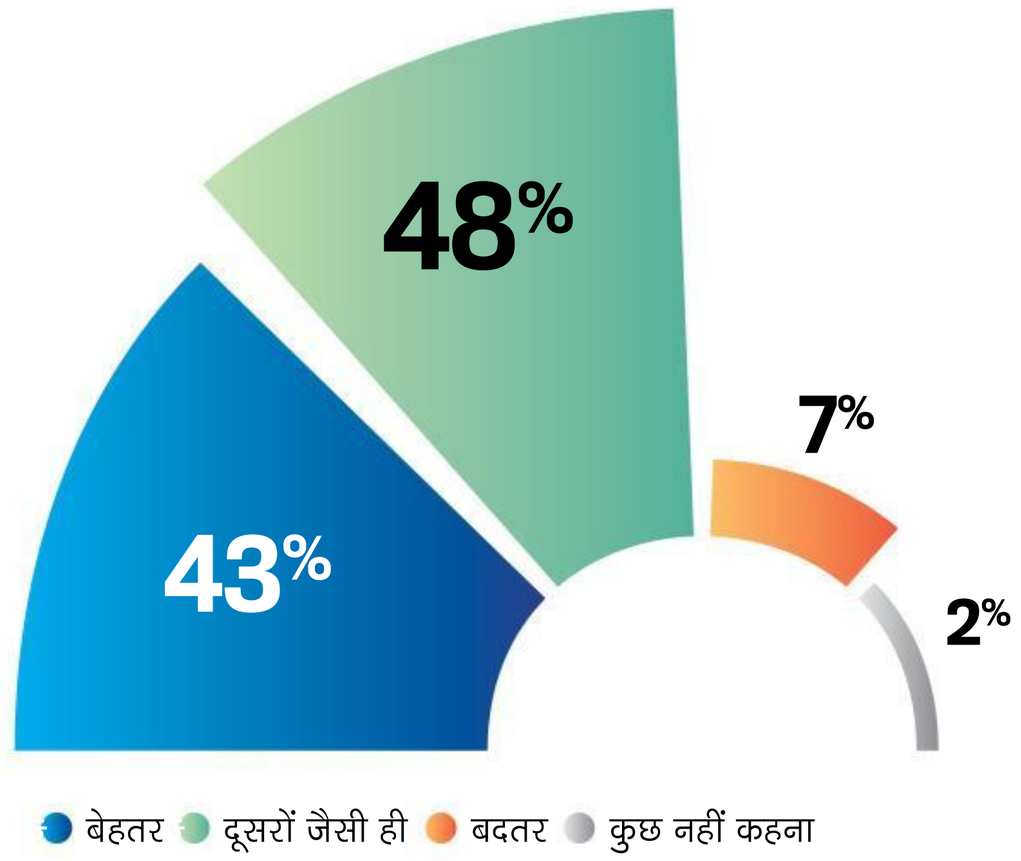

www.readwhere.com

सवालः क्या केंद्र सरकार को प्रवासी मजदूरों की मदद के मद वाली रकम सीधे उनके खातों में डाल देनी चाहिए थी?

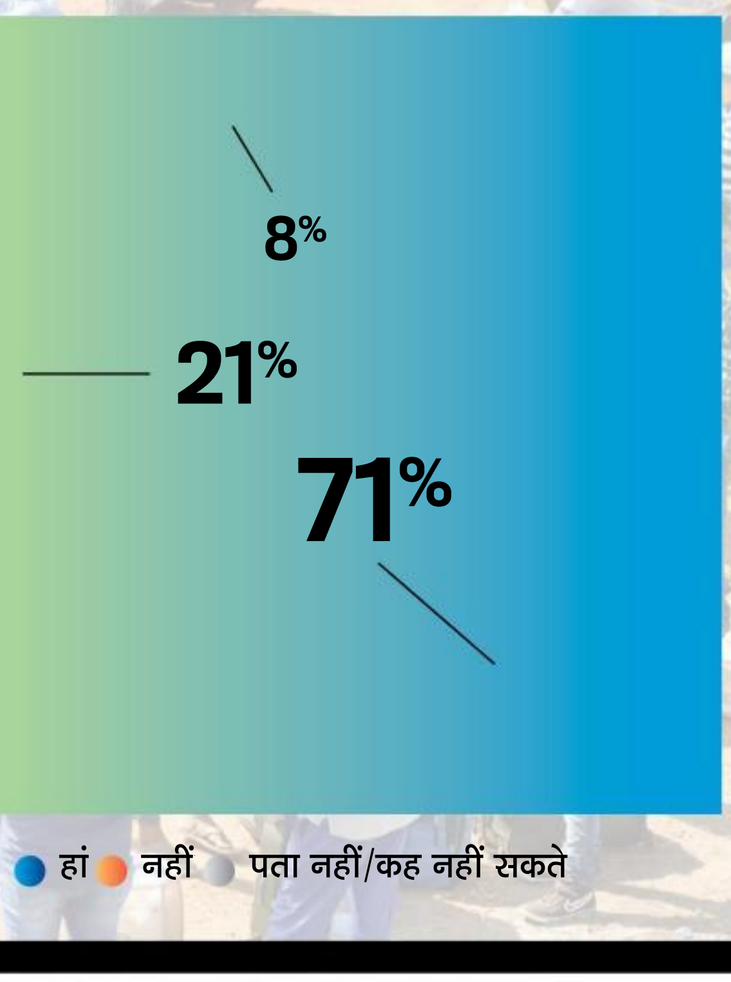

सवालः क्या लॉकडाउन से बड़े पैमाने पर लोगों की जान बची जैसा कि सरकार का दावा है?

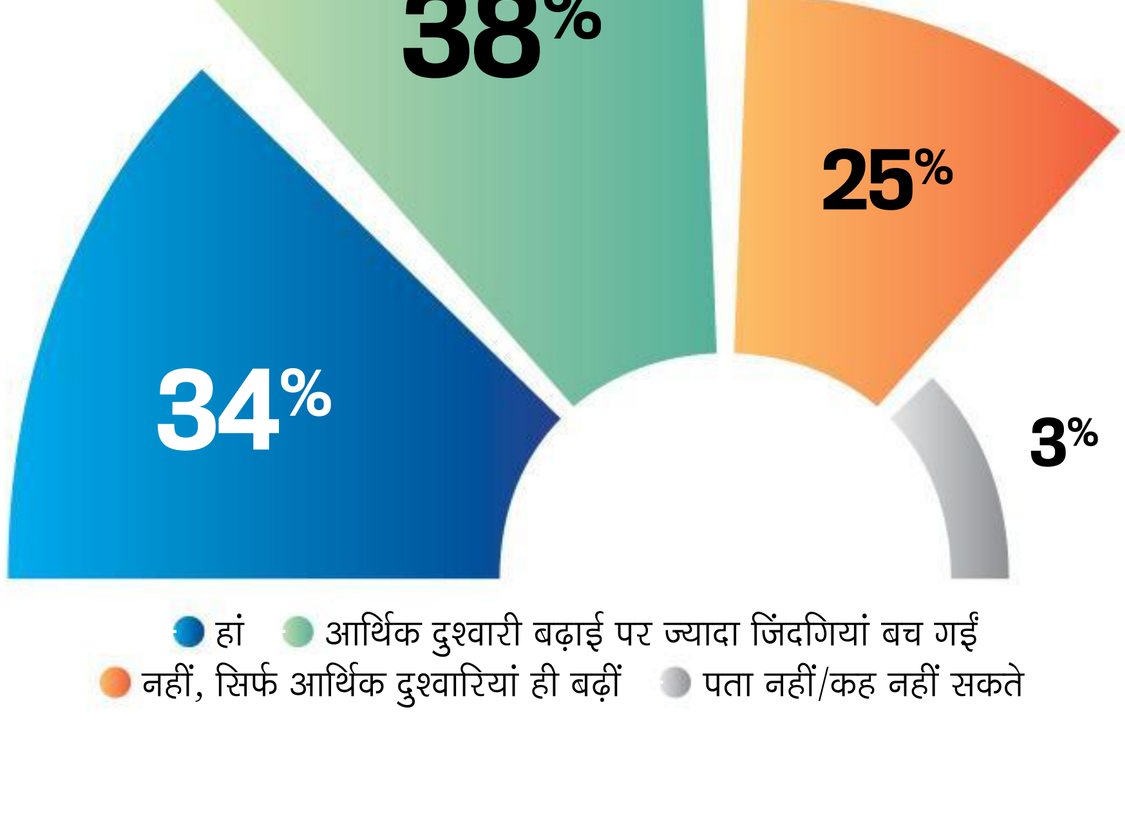

पैरों पर कभी खड़ी नहीं थी. हमने घुटनों के बल चलना शुरू किया और अब पांव पर मजबूती से खड़े हुए हैं.''

कोविड के खिलाफ भारत की वास्तविक सफलता को उन जिंदगियों के रूप में देखा जा सकता है जिन्हें बचा लिया गया. 3 अगस्त को संक्रमितों के स्वस्थ होने की 65.77 प्रतिशत की दर के साथ भारत दुनिया में सबसे आगे है. मार्च में लॉकडाउन के ऐलान के वक्त संक्रमण के मामलों के दोगुना होने का औसत समय 3.4 दिन का था जो बढ़कर 21 दिन हो गया है. कोविड के कारण जान गंवाने लोगों का आंकड़ा 3 अगस्त को 2.11 फीसदी था जो कोविड के प्रकोप के बाद सबसे कम है.

अगस्त 2020 में *इंडिया टुडे* के देश का मिजाज सर्वेक्षण (एमओटीएन) के नतीजे भी इन सफलताओं को लेकर जनता की स्वीकार्यता दर्शाते हैं. बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं ने कोविड को लेकर स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों के लिए सरकार की सक्रियता को सराहा है. 48 फीसद लोगों का मानना था कि कोविड पर भारत की प्रतिक्रिया दूसरे देशों के बराबर रही है. 43 फीसद इसे दुनिया के बाकी हिस्सों से बेहतर मानते हैं. वास्तव में, किसी दूसरे देश ने भारत जितना लंबा लॉकडाउन नहीं किया. चार चरणों के लॉकडाउन ने धीरे-धीरे लोगों को अपने जीवन को इसके अनुरूप ढालने

www.readwhere.com

में मदद की और जिससे वायरस के प्रसार की गति धीमी हुई. मुंबई के जसलोक अस्पताल में संक्रामक रोगों के प्रमुख डॉ. ओम श्रीवास्तव कहते हैं, ''कोई भी पूरे दिन घर में कैद नहीं रहना चाहता पर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी की स्थिति में, एहतियाती देखभाल अनिवार्य करना जरूरी हो जाता है. मार्च में कोई भी मास्क नहीं पहन रहा था क्योंकि हमारा मानना था कि वायरस छूने से फैलता है. आज हर जगह लोग मास्क में दिखते हैं. पर हमने उस दौरान लोगों को एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से घुलने-मिलने की आजादी न देकर वह समय व्यर्थ नहीं जाने दिया.''

सर्वे के निष्कर्ष इस बात का भी संकेत देते है कि जनता के लिए आखिर क्या ज्यादा मायने रखता है—जीवन या आजीविका. 72 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि लॉकडाउन ने उनका जीवन बचाया और सरकार का भी ऐसा ही दावा है. 38 प्रतिशत मानते हैं कि इसने आर्थिक संकट पैदा किया. बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं (34 प्रतिशत) ने यह भी माना कि उनका जीवन भी बचा और उन पर किसी भी प्रकार का आर्थिक प्रभाव भी नहीं हुआ. प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट डॉ. जैकब जॉन कहते भी हैं, ''जीवन दांव पर हो तब आप हर दूसरी चीज छोड़कर सबसे पहले जान बचाना चाहेंगे.''

बहुमत का न केवल यह मानना है कि लॉकडाउन ने लोगों की जान बचाई, बल्कि 77 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने भारत के स्वास्थ्य ढांचे में भरोसा जताया है. एक ऐसे देश के लिए जिसके सकल घरेलू उत्पाद का 1 प्रतिशत से भी कम स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होता हो, महामारी ने तंत्र में लोगों के विश्वास को मजबूत किया है. बेंगलूरू के मजूमदार शॉ मेडिकल सेंटर के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. आर. रंगनाथ कहते हैं, ''आज जब कोविड रोगियों को भर्ती किया जाता है, खून जमने से रोकने को हम तुरंत उन्हें थक्कारोधी दवाएं देना शुरू करते हैं और हर अंग की निगरानी करते हैं. हमारे पास मध्यम और गंभीर, दोनों चरणों वाले मरीजों को देने के लिए अधिक दवाएं मौजूद हैं. इस तरह की एक महामारी में और भारत जैसे बड़े देश में, कोविड के साथ मुकाबला करते हुए दूसरी परेशानियां होनी लाजमी थीं. पर हमने लोगों को जान बचाई और यह बात सबसे अहम है.''

सवाल: लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों के संकट के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं?

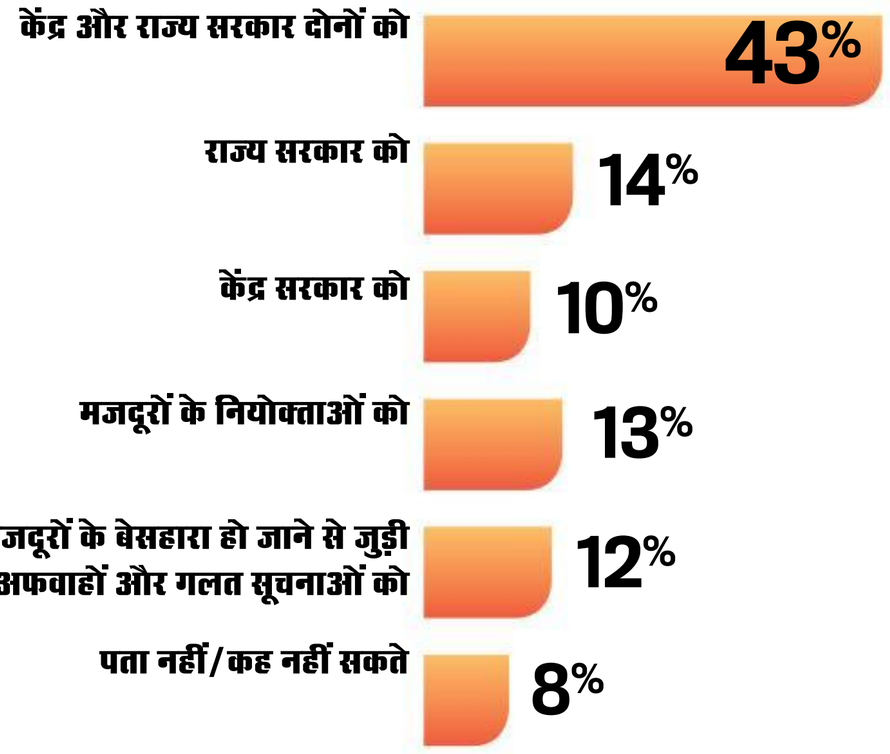

सवाल: क्या प्रवासियों को लॉकडाउन के दौरान उनके मूल राज्य लौट जाने की अनुमति दे दी जानी चाहिए थी?

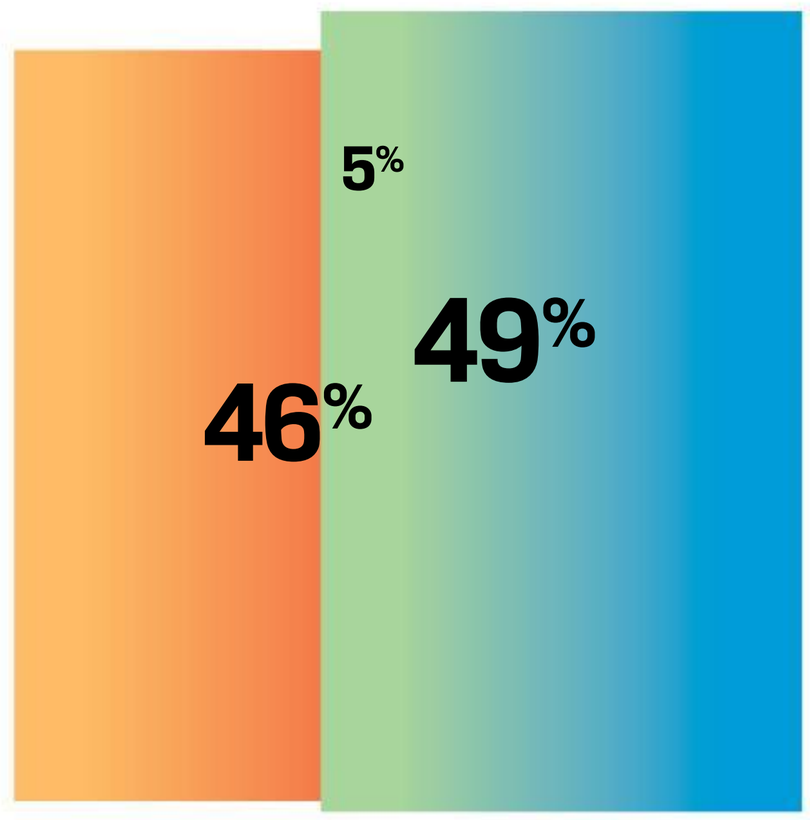

लॉकडाउन का सबसे ज्यादा और साफ-साफ दिखने वाला असर, जो सचमुच हिला देने वाला था, वह शहरों में काम करने वाले प्रवासी दिहाड़ी मजदूरों पर हुआ. अधिकांश फर्मों के बंद होने के कारण प्रवासी श्रमिकों के लिए जीवन चलाना दुश्वार हो गया और वे अपने घरों को लौटने लगे. जून में भारत के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि लगभग 97 लाख प्रवासियों को उनके गृहनगर भेज दिया गया था. यह संख्या यूपी से 21 लाख, बिहार से 10 लाख, महाराष्ट्र से 11 लाख और गुजरात से 20 लाख बताई गई.

प्रवासियों के घर लौटने की छटपटाहट के कारण पैदा हुए इस अपूर्व प्रवासी संकट और उसको लेकर अव्यवस्था की न केवल गंभीर आलोचना हुई बल्कि इससे कोविड के शहरों से ग्रामीण भारत में पहुंच जाने का जोखिम पैदा हुआ. अधिकांश प्रवासी खचाखच भरी बसों और ट्रेनों में घर लौटे जिससे कोविड के प्रसार का खतरा काफी बढ़ गया. हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर ऐंड मॉलिक्युलर बायोलॉजी के निदेशक डॉ. राकेश मिश्र कहते हैं, ''हम शुरू से कोविड को लेकर एक चीज पक्के तौर पर जानते थे कि यह अत्यधिक संक्रामक है. वायरस खुद को ढालने में चतुर रहा है ताकि दो लोगों के बीच संक्रमण फटाफट और शर्तिया हो. एक संक्रमित व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति तक इस वायरस को पहुंच जाने के लिए संक्रमित व्यक्ति

www.readwhere.com

सवालः क्या आपको देश में अस्पतालों के बुनियादी ढांचे पर भरोसा है?

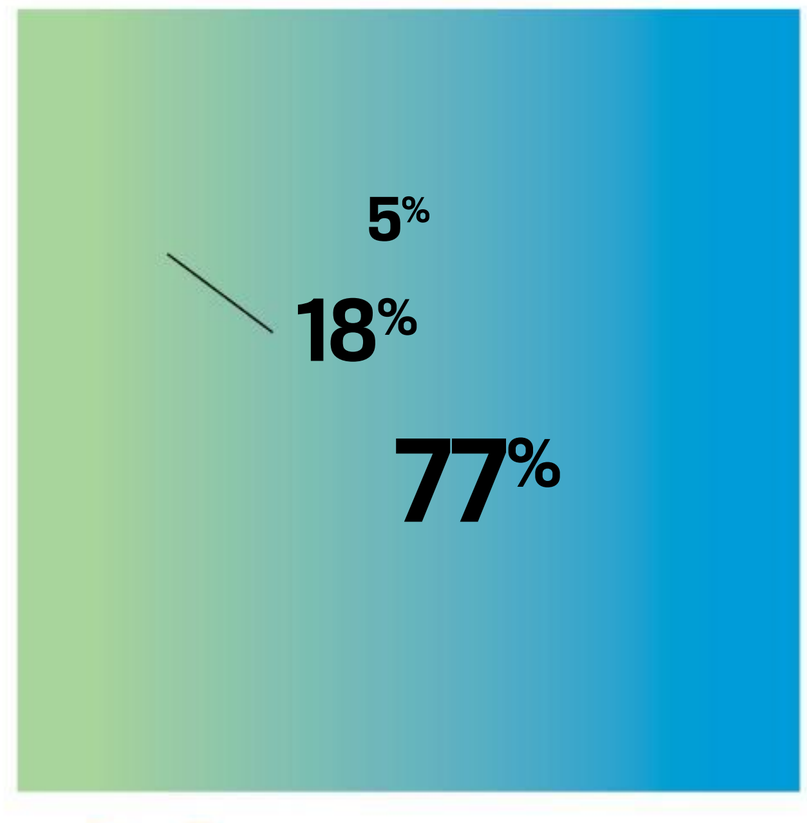

सवालः सरकार को किस पर ज्यादा खर्च करना चाहिए—स्वास्थ्य पर या सुरक्षा पर?

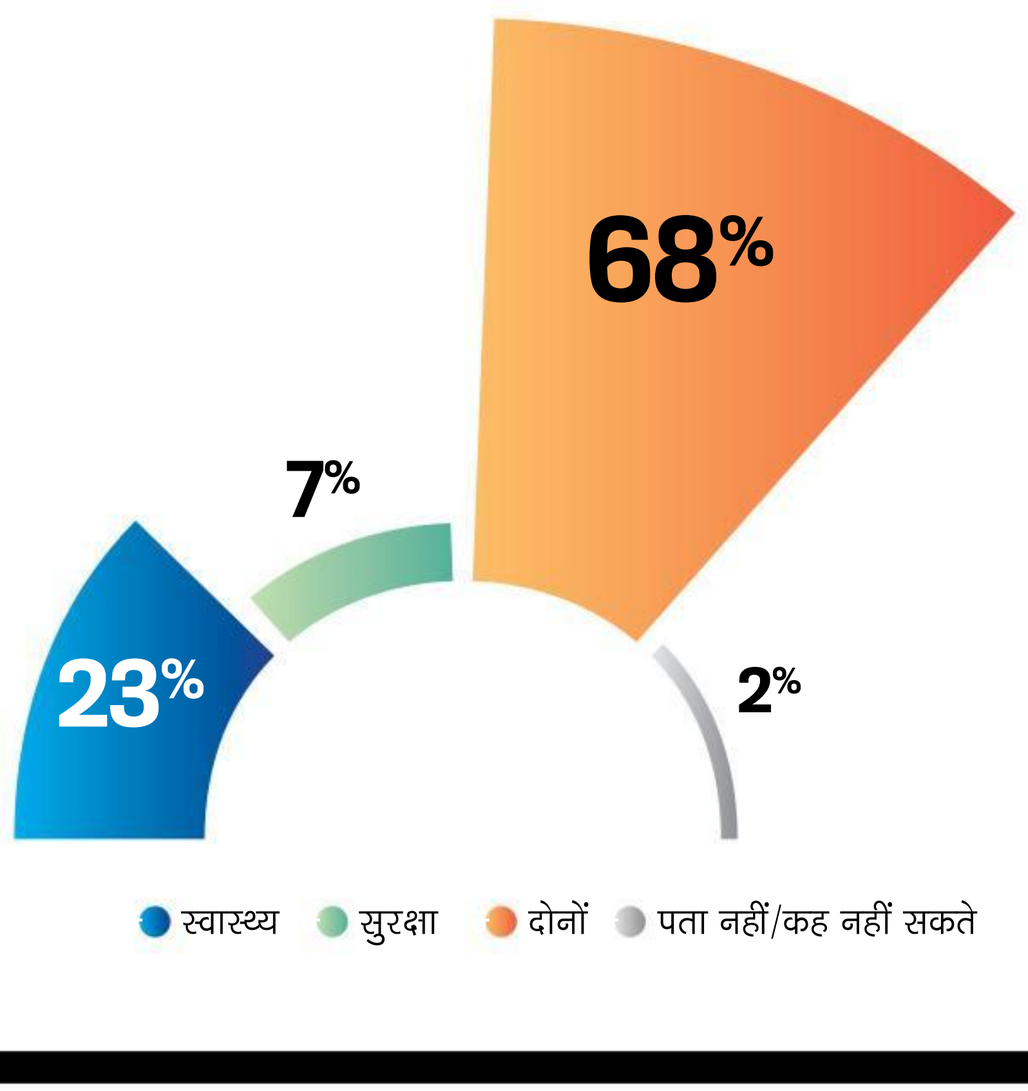

जो देश अपनी **जीडीपी का 1 फीसद से भी कम पैसा स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करता है, उसमें इस महामारी** ने व्यवस्था में लोगों का भरोसा मजबूत कर दिया लगता है

के हाथों या उसकी छुई किसी वस्तु पर वायरस का नाममात्र मौजूद होना ही काफी था. ऐसे लोग जो बहुत करीब रहते हैं या फिर यात्रा के दौरान बहुत नजदीक आते हैं, वहां एक कोविड संक्रमित व्यक्ति से संक्रमण फैल जाने का खतरा बहुत अधिक रहता है.''

प्रवासियों को घर वापस जाने की अनुमति देने के सरकार के फैसले का सर्वेक्षण में भाग लेने वाले ज्यादातर लोगों ने समर्थन किया (49 प्रतिशत), तो उत्तरदाताओं की एक बड़ी संख्या (46 प्रतिशत) का यह भी मानना है कि इस बीमारी की अत्यधिक संक्रामक प्रकृति को देखते हुए यह एक नासमझी भरा कदम रहा. पैंतीस प्रतिशत लोगों ने प्रवासी संकट के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों को जिम्मेदार ठहराया जबकि 14 प्रतिशत का मानना था कि सारा दोष राज्य सरकारों का था और केवल 10 प्रतिशत का कहना है कि इसके लिए पूरी तरह केंद्र जिम्मेदार है.

बात जब लॉकडाउन की आर्थिक कठिनाइयां कम करने को लेकर आई तो 71 प्रतिशत ने कहा कि केंद्र सरकार को प्रवासी श्रमिकों की मदद की मद का पैसा सीधे उनके खाते में ही डाल देना चाहिए था. अगर वित्तीय सुरक्षा मिली होती तो ज्यादातर लोगों ने लॉकडाउन के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा नहीं की होती. सर्वेक्षण में यह समझने की कोशिश भी की गई कि कामकाजी वर्ग की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ा है. 63 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा है कि उनकी आय घटी है—देश के पूर्व और पश्चिम में ऐसा मानने वालों की संख्या अधिक थी—और 22 प्रतिशत ने अपने कामकाज या नौकरी के नुक्सान की बात कही. हालांकि, केंद्र के घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज पर लोगों की राय बंटी हुई थी. 55 प्रतिशत का मानना था कि पैकेज के कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, वहीं 44 प्रतिशत लोग इससे असहमत थे या पक्के तौर पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं पाते थे.

72%

उत्तरदाताओं को लगता है कि देशभर में लॉकडाउन लगाने के सरकार के फैसले से लोगों की जान बचाने में मदद मिली

कोविड ने हमारी स्वास्थ्य प्रणाली की खामियों को गंभीर रूप से उजागर किया और केंद्र और राज्य सरकारों को युद्धस्तर पर इसमें सुधार के लिए मजबूर किया. मृत्यु और रोगियों के ठीक होने के मामले में दूसरे देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेशक बेहतर रही है, फिर भी संक्रमण के प्रसार को रोकने, कोविड से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता था. लगभग 68 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि देश को स्वास्थ्य सेवा और रक्षा, दोनों पर खर्च बढ़ाना चाहिए. लेकिन दोनों के बीच, एक बड़ी संख्या (23 प्रतिशत) का मानना है कि सरकार को रक्षा (7 प्रतिशत) की तुलना में स्वास्थ्य सेवा पर ज्यादा रकम खर्च करने की जरूरत है. यानी सिस्टम में भरोसा और गतिशीलता दोनों है, दरकार अब निवेश की है. ■

www.readwhere.com

दुश्मन नंबर एक

चीन-विरोधी भावनाएं इतने चरम पर पहले कभी न थीं, देश का मिजाज सर्वे में लोगों ने चीन के दुस्साहस का तीखा जवाब देने की वकालत की

संदीप उन्नीथन

इस साल 1 अप्रैल को नई दिल्ली और बीजिंग के बीच कूटनीतिक संपर्क लाइनें शांति और दोस्ती के संदेशों से इस कदर पटी पड़ी थीं कि जाम हो गईं. ठीक 70 साल पहले भारत ने वह काम किया था जो उस वक्त एक गैर-समाजवादी खेमे के देश के लिए नामुमकिन माना जाता था. उसने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को मान्यता दी थी, जिसने महज पिछले ही साल चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी का तख्ता पलटा था. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अप्रैल में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने पत्र में लिखा कि किस तरह दोनों पक्षों ने ''खासकर बीते कुछ वर्षों में राजनैतिक, आर्थिक और लोगों से लोगों के बीच संबंधों सहित अनेक क्षेत्र में दोतरफा मेलजोल बढ़ाया है.'' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग को भेजे अपने संदेश में दोनों देशों का जिक्र दो प्राचीन सभ्यताओं के रूप में किया, जिनके बीच सदियों से आपसी लाभप्रद आदान-प्रदान का लंबा इतिहास रहा है. उन्होंने विकास भागीदारी को नई

केंजाबरो फुकोहारा/गेट्टी इमेजेज

अब दुश्मन
चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान

www.readwhere.com

ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद भी जाहिर की.

अगर वुहान से रिसकर बाहर आई और दुनिया भर में फैली कोरोना वायरस की महामारी नहीं होती, जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रीय लॉकडाउन करना पड़ा, तो चीन के साथ कूटनीतिक रिश्तों की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सिलसिलेवार कई सारे आयोजन किए जाते.

भारतीय सैन्य जनरल चुपचाप खुश थे कि 'वुहान की भावना' ने उन्हें पाकिस्तान और आतंकवाद के मूल ढांचे पर ध्यान देने की मोहलत दे दी है. यह भावना राष्ट्रपति शी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच 2018 में वुहान में हुए पहले अनौपचारिक शिखर सम्मेलन से उपजी थी. बिल्कुल हो सकता है कि इसी प्रचंड भावना की आड़ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की वाहनों से लैस दो डिविजनों के अप्रैल में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की तरफ बढ़ने के इरादे और उससे उठे धूल के गुबार को छिपा लिया गया हो.

मई की शुरुआत में पूरी 3,448 किमी लंबी एलएसी और मुख्यत: पूर्वी लद्दाख की 840 किमी पट्टी पर अचानक कई टकराव हुए. पीएलए और भारतीय सेना अब इस तरह आमने-सामने हैं कि 1967 में सरहदी झड़पों के बाद पहले कभी नहीं रहीं. इस साल रिश्तों की सालगिरह मनाने की संभावनाएं चूर-चूर हो चुकी हैं और इसी साल चीन में होने वाले मोदी-शी के तीसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन की संभावनाएं छूमंतर हो गई हैं. दोनों सेनाओं के बीच पिछले दो महीने से चल रही बातचीत का कम ही कोई नतीजा निकला और पीएलए विवादित सीमा पर अपने नियंत्रण वाले इलाकों का विस्तार करने पर आमादा दिखाई देता है. नतीजा: भारत के लोग चीन के साथ हमारे रिश्तों को लेकर पहले जितने अनुकूल विचार रखते थे, उसमें भारी गिरावट आई है.

नई दिल्ली के नजरिए से देखें तो लगातार ज्यादा से ज्यादा आक्रामक होते चीन की तरफ से यह रणनीतिक खतरा इससे ज्यादा बेवक्त नहीं आ सकता था. आजाद भारत की कोई भी सरकार शायद ही कभी ऐसे तिहरे संकट से दोचार हुई होगी जिससे आज की सरकार घिरी हुई है—गंभीर जन स्वास्थ्य संकट, दुनिया के सबसे कठोर लॉकडाउनों में से एक से पैदा आर्थिक बदहाली और सीमाओं पर सैन्य खतरा. इन संकटों ने अपने विशालकाय उत्तरी पड़ोसी और सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार पर अपनी निर्भरता धीरे-धीरे कम करने के भारत के विकल्पों को सीमित कर दिया है.

पिछले देश का मिजाज (एमओटीएन) सर्वेक्षण के बाद के वक्त में हमने वुहान की भावना से लेकर लद्दाख की नफरत तक पूरा सफर तय कर लिया है. जनवरी 2020 के एमओटीएन सर्वेक्षण में 38 फीसद उत्तरदाता सोचते थे कि भारत और चीन के बीच रिश्ते बीते पांच साल में सुधरे थे. लेकिन, इस महीने एमओटीएन सर्वेक्षण में शामिल 84 फीसद जितनी भारी तादाद में लोगों ने माना कि शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी के साथ विश्वासघात किया है. वहीं, 91 फीसद उत्तरदाता मानते हैं कि बहुत-से चीनी ऐप पर पाबंदी लगाना और चीन कंपनियों को ठेके देने से इनकार करना चीन का मुकाबला करने के सही तरीके हैं.

इतना ही नहीं, 67 फीसद उत्तरदाताओं का कहना है कि चीन से बाहर निर्मित वस्तुओं के लिए वे ज्यादा कीमत अदा करने को भी तैयार हैं. चीन के प्रति अविश्वास इतना ज्यादा शायद पहले कभी नहीं था. यहां तक कि भारत और चीन के बीच 2017 में डोकलाम में 72 दिनों के गतिरोध के बाद हुए पहले एमओटीएन सर्वेक्षण में जनवरी 2020 में भी 42 फीसद लोगों ने माना था कि चीन के साथ भारत के रिश्ते सुधरे थे.

अब 47 फीसद लोग लद्दाख में भारत-चीन सीमा विवाद के लिए चीन की विदेशी आक्रामकता को जिम्मेदार ठहराते हैं. दिलचस्प बात यह है कि 41 फीसद लोग इसमें सरकार की गलती मानते हैं. इनमें से 30 फीसद ने भारत की गलत विदेश नीति को विवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया, जबकि 11 फीसद ने खुफिया नाकामी को इसकी वजह माना.

सवाल: चीन के साथ हालिया झड़प से निपटने में मोदी सरकार की कार्रवाई को आप कैसा आंकते हैं?

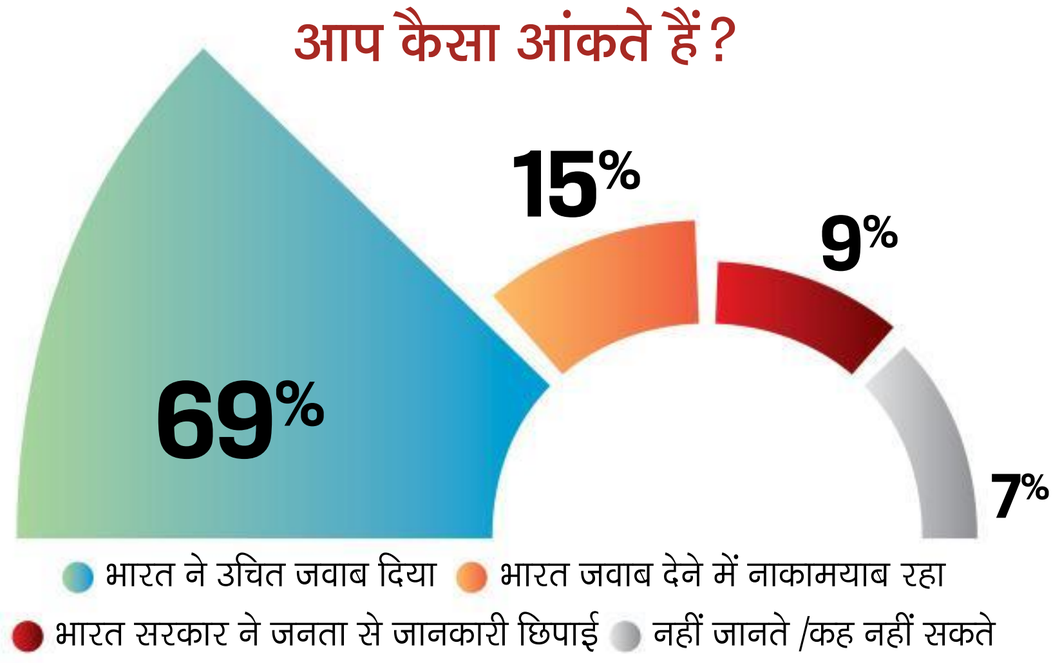

सवाल: सीमा के विवाद को लेकर क्या भारत को चीन से जंग लड़ना चाहिए?

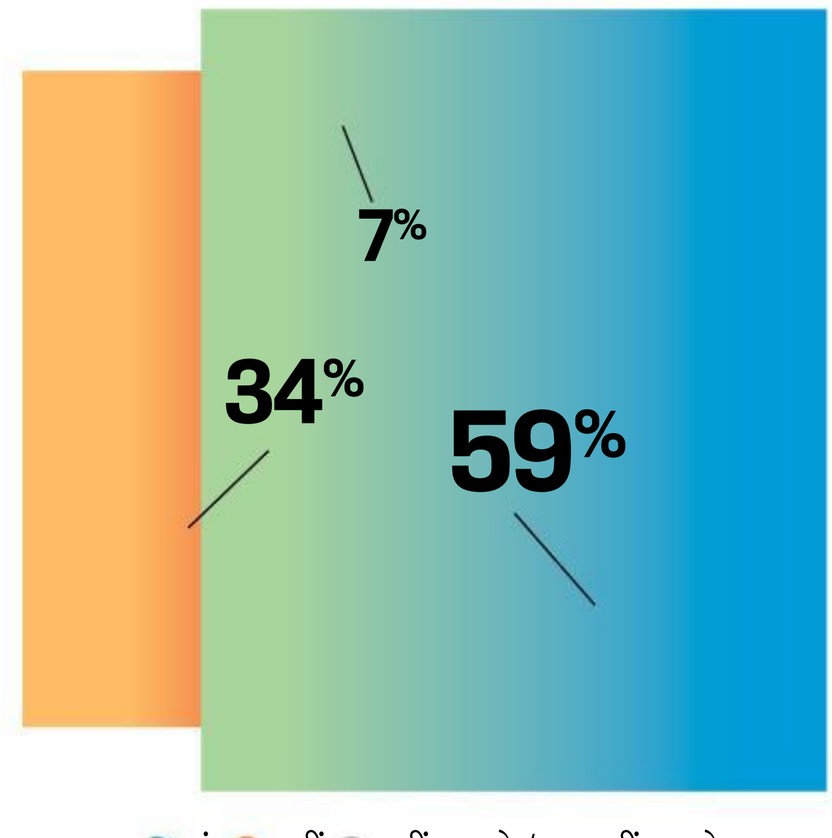

बहुसंख्यक—59 फीसद—लोग मानते हैं कि हमें चीन के साथ जंग छेड़ देनी चाहिए, वहीं 34 फीसद का कहना है कि नहीं, जंग नहीं छेड़नी चाहिए. वहीं, 72 फीसद मानते हैं कि चीन से लड़ाई में भारत वाकई जीत सकता है, जबकि केवल 19 फीसद ने माना कि हम जंग नहीं जीत सकते और 'यह गतिरोध में खत्म होगी'. हालांकि जंग, जिसकी संभावना और पैमाना सीमित है, साफ तौर पर किसी के हित में नहीं है. लेकिन लोग विकल्प के तौर पर इस पर भी विचार कर रहे हैं, यह बताता है कि भारतीयों के मन में चीन के खिलाफ गुस्सा किस हद तक उबल रहा है और बीजिंग ने कितनी बड़ी रणनीतिक गलती कर दी है.

भारत सरकार फिलहाल अपनी चीन नीति को नए सिरे से तौलने की प्रक्रिया में है. यह बदलाव दशकों में सबसे बड़ा बदलाव होगा. इसके लिए कई सारी बातों पर विचार किए जाने की संभावना है. इनमें यह भी है कि राष्ट्रपति शी लंबे समय तक रहेंगे या यह भी कि भारत के पास पहले के मुकाबले अब कहीं ज्यादा विकल्प हैं, मसलन वह चीन की ऐसी ही आक्रामकता से परेशान समान विचारों वाले एशियाई लोकतांत्रिक देशों से मेलजोल बढ़ा सकता है. भारत को दर्शकों की तालियां बटोरने का प्रलोभन छोड़ना होगा और आगे के लंबे रास्ते पर नजरें गड़ानी होंगी. ■

www.readwhere.com

इंडिया टुडे ग्रुप-कार्वी इनसाइट्स

देश का मिजाज जनमत सर्वेक्षण

कांग्रेस विपक्ष

असली संकट शीर्ष पर

कांग्रेस नेतृत्व के संकट और दिग्गज बनाम युवा की लड़ाई से हलकान, लेकिन देश का मिजाज सर्वे बताता है कि कहीं एक कोने में उम्मीद अब भी जिंदा है. गैर भाजपा और गैर कांग्रेस पार्टियां अगर एक साथ आ जाएं तो उनके लिए एक मौका है

कौशिक डेका

मनीष अग्निहोत्री

म

ई 2019 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद से ही कांग्रेस के लिए पिछला एक साथ रगों को बुरी तरह दुखाने वाला साबित हुआ है. देश की मुख्य विपक्षी पार्टी को भाजपा कर्नाटक और मध्य प्रदेश के रूप में उन दो राज्यों में पटखनी दे चुकी है, जहां उसने चुनाव जीते थे और तीसरे राज्य राजस्थान में भी सरकार बचाने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा है. इसने अपने सबसे होनहार नेताओं में से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में जाते देखा, एक अन्य युवा नेता सचिन पायलट पार्टी छोड़ने की कगार पर हैं. आशावादी कहेंगे कि पार्टी इस बीच दो राज्यों, महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार का हिस्सा भी तो बनी है. हालांकि यहां भी उसके लिए बहुत खुशफहमी पालने जैसी बात नहीं है क्योंकि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस मामूली-सी सहयोगी भर है. सात महीने सत्ता में रहने के बाद पार्टी की झारखंड इकाई में खदबदाहट शुरू भी हो गई है.

रही सही कसर इस बात को लेकर पार्टी के सहयोगियों के बीच सार्वजनिक मंचों पर हो रही जूतमपैजार ने पूरी कर दी कि क्या कांग्रेस को यूपीए-2 सरकार की विरासत का बहुप्रतीक्षित आत्मनिरीक्षण शुरू करना चाहिए या नहीं. जैसा अपेक्षित था, जनता के बीच पार्टी की पकड़ कमजोर होती जा रही है. 19 राज्यों के 97 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और 194 विधानसभा क्षेत्रों के 12,021 लोगों का साक्षात्कार लेकर किए गए इंडिया टुडे देश का मिजाज सर्वेक्षण में 47 फीसद लोगों ने कहा कि कांग्रेस मृत्यु शैय्या पर पहुंच गई है. हालांकि नुक्सान दिखाने वाले ऐसे हौलनाक आंकड़े भी कांग्रेस के कई नेताओं का विश्वास डिगाने में विफल हैं. 30 जुलाई को

www.readwhere.com

आला कमान
पिछले साल रायबरेली लोकसभा सीट के लिए सोनिया गांधी के पर्चा दाखिल करने से पहले पूजा के मौके की तस्वीर

सवालः पार्टी नेता बगावत कर रहे या पार्टी छोड़ रहे तो क्या कांग्रेस का अंत निकट आ गया है?

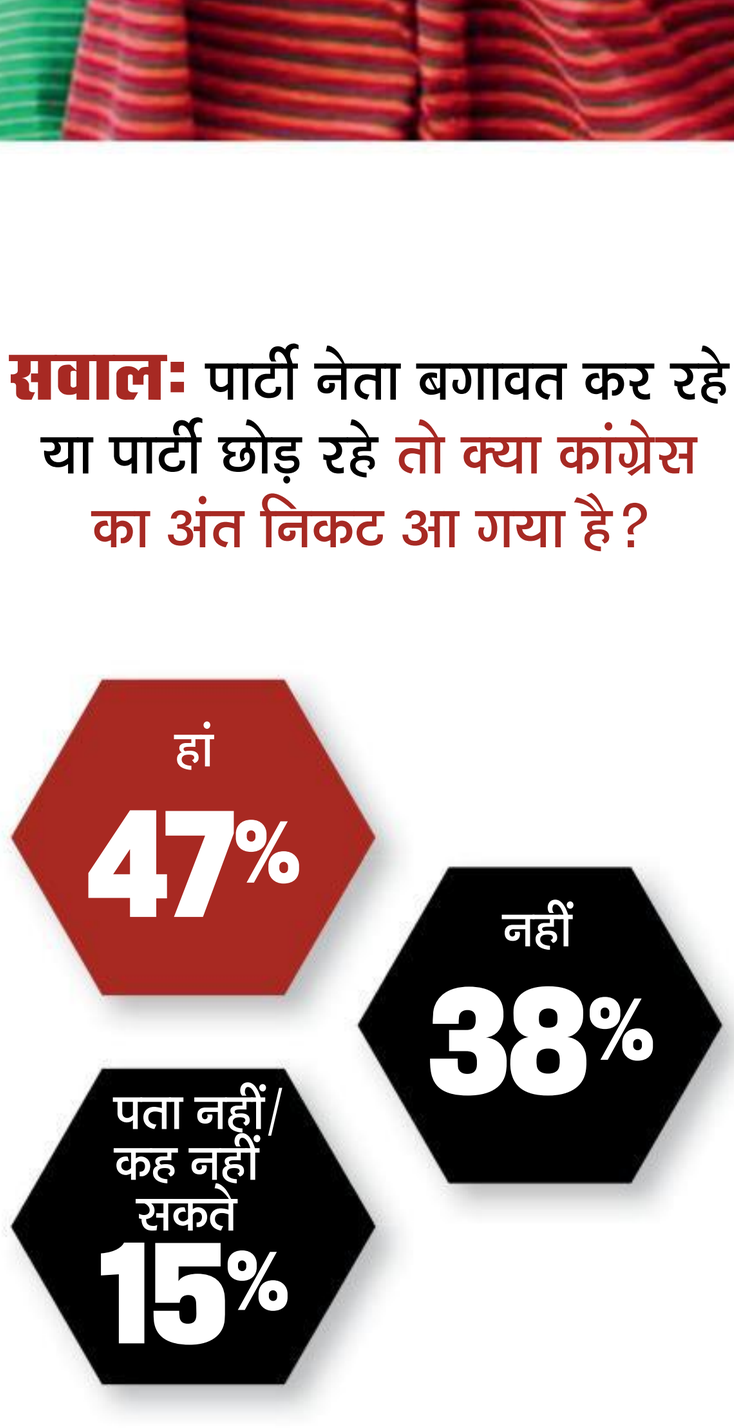

पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों की बुलाई गई बैठक में कथित रूप से यूपीए-2 की अवधि से आत्ममंथन शुरू करने का सुझाव देने वाले राजीव सातव कहते हैं, ''2024 तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मजबूत नेतृत्व में कांग्रेस नए जोश के साथ मजबूती से खड़ी होगी. जनता के समर्थन से हम भाजपा को हराएंगे क्योंकि यह गलतबयानी और लोगों को बांटने के अलावा हर मोर्चे पर विफल रही है.'' राहुल के साथ निकटता के लिए जाने जाते रहे सातव, सिंधिया के पार्टी छोड़ने या पायलट की बगावत को पार्टी के अस्तित्व पर खतरे के रूप में नहीं देखते. उनकी राय में ''कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं है.'' इसकी बजाए वे राहुल में भरोसा दोहराते हुए कहते हैं कि राहुल ने पार्टी में ''एक बेहतर प्रणाली तैयार की है जो युवाओं और प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की पार्टी में तरक्की के साथ-साथ उन्हें संसद तक पहुंचने का मार्ग खोलती है.''

फिर भी एक-चौथाई से कम उत्तरदाता (23 प्रतिशत) ही राहुल को लेकर सातव के इस उत्साह का समर्थन करते हैं. राहुल ने आम चुनाव में पार्टी के निकृष्ट प्रदर्शन के कारण पिछले साल जुलाई में कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया था. जहां तक पार्टी के भाग्य को फिर से संवारने की बात है तो गांधी परिवार के युवराज अब भी सबसे पसंदीदा विकल्प तो बने हुए हैं. हालांकि अगस्त 2018 यानी राहुल के अध्यक्ष का पदभार संभालने के आठ महीने बाद हुए सर्वे में जहां 47 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उन्हें पार्टी का संभावित उद्धारक माना था, उसके मुकाबले यह संख्या कम है. इस

www.readwhere.com

बार के सर्वे में तो जनवरी 2020 के 'देश का मिजाज' सर्वे के मुकाबले भी एक प्रतिशत कम लोग उनके साथ आए हैं.

राहुल की घटती हुई सार्वजनिक स्वीकार्यता के विपरीत, जिस नेता पर लोगों का विश्वास बढ़ता दिखता है वे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं. पिछले सर्वे में 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना था कि जीवन के अस्सी बसंत देख चुके मनमोहन सिंह कांग्रेस को पुनर्जीवित कर सकते हैं, वहीं ताजा सर्वेक्षण में ऐसा मानने वालों की संख्या 18 प्रतिशत हो गई है. यह बात ऐसे समय में सामने आई है जब पार्टी में वरिष्ठ नेताओं ने यूपीए की विरासत और परोक्ष रूप से मनमोहन सिंह पर सवाल उठाने के लिए सातव को आड़े हाथों लिया है. यह एक तरह से अपने पद के दूसरे और अंतिम कार्यकाल के आखिरी दिनों में मनमोहन सिंह की उस भविष्यवाणी पर भी आंशिक रूप से मुहर है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था, ''मीडिया की तुलना में इतिहास मेरे प्रति ज्यादा दयालु होगा.'' सातव ने बाद में सफाई दी कि उनका इशारा मनमोहन की सिंह ओर नहीं था क्योंकि वे 'दोषारोपण से परे हैं.'

मनमोहन सिंह का यह अचानक पुनरुद्धार ही है जो उनके रूप में पहली बार किसी गैर-गांधी व्यक्ति ने 'कांग्रेस को पुनर्जीवित करने वाले नेता' के रूप में शीर्ष तीन पदों में से एक पर कब्जा किया है. यह पार्टी में नेतृत्व के संकट का एक संकेत भी है जिससे पार्टी पिछले साल राहुल के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद से जूझ रही है. राहुल का योग्य विकल्प खोजने में पार्टी के नाकाम रहने के कारण 73 वर्षीया और बीमार सोनिया गांधी को पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बनाना पड़ा था. हालांकि यह निर्णय कांग्रेस की गांधी परिवार से परे देखने की अनिच्छा को दर्शाता है. इसे लोगों का समर्थन भी मिला है. सर्वे के उत्तरदाताओं में से 41 प्रतिशत ने सोनिया के प्रदर्शन को अच्छा माना, हालांकि यह छह महीने पहले मिले 49 प्रतिशत के समर्थन से कम है.

> राहुल ब्रिगेड ने **उनकी वापसी के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी है** पर वे खुद, लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 'अकेले ही लड़ने' पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं

सोनिया 10 अगस्त को पार्टी प्रमुख के रूप में नवीनतम कार्यकाल का साल भर पूरा करेंगी. वे कांग्रेस कार्य समिति की ओर से नियुक्त की गई थीं और पार्टी संविधान के अनुसार, ऐसी नियुक्तियों को एआइसीसी के सत्र में अनुमोदन की जरूरत होती है. पर ऐसा नहीं हुआ. और कोविड-19 के भारत भर में उग्र होने के साथ निकट भविष्य में ऐसे सत्र के आयोजन की संभावना भी नहीं है. अधिकांश कांग्रेसी दिग्गज उनके कार्यकाल को बढ़ाने के पक्ष में हैं लेकिन राहुल के वफादारों ने उनकी वापसी की मांग शुरू कर दी है. दूसरी ओर 50 वर्षीय राहुल ने अपने समर्थकों को निराश करते हुए पार्टी और अपने सहयोगियों के लिए एक पुनरुद्धार योजना को अपनाने की बजाए अपनी 'अकेले की लड़ाई' पर ध्यान केंद्रित करना चुना है.

पिछले छह महीनों में राहुल ने मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर एक गंभीर और संवेदनशील नेता के रूप में अपनी छवि बनाने के उद्देश्य के साथ एक 'वीडियो युद्ध' छेड़ रखा है, यह बताने को कि वे 'पप्पू' नहीं हैं, जैसा कि भाजपा के ट्रोल्स उन्हें प्रोजेक्ट करते रहे हैं. उन्हें कोविड के कारण लॉकडाउन के ऐलान के बाद पलायन करते प्रवासियों के साथ सड़कों पर बातचीत करते हुए, वैश्विक विशेषज्ञों के साथ कोविड-19 और अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हुए और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर जारी वीडियो में चीन के साथ भारत के सीमा संघर्ष का विश्लेषण करते हुए देखा गया था. इन वीडियो की सामग्री भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राहुल की लड़ाई के संकेत देती है, जो भाजपा के सबसे शक्तिशाली प्रतीक—प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास दिखती है. यह लड़ाई भी पार्टी के शीर्ष पर लौटने की उनकी अनिच्छा की वजह है. अपने इस्तीफे में उन्होंने उल्लेख किया था कि ''प्रधानमंत्री, आरएसएस और जिन संस्थानों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है'' उनसे संघर्ष में, अन्य कांग्रेस नेताओं के समर्थन के बिना उन्होंने खुद को एकदम अकेला पाया था और अकेले ही लड़ते रहे. उनके सहयोगी कहते हैं कि तब से परिदृश्य बहुत बदला तो है नहीं.

जून में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में, राहुल ब्रिगेड के सदस्य समझे जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.पी.एन. सिंह ने कथित तौर पर कहा कि कांग्रेस को मोदी की नीतियों और गलत फैसलों पर निशाना साधना चाहिए लेकिन यह हमला व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए. आर.पी.एन. सिंह की यह टिप्पणी शायद दो दिन पहले राहुल के एक ट्वीट के कारण थी, जिसमें कहा गया था कि ''नरेंद्र मोदी वास्तव में सरेंडर (आत्मसमर्पण) मोदी हैं.'' इस कटाक्ष के जरिए राहुल ने चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के दौरान 'आत्मसमर्पण' करने का आरोप लगाया था. पार्टी कोषाध्यक्ष और सोनिया गांधी के अनौपचारिक सलाहकार अहमद पटेल ने भी कथित तौर पर कहा कि पार्टी के नेताओं को मोदी के खिलाफ मुखर होना चाहिए, लेकिन 'असंयमित भाषा' के उपयोग से बचना चाहिए. आलोचना के ऐसे सुर पिछले साल भी सुने गए थे जब जयराम रमेश और शशि थरूर जैसे कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि पार्टी मोदी की व्यक्तिगत छवि पर जरूरत से ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है.

हालांकि, राहुल इस तरह की आलोचना को बहुत तवज्जो देने के मूड में नहीं हैं और उन्होंने लगभग रोज प्रधानमंत्री पर हमला करना जारी रखा है. उन्होंने कार्यसमिति की बैठक में कहा, ''मैं पीएम मोदी से नहीं डरता. मैं उनकी आलोचना करता रहूंगा. अगर यहां के लोगों को कोई समस्या है, तो कार्यसमिति मुझे चुप रहने को कह सकती है.'' अगले दिन (24 जुलाई), उन्होंने ट्वीट किया जिसमें परोक्ष रूप से उन्होंने खुद को सबसे पहले आगाह करने वाला होने का श्रेय लिया, ''मैं उन्हें कोविड-19 और अर्थव्यवस्था पर चेताता रहा. उन्होंने इसे अनसुना कर दिया. आखिर आपदा आ ही गई. मैं उन्हें चीन को लेकर आगाह करता

www.readwhere.com

सवालः गांधी परिवार में अव्वल पसंद बने रहे राहुल

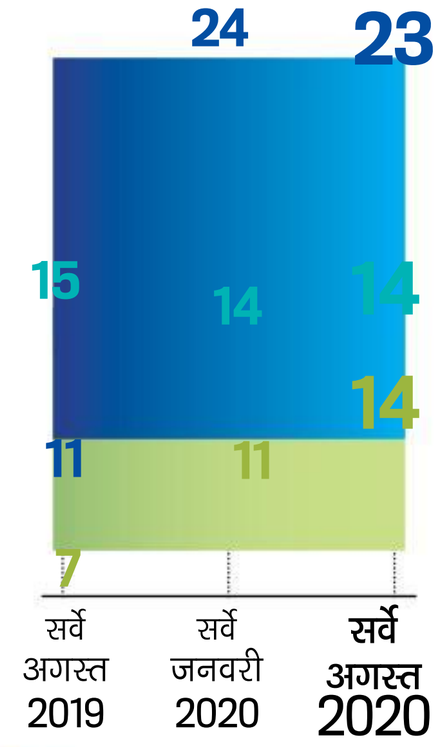

लगता है राहुल ने लोगों के दिमाग में पहली वरीयता के रूप में जगह बना ली है; आंकड़े % में

सवालः भारत-चीन सीमा संघर्ष को लेकर राहुल गांधी के मोदी सरकार की आलोचना से आप सहमत हैं?

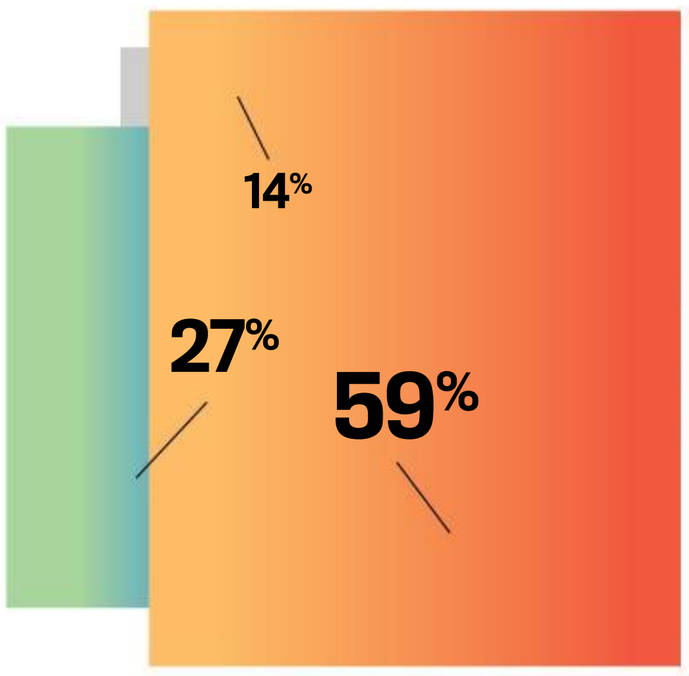

सवालः कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी के प्रदर्शन का आकलन आप किस तरह से करते हैं?

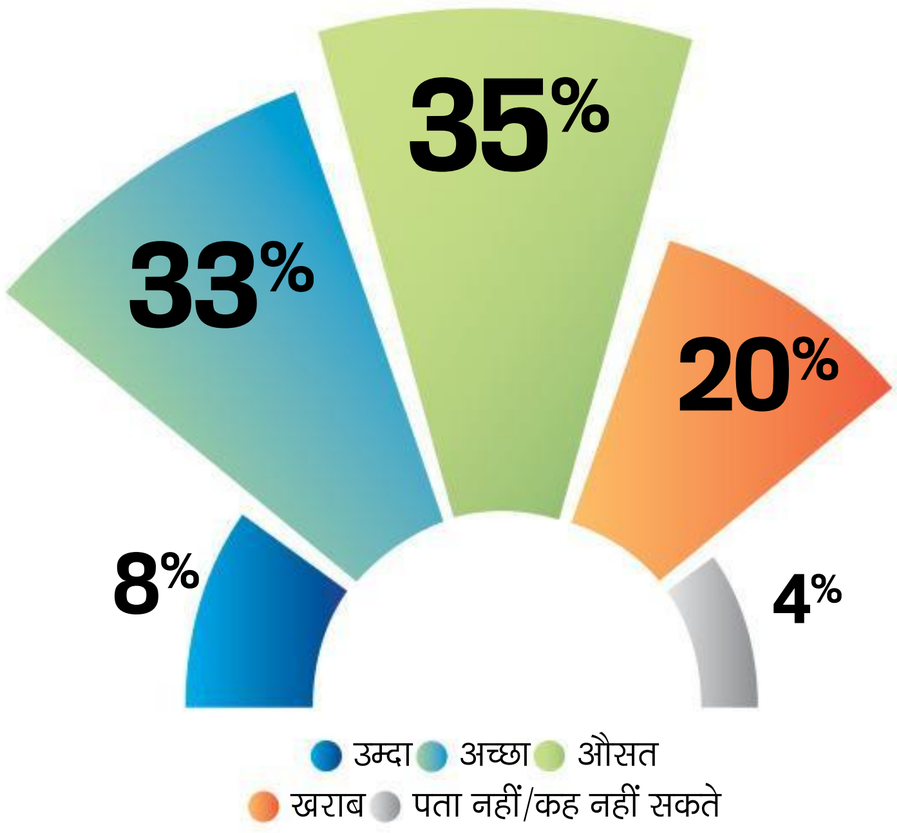

रहता हूं. वे इसे भी अनसुना कर रहे हैं.'' दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग उन्हें अभी तक उस भूमिका में देखने के लिए तैयार नहीं दिखते. उन्होंने कोविड-19 महामारी के खतरों को लेकर बहुत शुरुआत में 12 फरवरी को ही देश को आगाह करते हुए मोदी सरकार से निवारक उपाय करने का अनुरोध किया हो सकता है, लेकिन 61 प्रतिशत उत्तरदाताओं को राहुल की कोविड-19 को लेकर मोदी सरकार की आलोचनाओं में कोई दम नहीं दिखता. आर.पी.एन. सिंह और कांग्रेस के दिग्गजों की राजनैतिक व्यावहारिकता दिखाने की नसीहत को भी देश का मिजाज सर्वे में समर्थन मिला है क्योंकि ज्यादातर उत्तरदाता चीन के साथ भारत के सीमा संघर्ष को लेकर राहुल द्वारा मोदी सरकार की आलोचनाओं से सहमत नहीं थे. 59 फीसद लोगों का कहना है कि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे की हो तो राहुल को सरकार पर हमले नहीं करने चाहिए.

राहुल ब्रांड राजनीति के विरोधी कांग्रेस के नेताओं के लिए उत्साह की बात यह हो सकती है कि 44 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विपक्ष के रूप में पार्टी की भूमिका को पसंद किया. शायद यह इस बात का संकेत है कि राष्ट्र को अभी भी पार्टी पर भरोसा है, लेकिन लोग उसे एक मजबूत नेतृत्व और नई बातों के साथ उभरने की उम्मीद रखते हैं. कभी राहुल के राजनैतिक गुरु के रूप में जाने गए दिग्विजय सिंह कहते हैं, ''वे अलग हैं और अलग तरीके की राजनीति करना चाहते हैं. हमें उन्हें ऐसा करने की अनुमति देनी चाहिए, पर हम उनसे संसद में अधिक सक्रिय और लोगों के लिए अधिक सुलभ होने की उम्मीद भी करते हैं.'' शरद पवार ने उन्हें 'भारत यात्रा पर निकलने' की सलाह दी.

नेतृत्व संकट के बावजूद कांग्रेस को अभी भी लोगों का समर्थन मिल सकता है पर भारतीय लोकतंत्र का दुर्भाग्य देखिए कि दूसरे विपक्षी दल जनता की नब्ज टटोलने में नाकाम रहे हैं. कोविड-19 संकट के साथ एक विशेष बात रही है कि इसने भाजपा और उसके विरोधियों दोनों पर बिना मुरव्वत के समान रूप से आघात किया है. भाजपा केंद्र और कई राज्यों में महामारी से लड़ रही है, तो अन्य दल भी अपने-अपने राज्यों में वैसी ही लड़ाई में फंसे हैं—छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब में कांग्रेस; पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस; ओडिशा में बीजू जनता दल, महाराष्ट्र में शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-कांग्रेस; केरल में वामपंथी; तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति; आंध्र प्रदेश में वाइएसआर कांग्रेस पार्टी; झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा-कांग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल. इसलिए केंद्र की आलोचना करते हुए वे भी उसी खेल में उलझ जाते हैं और अपने राज्यों में उनके खिलाफ भी वैसे ही आरोप लगते हैं. जो लोग सत्ता में नहीं हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी—महामारी के कारण लॉकडाउन प्रतिबंधों के चलते उनकी सारी गतिविधियां केवल सोशल मीडिया पर हुई हैं. नतीजा: महामारी से निबटने में भाजपा शासित सरकार की नाकामियां गिनाते समय कोई ठोस तर्क देने में में वे सामूहिक रूप से विफल रहे हैं. 53 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि विपक्षी दलों ने रस्म अदायगी के लिए सरकार की आलोचना की है.

आंकड़ों के इस संदर्भ में देखें तो धारणाओं की लड़ाई में इस नुक्सान की कीमत बहुत अधिक लगती है. इस बार के देश का मिजाज सर्वे के अनुसार, गैर-एनडीए दलों का सामूहिक वोट शेयर 58 प्रतिशत है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें मिले शेयर से तीन प्रतिशत अंक ज्यादा है. लोकसभा सीटों के लिहाज से देखें तो यह 227 सीटों में बदल जाता है जो बहुमत से 50 सीटें ही कम है. ध्यान देने योग्य बड़ी बात यह है कि विपक्ष का यह लाभ मुख्य रूप से गैर-यूपीए दलों के कारण है. संदेश स्पष्ट और जोरदार है. जरूरत पड़ने पर राष्ट्र दो राष्ट्रीय दलों भाजपा और कांग्रेस से परे देखने के लिए तैयार है—लेकिन अन्य दलों को भी अपनी आवाज दुरुस्त रखनी होगी और प्रयास करने होंगे कि लोग उनकी बातों को गंभीरता से सुनें. ■

www.readwhere.com

परिवर्तनकारी मुख्यमंत्री

विकास के कामों में तकनीक का इस्तेमाल करने वाले नई पीढ़ी के मुख्यमंत्रियों ने जीता मतदाताओं का भरोसा

अमरनाथ के. मेनन

शीर्ष पर
21 अप्रैल को लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकाल के आखिरी दो साल में प्रवेश कर गए हैं और वे अपने अधूरे कामों के बारे में कहते हैं, ''अपराध और भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो भी जरूरी होगा, हम करेंगे.'' वे राज्य में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने इस कुर्सी पर तीन साल पूरे किए हैं और भगवा कपड़ों में रहने वाले 48 साल के नेता ने इसे राज्य के लिए परिवर्तनकारी यात्रा में बदलने की ठान रखी है.

अगस्त 2020 का देश का मिजाज सर्वेक्षण के मुताबिक, लोगों के मन में यह धारणा मजबूत होती जा रही है कि योगी एक कुशल प्रशासक हैं और वे सूबे को निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बना रहे हैं. वह भी तब, जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य के शुरू होने से उनकी पार्टी का हिंदुत्व अभियान और राम जन्मभूमि आंदोलन भी अंजाम तक आ गया है. भारत भर में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की रेटिंग जनवरी के 18 फीसद से बढ़कर अगस्त में 24 फीसद पर आ गई है.

आदित्यनाथ का ध्यान अब चालीस लाख प्रवासियों के लिए रोजगार पैदा करना है जो लॉकडाउन के दौरान वापस आ गए हैं. महामारी के आने से पहले, उन्होंने अर्थव्यवस्था को सुधारने की कुछ पहल की थी, और वे उद्योग लगाने के लिए निवेशकों का स्वागत कर रहे थे. धीरे-धीरे इसका नतीजा दिखने लगा है.

परियोजनाओं और निवेशकों पर नजर रखने वाली प्रोजेक्ट्स टुडे के मुताबिक, उत्तर प्रदेश का सकल निवेश मार्च, 2015 के 4.2 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले दोगुना बढ़कर मार्च, 2020 में 8.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है. यहां परियोजना लागू करने की दर 36.9 फीसद से बढ़कर 43.9 फीसद हो गई है जबकि निवेश में निजी क्षेत्र का हिस्सा भी मार्च, 2018 के 29.4 फीसद से बढ़कर मार्च, 2020 में 42.2 फीसद हो गया है. एकल खिड़की व्यवस्था निवेश मित्र के साथ मुख्यमंत्री ने निवेश के लिए आवेदन से स्वीकृति तक के चक्र को आसान बना दिया है. लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 70,419 रु. ही है जो देश में दूसरा सबसे कम और राष्ट्रीय औसत 1.34 लाख रु. का लगभग आधा ही है. इस तरह, सूबे को अभी लंबा रास्ता तय करना है. मुख्यमंत्री कहते हैं, ''हम राज्य के प्रति नजरिया बदलने में सफल रहे हैं. अब उत्तर प्रदेश विकास और

www.readwhere.com

सवाल: भारत में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री कौन?

(देशभर के लोगों की प्रतिक्रिया पर आधारित)

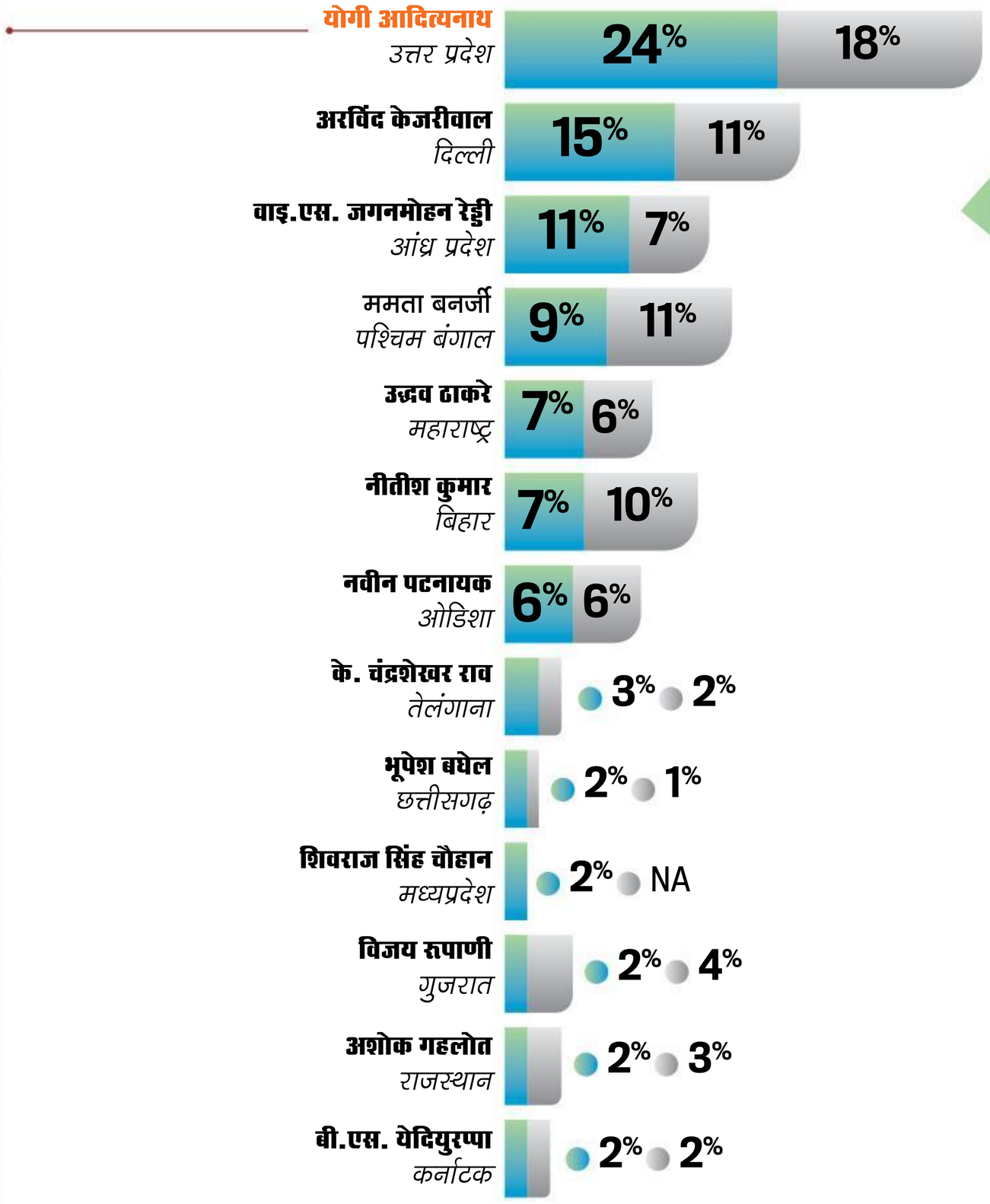

सवाल: कौन है सबसे बेहतर काम करने वाला मुख्यमंत्री (गृह राज्य)?

(राज्य के लोगों के जवाब पर आधारित)

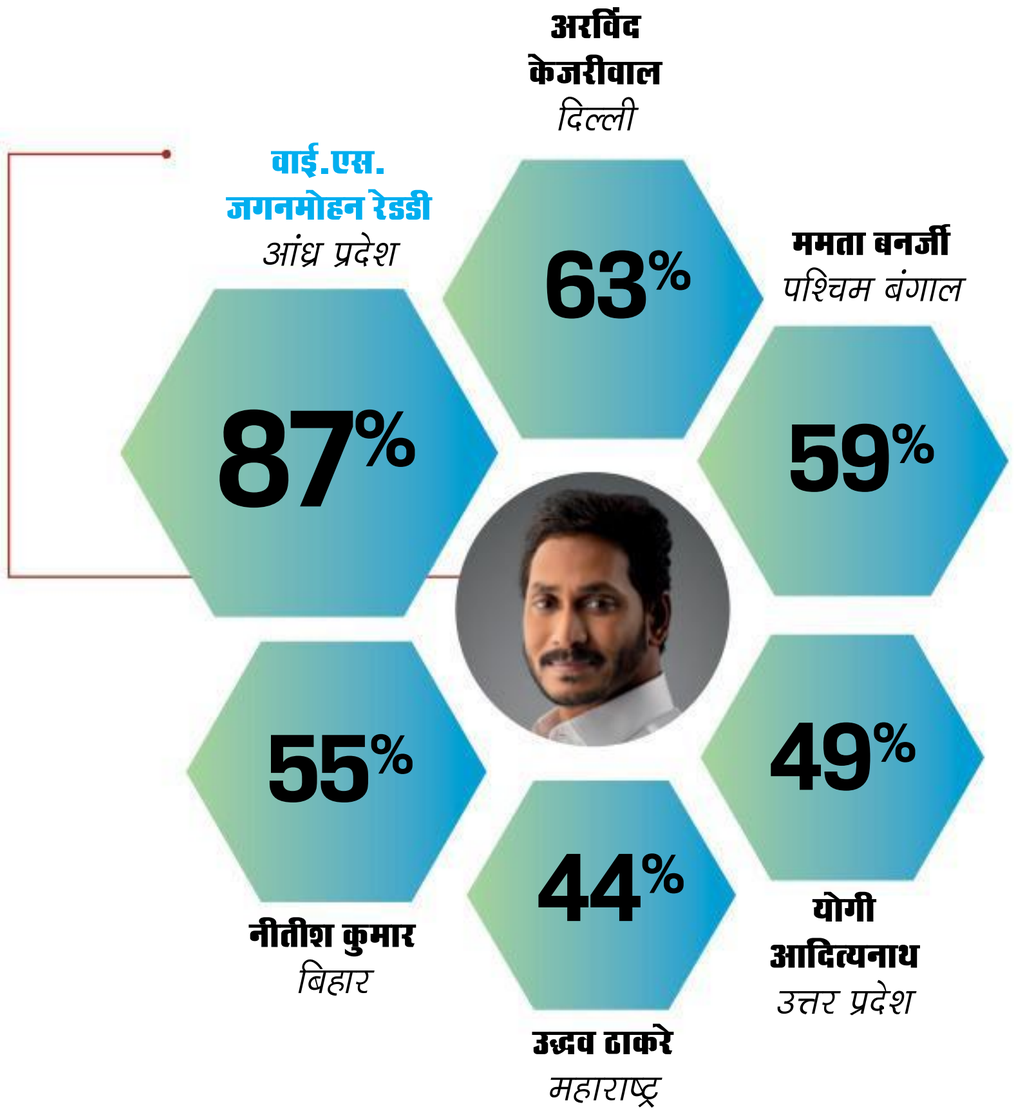

सवाल: आप कोविड-19 से निपटने में राज्य सरकार का आकलन कैसे करेंगे?

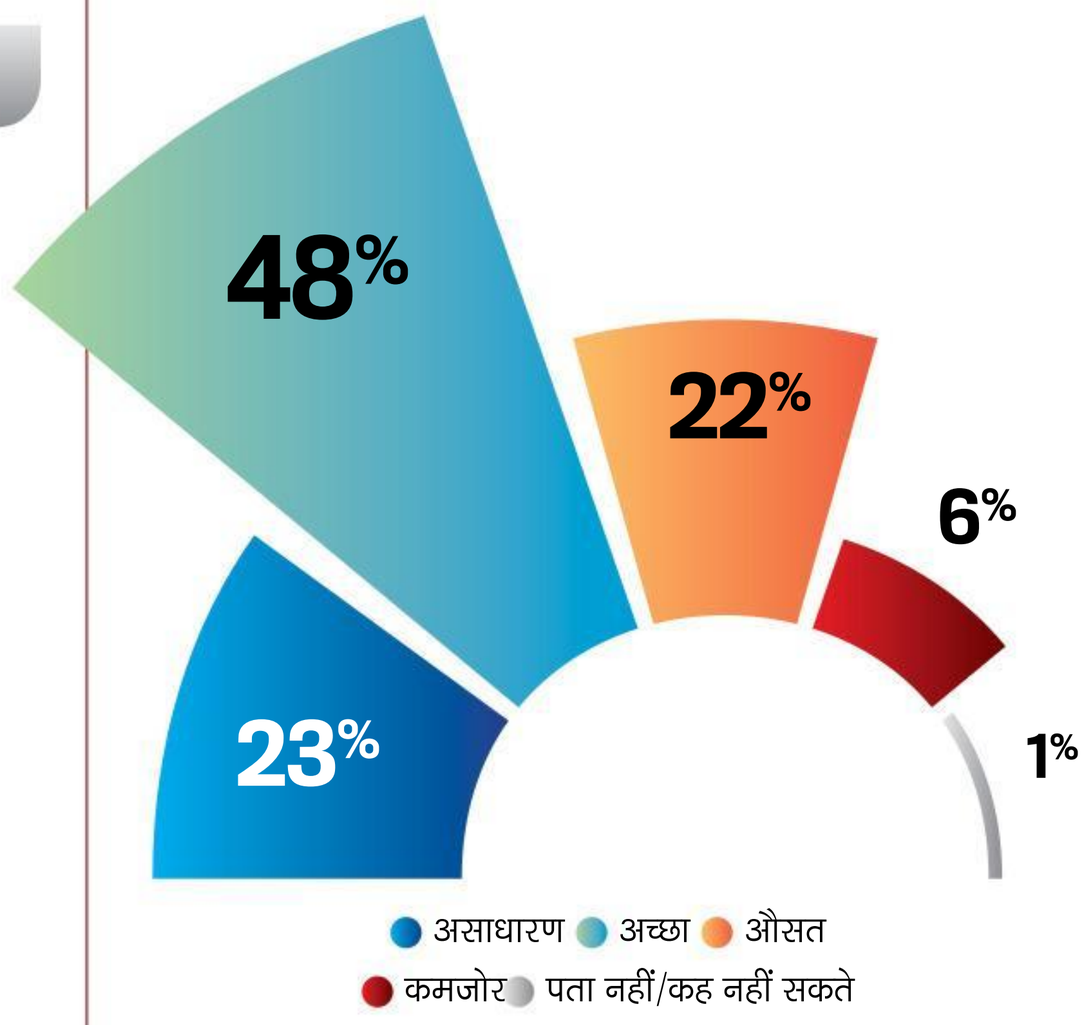

सुशासन के रास्ते पर है.'' योगी आदित्यनाथ से उम्र में छह महीने छोटे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाइ.एस. जगनमोहन रेड्डी, जिन्होंने पिछले साल 30 मई को ही कुर्सी संभाली है, का आकर्षण और अधिक है. देश का मिजाज सर्वे के मुताबिक, उनके गृह राज्य के 87 फीसद लोग उनके पक्ष में हैं और यह किसी भी मुख्यमंत्री को मिली सर्वाधिक रैंकिंग है. आदित्यनाथ को अपने राज्य में मिला समर्थन महज 49 फीसद है जबकि तीन अन्य—अरविंद केजरीवाल (दिल्ली), ममता बनर्जी (पश्चिम बंगाल) और नीतीश कुमार (बिहार) 55 फीसद या अधिक अंकों के साथ ऊपर हैं.

रेड्डी की बढ़त की वजह है कि उन्होंने 2019 में गरीबों से किए चुनाव-पूर्व वादों को पूरा करने की कोशिश की है. गरीबी उन्मूलन योजनाओं की जद में लगभग पूरी आबादी आ चुकी है और इन सब पर ग्राम सचिवालय व्यवस्था के जरिए नजर रखी जाती है. पिछले साल 2 अक्तूबर को शुरू और रेड्डी के दिमाग की उपज यह योजना राज्य में भविष्य के प्रशासन के संकेत के रूप में उभर रही है.

इसके लिए उन्होंने जमीनी स्तर पर विशाल प्रशासनिक तंत्र तैयार किया है. हर 2,000 की आबादी पर एक ग्राम या वार्ड सचिवालय और हर 100 घरों के लिए एक स्वयंसेवक तैयार किया है. इस तरह उन्होंने 3,89,000 नौकरियां भी सृजित की हैं. ये स्वयंसेवक नागरिकों को घर पर सेवाएं उपलब्ध कराते हैं. यह उनका काम है कि हर घर में जाकर लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित की जा सके और समय-बद्ध और पारदर्शी तरीके से सभी उचित सेवाएं समुचित रूप से पहुंचाई जाएं. इसके साथ ही, इसी काम के लिए 200 कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव की एक टीम है जो सेवा को लेकर की गई मांगों पर कामकाज की प्रगति पर निगाह रखती है.

असल में, तकनीक की मदद से, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने एक ऐसी व्यवस्था तैयार की है जिससे विभिन्न सरकारी सेवाओं का फायदा लगातार अबाधित रूप से लोगों तक पहुंच रही है. ■

www.readwhere.com

इंडिया टुडे ग्रुप-कार्वी इनसाइट्स

देश का मिजाज जनमत सर्वेक्षण

मनोरंजन

भारत कुमार सब पर भारी

हिंदी सिनेमा में खान तिकड़ी की फीकी पड़ती चमक के साथ अक्षय कुमार ने शीर्ष पर कब्जा जमाया; अभिनेत्रियों में फिल्मी खानदानों से बाहर की लड़कियों का बोलबाला

सुहानी सिंह

सवाल: कौन है हीरो नंबर 1?

अमिताभ बच्चन
23%

शाहरुख खान
11%

सलमान खान
10%

आमिर खान
6%

अजय देवगन
4%

रणबीर सिंह
4%

हृतिक रोशन
4%

रणवीर कपूर
2%

शाहिद कपूर
2%

अक्षय कुमार
24%

यासिर इकबाल

विड-19 की वजह से सिनेमाघरों को बंद हुए चार महीने से ज्यादा हो चुके हैं. ऐसे में सिनेमाघरों में जितना सन्नाटा पसरा है, थिएटर मालिकों का भविष्य भी उतना ही अंधकार भरा हो चला है. इंडिया टुडे देश का मिजाज सर्वेक्षण के मुताबिक, 53 फीसद यानी आधे से ज्यादा उत्तरदाताओं ने कहा कि वे सिनेमाघर खुलने के बाद भी फिल्में देखने नहीं जाएंगे. ओटीटी प्लेटफॉर्म ने फिल्मों के उत्साही दर्शकों की जरूरतें पूरी करके थिएटर मालिकों की तकलीफें और बढ़ा दी हैं. बीते कुछ महीनों में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पहली बार दिखाई गई नई फिल्मों की तो बात ही छोड़ दें. साल 2020 में बॉक्स ऑफिस का तो जैसे सफाया ही हो गया. केवल एक अजय देवगन की *तान्हाजी: द अनसंग वारियर* ने 269 करोड़ रुपए कमाए. तो अब 100 करोड़ कमाने वाली अगली फिल्म हमें कब देखने को मिलेगी?

हिट फिल्म देने के लिए जिस एक अदाकार पर भरोसा किया जा सकता है, वे हैं अक्षय कुमार. देश का मिजाज सर्वे में वे पहली बार टॉप पर आए हैं. जनवरी में हुए पिछले सर्वे में वे सलमान खान के साथ साझा रूप से शीर्ष पर थे. पिछले छह महीने में उनके दमदार प्रदर्शन का श्रेय इस तथ्य को दिया जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लगातार हो रहे खुलासों से उनका नाम बेदाग है और वे सबसे व्यस्त अभिनेता

www.readwhere.com

सवालः सिनेमा घरों के खुलने पर क्या आप फिल्म देखने वहां जाएंगे?

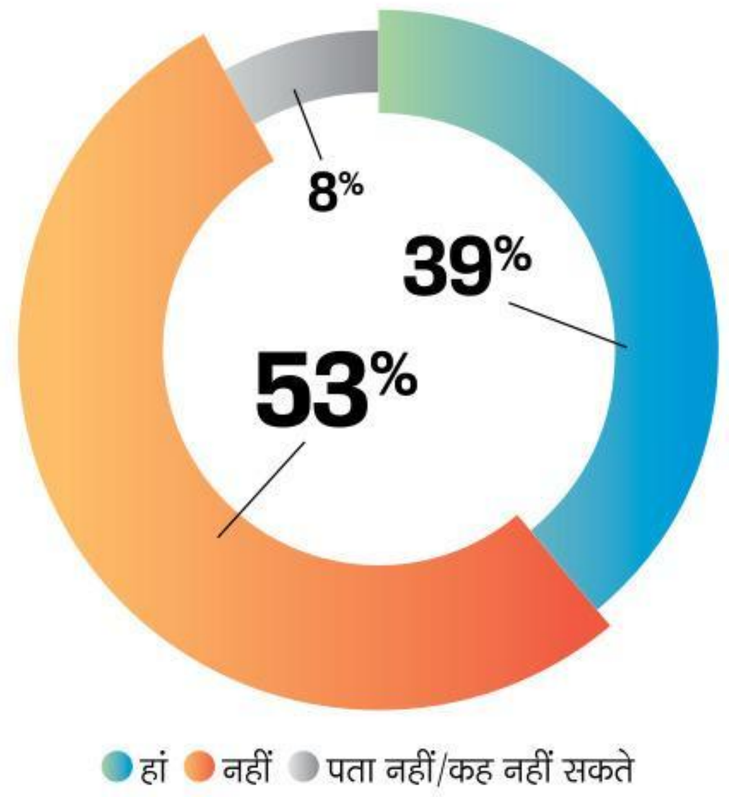

बने हुए हैं. अगस्त में वे ब्रिटेन में एक फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे और काम पर लौटने वाले पहले सितारे होंगे. उनकी फिल्म *सूर्यवंशी* के निर्माता थिएटर खुलने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं *लक्ष्मी बम* अगले महीनों में ओटीटी पर रिलीज होगी. सत्तर से ऊपर के, और घर से काम करने के बावजूद कोविड के शिकार अमिताभ बच्चन अक्षय से ज्यादा पीछे नहीं हैं.

हालांकि सर्वे का सबसे उल्लेखनीय नतीजा खान की लोकप्रियता का तेजी से लुढ़कना है. बदलाव इतना ही है कि शाहरुख अब सलमान और आमिर से आगे हैं और सर्वे में शामिल लोगों ने लॉकडाउन के दौरान उनके मीर फाउंडेशन के कई चैरिटेबल कामों को सराहा है. अक्तूबर 2018 में *ठग्स ऑफ हिंदोस्तान* के बाद आमिर की और दिसंबर 2018 में *जीरो* के बाद शाहरुख की कोई फिल्म नहीं आई. वहीं सलमान की *दबंग* की ताजातरीन पेशकश मुरीदों का दिल जीतने में नाकाम रही. देवगन, 2019 की सबसे बड़ी हिट *वॉर* में दिखाई दिए. ऋतिक रोशन, शीर्ष 10 में सबसे युवा 35 वर्षीय रणवीर सिंह एक साथ छठी पायदान पर हैं.

अभिनेत्रियों में दीपिका पादुकोण ने *छपाक* के प्रचार के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ एकजुटता दिखाकर बढ़त हासिल कर ली. *छपाक* उनके अपने प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी और इसमें उन्होंने तेजाब के हमले की शिकार लड़की का किरदार अदा किया. वे फिल्म जगत की अकेली शख्सियत भी हैं जिन्होंने अवसाद से राजपूत की जद्दोजहद की खबरें आने के बाद मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने की बात की. निर्माण (*पाताललोक, बुलबुल*) और सोशल मीडिया पर गतिविधियों को लेकर ज्यादा खबरों में रहीं अनुष्का शर्मा फिसलकर 5वीं पायदान पर पहुंच गईं, जबकि प्रियंका चोपड़ा जोनास, कैटरीना कैफ और ऐश्वर्य राय ने बेहतर प्रदर्शन किया.

उधर मनाली के अपने घर से कई मुद्दों पर वीडियो कमेंट्री दे रहीं और उसमें सबसे ज्यादा राजपूत की त्रासदी से उठती लपटों को हवा देने वालीं कंगना रनौत ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया. आलिया भट्ट की बराबरी में आईं रनौत शायद इस बात से तसल्ली हासिल करेंगी कि सर्वे में शीर्ष पांच अभिनेत्रियां उनकी तरह फिल्मी परिवारों के बाहर से आई हैं. ■

सवालः कौन है हीरोइन नंबर 1?

प्रियंका चोपड़ा जोनास
14%

कटरीना कैफ
13%

ऐश्वर्या रॉय बच्चन
10%

अनुष्का शर्मा
9%

आलिया भट्ट
6%

कंगना रनौत
6%

सोनाक्षी सिन्हा
3%

करीना कपूर खान
3%

श्रद्धा कपूर
3%

www.readwhere.com

स्मृति

रंगमंच के सुल्तान का प्रस्थान

अनुपम खेर

बंदीप सिंह

भारतीय रंगमंच के बादशाह अल्काजी साहब मेरे गुरु थे. इनसान और अदाकार के तौर पर मैंने जो कुछ सीखा, उन्हीं से सीखा. उन्हीं की अगुआई में दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) से कई शानदार अभिनेता निखरकर निकले. उनमें सुरेखा सीकरी, दिवंगत ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, रोहिणी हट्टंगड़ी, पंकज कपूर के साथ विजया मेहता और रतन थियाम सरीखे निर्देशक शामिल थे. उन्होंने हमें कविता, पेंटिंग, किताबों और संस्कृति की कद्र करना सिखाया. गधे को घोड़ा बना दिया. उन्होंने अदाकारों की जिंदगी को गरिमा दी और थिएटर के प्रति लोगों के सम्मान में इजाफा किया.

मैंने 1974 में एनएसडी के लिए आवेदन किया पर नाकाम रहा. फिर मैं चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट में साल भर के कोर्स से जुड़ गया. वहां मैं दो नाटकों में मुख्य किरदार था, जिनकी कमान अल्काजी की बेटी अमाल अल्लाना के हाथ में थी.

अल्काजी के बारे में मैंने कई किंवदंतियां सुन रखी थीं: वे बहुत सख्त हैं, करिश्माई हैं, बहुत ऊंचे दर्जे की शख्सियत हैं. अगले साल जब मैं एनएसडी पहुंचा तो पाया कि वे अपने बारे में कही-सुनी जाती इन तमाम बातों से मीलों ऊपर थे. उनसे मिलने तक मुझे पता न था कि पहेली किसे कहते हैं!

उनकी कार के हॉर्न और गलियारों में उनके चलने से हम छात्र समझ लेते थे कि आज उनका मिजाज कैसा है. उन्होंने हमें वेस्टर्न ड्रामा सिखाया. पहली क्लास में ही उन्हें आर्थर मिलर के *अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज* का ऊंचे स्वर में पाठ करते देख मैं तो हक्का-बक्का! यूनिवर्सिटी में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था पर उनकी क्लास में तो लगा कि गांव से आया हूं. अपनी कक्षाओं का वे बेसब्री से इंतजार करते थे.

उनका आचरण और व्यवहार अपने आप में पाठ की तरह थे. वे हमेशा अभिनेता में अनुशासन की जरूरत पर जोर देते थे, कहते कि कामयाबी के लिए तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा. वे हमें जॉन गिलगुड, लॉरेंस ओलिवर और मर्लन ब्रांडो के बारे में बताते. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी गजब का था. हम सब मिनी अल्काजी होना चाहते थे.

उनके साथ मेरा पहला नाटक ज्यां पॉल सार्त्र का *मेन विदाउट शैडोज* था. इससे मैंने जिंदगी के कुछ बेहतरीन सबक सीखे. वे हरेक किरदार बड़ी ही नफासत से अदा करते. चूक की कहीं रत्ती भर गुंजाइश नहीं.

एक बार मैं हेनरिक गिब्सन के *पिअर गिंट* का प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया. अल्काजी ने अल्टीमेटम दे दिया था: पूरा न किया तो स्कूल छोड़कर जा सकते हैं. मैं अपना हश्र जानता था और अपने बैच के साथियों से विदा ले रहा था. फिर भी क्लास में चला गया और अपमान सहने के लिए तैयार था. उनका मिजाज बिगड़ा हुआ था. जब एसाइनमेंट के लिए रोल कॉल की बारी आई, मैं पांचवे नंबर पर था. दूसरों ने जवाब दिया, 'आइ हैव डन, सर'. वहीं मैंने गर्दन को सही झटका देते हुए कहा, 'आइ विल डू, सर'. यह कहकर मैं बच निकला. उस रोज हर कोई मेरी फौरी सूझबूझ को मान गया.

आठ साल बाद मुझे पता चला कि वे पहलगाम में थे. मैं वहीं फिल्म की शूटिंग कर रहा था. मैंने कुछ वक्त देने की गुजारिश की और उन्होंने दोपहर के खाने पर मिलने की मेहरबानी की. लिड्डर नदी के किनारे उनके साथ बीयर की चुस्कियां लेते हुए—और मैं चाहता था कि पूरी दुनिया को इस लम्हे का तजुर्बा मिले—महज आधी बोतल गटकने के बाद हल्के नशे में मैंने तय किया कि इब्सन वाला कस्सा सुनाऊं. मगर मैं खत्म कर पाता, उससे पहले ही उन्होंने गर्दन को उसी तरह झटका देते हुए मेरे लफ्ज दोहराए, 'आइ विल डू, सर'. उन्होंने कहा, ''मैं समझ गया था पर तुम्हें स्कूल से निकालना नहीं चाहता था.''

अपने नाटक *कुछ भी हो सकता है* में मैं तीन गुरुओं—बलवंत गार्गी, अल्लाना और अल्काजी—को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. मेरी संस्था ऐक्टर प्रीपेयर्स के तीनों तलों के नाम उनके नाम पर हैं. दिल्ली के कमानी सभागार में मेरा शो देखने के बाद अल्काजी ने मुझे एक चिट्ठी लिखी. यह मेरी सबसे शानदार अमानत है. उपलब्धियों की फेहरिस्त में यह सबसे ऊपर है. भारतीय रंगमंच—इसके अभिनेता, निर्देशक, सेट डिजाइनर—हरेक चीज के लिए उनके ऋणी हैं.

सुहानी सिंह *से बातचीत के आधार पर*

www.readwhere.com

एक युगपुरुष का महाप्रयाण

जयदेव तनेजा

आधुनिक भारतीय रंगमंच और कला जगत को अपना बहुआयामी अपूर्व योगदान देने और विरल उपलब्धियों से संपन्न 95 वर्षों का भरा-पूरा रचनात्मक, सार्थक जीवन जीने के बाद किंवदंती-पुरुष इब्राहिम अल्काजी का देहावसान न तो असामयिक है और न ही आकस्मिक. फिर भी उनके प्रस्थान की खबर आने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर रंगकर्मियों और समाज के दूसरे क्षेत्र के लोगों की श्रद्धांजलियों का जैसा तांता लगा, वह सचमुच भावविभोर कर देने वाला था.

उन्हें थिएटर छोड़े कई दशक गुजर चुके थे फिर अल्काजी के नाम का वह क्या जादू है जो उनके शिष्यों के शिष्यों के भी शिष्यों को उनके नाम के साथ जोड़ने में गर्व का अनुभव करवा रहा था? मेरे जैसे एकलव्य भी न जाने कहां-कहां और कितने होंगे जिन्हें यह कहते हुए फख्र होता है कि हमने अल्काजी साहब और उनके उत्कृष्ट रंगकर्म को लंबे समय तक निकट से देखा है. इतना ही नहीं, नाटक और नाट्य प्रदर्शन को देखने की तमीज, समझ और उसे परखने की कला उन्हीं से पाई है.

यह संयोगमात्र नहीं है कि शीर्षस्थ फिल्मकार श्याम बेनेगल और कथाकार उदय प्रकाश जैसे जाने कितने प्रबुद्ध रचनाकार होंगे जिन्हें लग रहा होगा, ''अब कभी कोई दूसरा अल्काजी नहीं होगा.'' अल्काजी अपनी रंगदृष्टि, मौलिक कल्पनाशीलता, अनुशासनप्रियता, उत्कृष्टता से कम पर कभी संतुष्ट न होने की प्रवृत्ति, सिद्धांतों पर डटे रहने की संकल्प-शक्ति जैसे गुणों के बीज तो वे अपने शिष्यों में शुरू से बोते आए थे. जिन्होंने उन गुणों को खाद-पानी देकर पोसा वे आज अपने कला-माध्यम के शिखर पर हैं. उन सबमें किसी न किसी रूप में अल्काजी जीवित हैं और उन्हीं के माध्यम से संस्कार आने वाली पीढ़ियों में परंपरा बनकर हमेशा जीवित रहेंगे.

अपने मन में अल्काजी से संबद्ध बेशुमार दिलचस्प और खट्टे-मीठे यादगार संस्मरणों का भंडार रखने वाले सुविख्यात रंगकर्मी रंजीत कपूर इस मौके पर फिराक गोरखपुरी के एक शेर के बहाने उनके तमाम शिष्यों को गर्व के साथ उनकी समृद्ध विरासत का हिस्सा बनाते हुए कहते हैं कि

सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं इक बुजुर्ग
हम सबके सब फकीर उसी सिलसिले के हैं

यह भी महज संयोग नहीं कि ब.व. कारंत, बी.एम. शाह, ओम शिवपुरी, सुधा शर्मा/शिवपुरी, मोहन महर्षि, कमलाकर सोनटक्के इत्यादि के सहयात्री रहे वरिष्ठ रंगकर्मी रामगोपाल बजाज तमाम अहसमतियों और विरोध के बावजूद अपने गुरु को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं. उनका गला रुंध जाता है और आंखें डबडबा आती हैं. उद्धव के सामने कृष्ण को भेजे गोपियों के संदेश की तरह वे बिना कुछ बोले भी सब कुछ कह जाते हैं.

बाद की पीढ़ियों के पंकज कपूर, उत्तरा बावकर, रोहिणी हट्टंगड़ी, एम.के. रैना, नीलम मानसिंह चौधरी, अनुपम खेर, रघुवीर यादव, नादिरा बब्बर, राज बब्बर, अशोक सागर भगत, देवेंद्र राज अंकुर, सुशील कुमार सिंह, सबीना मेहता जेटली, डॉली अहलूवालिया, कमल तिवारी इत्यादि में से शायद ही कोई होगा जो हिंदी रंगमंच और स्कूल के उस स्वर्णकाल में अल्काजी के सख्त अनुशासन और आतंक से आहत, दुखी और परेशान न हुआ हो. और अंततः अपने प्रिय 'चचा' के उस 'दुर्व्यवहार' के असली मकसद और परोक्ष सहायता से उपकृत होकर उनका मुरीद न हो गया हो.

आज जिससे भी बात कीजिए, वह अल्काजी जैसे गुरु का शिष्य होने को

इब्राहिम अल्काजी ही थे जिन्होंने रंगमंच में कई पीढ़ियों को नाटक देखने की समझ और तमीज और समीक्षकों को उसे परखने की कला दी

अपना सौभाग्य मानता है और गर्व से स्वीकार करता है कि ''मैं आज जो कुछ भी हूं, जहां भी हूं, उन्हीं की वजह से हूं.'' अपनी तमाम आलोचनाओं और सीमाओं के बावजूद इस नाम के जादू का रहस्य क्या है? नाट्य निर्देशक के रूप में दिल्ली में कैलाश कॉलोनी के पीछे *आषाढ़ का एक दिन* जैसे संस्कृतनिष्ठ काव्यात्मक भाषा वाले मौलिक हिंदी नाटक की मुक्ताकाशी अभूतपूर्व प्रस्तुति, फिरोजशाह कोटला और पुराना किला के खंडहरों की विराट पृष्ठभूमि में अंधायुग, तुगलक और सुल्तान रजिया जैसे पौराणिक-ऐतिहासिक परिवेश, पात्रों, घटनाओं वाले बहुत बड़े फलक के नाटकों के भव्य और अत्यंत प्रभावशाली सफल प्रदर्शनों को व्यापक स्तर पर पहचान और प्रतिष्ठा का आधार माना जा सकता है.

डॉ. जयदेव तनेजा *सुपरिचित रंग समीक्षक हैं*

www.readwhere.com

लय में लगातार

रंगकर्मी-अभिनेत्री **इला अरुण** अपनी नई फिल्मों, लॉकडाउन के इस्तेमाल और आत्मकथा पर

अलामी

● *रात अकेली है* में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मां के एक रेगुलर-से रोल को आपने अपने वाचिक खासकर अवधी लहजे से खास बना दिया.

राइटर (रिमता सिंह) ने भी कहा कि इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था. जरूरी नहीं कि आप शब्दों को बदलें, पर उसकी लय पकड़ में आ जाए तब आप ऐक्टिंग नहीं करते, उसे जीते हैं. किरदार को सार्वभौमिक बनाने के लिए उसकी आत्मा को पकड़ना जरूरी है. डायरेक्टर ने भरोसा किया तो मैंने भी लिबर्टी ली और उसमें वह भाषा, वह आत्मीयता डालने की कोशिश की. नवाज के साथ *घूमकेतु* में भी हमारी केमिस्ट्री वर्कआउट हुई थी.

● नाटकों के लिए आपने इब्सन और धर्मवीर भारती को खूब पढ़ा. अभी क्या पढ़ रही हैं?

अमीश त्रिपाठी की *लीजेंड ऑफ सुहेलदेव* के सौ पन्ने पढ़े हैं. पर पढ़ने से ज्यादा देख रही हूं. पूरी *रामायण, महाभारत, कृष्णा, विष्णु पुराण.* ये ऐसे ही चल रहा है जैसे अभी त्रेता की क्लास में हूं और थोड़ी देर बाद द्वापर में (हंसते हुए). 30-38 साल पहले इनके बनते वक्त यह सोचकर नहीं जुड़ी थी कि ये कंजर्वेटिव अप्रोच के होंगे.

● कुछ लिख भी रही हैं आप.

हां, कोविड-19 के दौरान दो डायरियां लिखीं. इसमें मैं दिल खोलकर बात कर रही हूं. जब आप अकेले बैठे होते हैं तो फ्लैशबैक, फ्लैश फॉरवर्ड सबमें आते-जाते हैं. नोट्स नहीं बल्कि मुझे लगता है ये ऑटोबायोग्राफी है. श्याम बेनेगल इसके बहुत बड़े हिस्से हैं. काफी हद तक पूरी कर ली है. इट्स ऑल अबाउट माइ जर्नी.

● यानी लॉकडाउन का आपने अच्छा इस्तेमाल किया.

देखिए, दो फिल्में इस दौरान रिलीज हो गईं: *रात अकेली है* और *घूमकेतु*. हंसल मेहता की *छलांग* की टीम के लोग शायद थिएटर्स खुलने का इंतजार कर रहे हैं. तो इन फिल्मों का प्रोमोशन किया, लिखा, पढ़ा, देखा, पॉडकास्ट भी किया. कोरोना पर *सुन लो ना* वीडियो भी निकाला. तो लॉकडाउन में ठीकठाक रहा मामला बल्कि कुछ ज्यादा ही काम हो गया.

—शिवकेश

Business Today

INDIA TODAY GROUP

BUDGET
U
S
FINANCE
NEST
ANALYSIS
S
T
WISDOM
D
AWARENESS
Y

GET THE FINAL WORD

WITH INDIA'S NO. 1 BUSINESS MAGAZINE.

Access your free copy now

www.businesstoday.in/emag

www.businesstoday.in/magzter

*Read unlimited articles till further notice.

www.readwhere.com

ZEE LABORATORIES

करोड़ो लोगो का आज़माया

झुर्रियां | काले घेरे | छाईंया

MYFAIR

रूप संवारे, त्वचा निखारे

- क्रीम
- साबुन
- फेस वाश
- सन स्क्रीन

सम्पूर्ण कॉस्मेटिक रेंज
हर प्रमुख दवा विक्रेता के यहां उपलब्ध
9896134500

A Product of
ZEE LABORATORIES LTD.

Online Shopping:
www.myfair.in

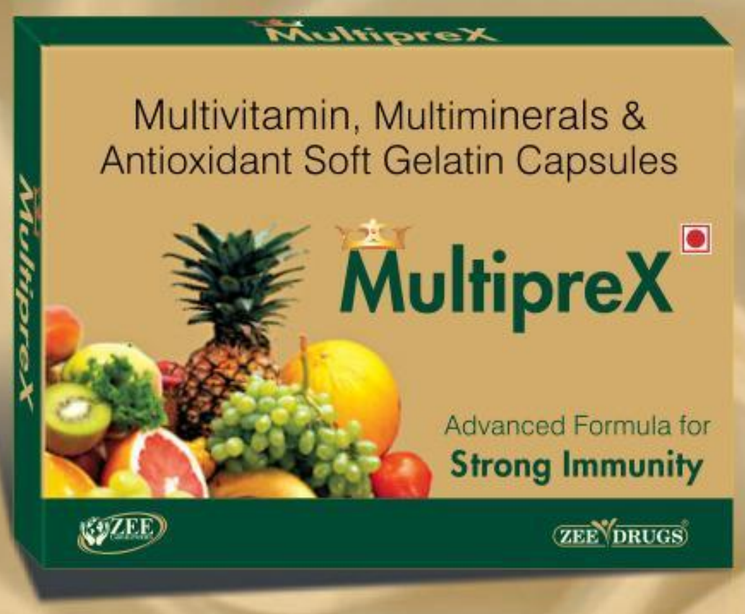

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए

MultipreX™

कैप्सूल, सिरप, ओरल ड्राप्स, पाउडर

Natural Immunity Booster

प्रतिरक्षा में सुधार, विटामिन और मिनरल की कमी को पूरा कर रोगों से बचाए

रोजाना सेवन करे
9896134500
हर प्रमुख दवा विक्रेता के यहां उपलब्ध